



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 12—मार्च 18, 2016 (फाल्गुन 22, 1937)

No. 11]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 12—MARCH 18, 2016 (PHALGUNA 22, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 253

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 213

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 607

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 335

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 61

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 179

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक *

*अंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

Page No.		Page No.	
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	253	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	213	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	607	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	335
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	61
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	179
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 फरवरी 2016

संकल्प

सं. 06/19/2013-टफ्स-संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के लिए वित्तीय और प्रचलनात्मक मानदंड और क्रियान्वयन वाले दिशानिर्देश को इस मंत्रालय के दिनांक 04/10/2013 के समसंख्यक संकल्प के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। उक्त दिशानिर्देश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 17.09.2014 से 12.01.2016 तक लंबित यूआईडी आवेदनों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

1. वित्तीय मानदंड

1.1 बजट आबंटन: संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) जिसे दिनांक 17.09.2014 से 12.01.2016 की आधी रात तक आईटीयूएफएस सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया था, के अंतर्गत लंबित विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) आवेदनों के लिए इस योजना के अंतर्गत बजट आबंटन उक्त आबंटन के 1 प्रतिशत की दर से प्रशासनिक लागत सहित 4005 करोड़ रुपए है।

1.2 तत्कालीन संशोधित टीयूएफएस (सूची-I एवं सूची-II), आरटीयूएफएस और आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 तक स्वीकृत मामलों की प्रतिबद्ध देयताओं के विरुद्ध दावों पर विचार करने के लिए 8666 करोड़ रुपए की राशि भी निर्दिष्ट की गई है। तत्कालीन संशोधित टीयूएफएस (सूची-I एवं सूची-II), आरटीयूएफएस के अंतर्गत स्वीकृत मामलों की प्रतिबद्ध देयताओं का मिलान किया जा रहा है।

1.3 यह दोहराया जाता है कि स्टैंड अलोन स्पिनिंग सेक्टर पर कुल सब्सिडी प्रवाह 26% से अधिक नहीं होगा।

2. प्रचालनशील मानदंड

2.1 एक आईटीयूएफएस सॉफ्टवेयर की स्थापना की गई है। ऋणदाता एजेंसियों और व्यक्तिगत आवेदकों ने आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत यूआईडी जारी करने के लिए दिनांक 17.9.2014 से 12.1.2016 की आधी रात तक आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत स्वीकृत आवधिक ऋण का व्यौरा अपलोड किया था।

2.2 यूआईडी संख्या जारी करने के लिए ऐसे आवेदनों के संबंध में उसी क्रम के अनुसार जिसमें वे इस योजना के अंतर्गत पात्रता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर वस्त्र आयुक्त का कार्यालय में केन्द्रीय सर्वर पर आईटीयूएफएस सॉफ्टवेयर में प्राप्त होते हैं, पहले आओ-पहले पाओं के आधार पर विचार किया जाएगा।

2.3 आरआरटीयूएफएस पर संकल्प के पैरा V-1(vi) के संदर्भ में पहले से अपलोडिड और दिनांक 17.9.2014 से 12.1.2016 की आधी रात तक यूआईडी आवेदकों के संबंध में क्षेत्र और ऋण राशि में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.4 यूआईडी संख्या प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई सूचना/दस्तावेजों के सही होने की जिम्मेवारी संबंधित आवेदक तथा ऋणदाता एजेंसी (यों) की होगी।

2.5 इकाई द्वारा सभी मशीनरी की स्थापना

2.5.1 आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंचमार्क वाली सभी पात्र मशीनरी के विनिर्माण का वर्ष, विनिर्माता का नाम और क्रमांक संख्या मशीन (नों) पर स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की गई है। कुल मिलाकर, एक 'मशीन पहचान कोड' (एमआईसी) वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटित की जाएगी जो इस योजना के अंतर्गत खरीदी गई प्रत्येक मशीन के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। यह एमआईसी मशीनरी पर अनिवार्य रूप से उत्कीर्ण किया जाएगा और समय-समय पर प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान सत्यापित की जाएगी।

2.5.2 एमआईसी का निर्णय देश-कोड, राज्य/प्रांत कोड, मशीन विनिर्माता कोड (जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है), मशीन विनिर्माता के अधिकृत एजेंट कोड, वाणिज्यिक बीजक संख्या, आयात पत्र संख्या और लदान बिल संख्या (केवल आयातिक मशीनरी के मामले में), मशीन क्रमांक संख्या आदि के आधार पर किया जाएगा।

3. यूआईडी रद्द करने का प्रावधान

3.1 इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए यूआईडी उन मामलों में रद्द कर दिए जाएंगे जहां:

3.1.1 आवेदक किसी कारण से इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने का निर्णय नहीं लेता है जिसके लिए उसने आईटीयूएफएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके संबंधित ऋणदाता एजेंसी के माध्यम से जारी की गई यूआईडी को रद्द करने के लिए अनुरोध अपलोड किया है। यह अनुरोध निर्धारित प्रपत्र-1 में किया जाना चाहिए।

3.1.2 किसी स्तर पर आवेदन रद्द कर दिए जाने पर यूआईडी स्वतः निरस्त हो जाएगा।

4. दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा

इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही सब्सिडी के दुरुपयोग से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा की व्यवस्था की गई है:

(क) यह अनिवार्य बनाया जाए कि सभी पात्र मशीनरी का नाम, निर्माण का वर्ष, विनिर्माता का नाम और क्रम संख्या तथा वस्त्र आयुक्त द्वारा आबंटित एमआईसी संख्या मशीन पर स्पष्ट रूप से उत्कीर्ण किया जाना चाहिए।

(ख) वस्त्र आयुक्त द्वारा गठित किए जाने वाले एक संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) प्रतिपूर्ति के लिए दावों की जांच करते समय इस योजना के अंतर्गत अलग किए गए नमूना मामलों के रूप में इकाई द्वारा स्थापित की गई मशीनरी/बनाई गई परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करेगा।

5. शिकायत निवारण तंत्र

5.1 इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण, वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक शिकायत समिति जिसमें वस्त्र मंत्रालय, ऋणदाता एजेंसियों और औद्योगिक संघों आदि के प्रतिनिधि होते हैं, द्वारा किया जाएगा।

5.2 नीतिगत मामले और तत्संबंधी टिप्पणी से संबंधित शिकायतों को सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जो इसका निवारण करेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को प्रेषित की जाएं।

पुष्पा सुब्रह्मण्यम
अपर सचिव

प्रपत्र-1

भाग I (लाभग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

संबंधित ऋणदाता एजेंसी के माध्यम से एटीयूएफएस के अंतर्गत जारी यूआईडी रद्द करना

नोट : दूसरी ऋण प्रदाता एजेंसी में परिवर्तन के समय इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई ऋणप्रदाता एजेंसी एटीयूएफएस के अंतर्गत शामिल है।

1.	यूआईडी संख्या	स्वतः तैयार की गई
2.	यूआईडी अनुमोदन की तारीख	स्वतः तैयार की गई
3.	इकाई का नाम	स्वतः तैयार की गई
4.	इकाई का पता	स्वतः तैयार की गई
5.	इकाई की ई-मेल आईडी	स्वतः तैयार की गई
6.	पैन संख्या	स्वतः तैयार की गई
7.	आवधिक ऋण स्वीकृति की तारीख	स्वतः तैयार की गई

8.	परियोजना लागत रुपए में	स्वतः तैयार की गई
9.	दावा किया गया क्षेत्र	स्वतः तैयार की गई
10.	ऋणदाता एजेंसी का नाम	स्वतः तैयार की गई
11.	ऋणदाता एजेंसी का पता	स्वतः तैयार की गई
12.	ऋणदाता एजेंसी का शाखा कोड	स्वतः तैयार की गई
13.	स्वीकृत आवधिक ऋण रुपए में	स्वतः तैयार की गई
14.	प्रमोटर का अंशदान रुपए में	स्वतः तैयार की गई
15.	आवधिक ऋण का खाता संख्या	स्वतः तैयार की गई
16.	यूआईडी के अनुसार पूर्व प्राधिकृत कुल सब्सिडी मूल्य रुपए में	स्वतः तैयार की गई
17.	जारी की गई यूआईडी रद्द किए जाने का कारण	

प्रमाणित किया जाता है कि:

इस प्रपत्र में दी गई सूचना सही हैं एवं सत्य हैं और मैं/हम _____ वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा जारी की गई उक्त यूआईडी को निरस्त करने का अनुरोध करते हैं। इसके अलावा मैं/हम वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा जारी की गई उपरोक्त यूआईडी के संबंध में कभी किसी सब्सिडी का पूर्ण अथवा आंशिक दावा नहीं करेंगे।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

दिनांक

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम एवं पदनाम)

नोट: कृपया प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर के साथ कंपनी/इकाई की सील/रबर स्टैंप लगाएं।

भाग ॥ (ऋणदाता द्वारा जारी की जाए)

संबंधित ऋणदाता एजेंसी द्वारा एटीयूएफएस के अंतर्गत जारी यूआईडी रद्द करना

प्रमाणित किया जाता है कि :

आवेदक द्वारा प्रपत्र-। के भाग-। में दी गई सूचना हमारे बैंक के पास उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर सही पाई गई है।

प्रपत्र-8 के भाग-। में आवेदक इकाई द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों से, मैं/हम _____ एतद्वारा आवेदक इकाई को वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा जारी यूआईडी संख्या रद्द करने की सिफारिश करते हैं।

संकल्प

सं.06/15/2015-टप्स—संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 13/01/2016 के समसंख्यक संकल्प के माध्यम से अधिसूचित की गयी है। उक्त संकल्प के साथ एटीयूएफएस के दिशानिर्देश अर्थात दिनांक 17.09.2014 से 12.01.2016 तक इसके क्रियान्वयन अवधि के दौरान एटीयूएफएस के वित्तीय और प्रचालनात्मक मानदंड और क्रियान्वयन तंत्र नीचे दिए गए हैं:-

1. उद्देश्य:

1.1 देश में व्यवसाय को आसान बनाने और विनिर्माण में ‘जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट’ के साथ “मेक इन इंडिया” के माध्यम से रोजगार का सृजन करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के इष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सरकार संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के अंतर्गत पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान करेगी।

1.2 यह योजना वस्त्र उद्योग में आयात स्थानापन्न के साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार, निर्यात को बढ़ावा देने को सुविधाजनक बनाएगी। यह वस्त्र मशीनरी (बैंचमार्क प्रौद्योगिकी वाली) के निर्माण में निवेश को अप्रत्यक्ष रूप से भी बढ़ावा देगी।

2. योजना की परिभाषाएं

2.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन का तात्पर्य वस्त्र उद्योग अत्याधुनिक अथवा लगभग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करना है। मशीनरी के प्रौद्योगिकी के स्तरों को तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटरिंग समिति (टीएमसी) द्वारा वार्षिक आधार पर अध्ययन

और निर्दिष्ट किया जाएगा। निर्दिष्ट सीमा से कम प्रौद्योगिकी स्तर वाली मशीनरी को एटीयूएफएस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण की अनुमति नहीं है।

2.2 पूँजी निवेश सब्सिडी: (सीआईएस) का तात्पर्य इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए बेन्चमार्क वाली नई मशीनरी की खरीद के लिए “सावधि पूँजी निवेश” में किए गए निवेश पर क्षेत्र की निर्धारित दर पर सब्सिडी है जिसका निर्धारण कंपनी द्वारा इसकी स्थापना के पश्चात बैन्च मार्क मशीनरी की प्राथमिक लागत पर किया जाएगा।

2.3 गार्मेंट/अपैरल/मेड-अप्स: का तात्पर्य पहनने योग्य अथवा गैर-पहनने योग्य सिलेंसिलाए फैब्रिक से है जिसके कम से कम दो किनारों को सिलाई मशीन का प्रयोग करके सिला जाता है।

2.4 तकनीकी वस्त्र: का तात्पर्य सजावटी-अथवा साज-सज्जा की अपेक्षा उनके तकनीकी निष्पादन और कार्यकारी परिस्मृतियों के लिए प्राथमिक रूप से प्रयोग की गई सामग्रियों और उत्पाद हैं जहां कार्य प्राथमिक मानदंड हैं। तकनीकी वस्त्र में आटोमोटिव अनुप्रयोग, मेडिकल टेक्सटाइल, जियो-टेक्सटाइल, एग्रो-टेक्सटाइल, प्रोटेक्टिव क्लोटिंग, पार्क टेक आदि शामिल हैं।

2.5 एटीयूएफएस के लाभ योजना के अंतर्गत बेन्चमार्क मशीनरी के लिए उपलब्ध हैं जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:-

क) वीविंग, वीविंग प्रैपरेटरी और निटिंग

ख) फाइबर की प्रोसेसिंग, यार्न, फैब्रिक्स, गार्मेंट, और मेड-अप्स।

ग) तकनीकी वस्त्र

घ) गार्मेंट/मेड-अप्स निर्माण

ड.) हथकरघा क्षेत्र

च) रेशम क्षेत्र

छ) पटसन क्षेत्र

3. पूँजी निवेश सब्सिडी प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड

3.1 एटीयूएफएस के अंतर्गत निर्दिष्ट क्षेत्रों में पात्र बैंचमार्क वाली मशीनरी पर निवेश के लिए पूँजी निवेश सब्सिडी उपलब्ध होगी। बैंचमार्क वाली पात्र मशीनरी को तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटरिंग समिति (टीएएमसी) द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को अध्ययन और निर्दिष्ट किया जाएगा। वस्त्र आयुक्त टीएएमसी के अनुमोदन के पश्चात पात्र मशीनरी की सूची को अधिसूचित करेंगे। इस योजना के निर्दिष्ट सीमा से कम प्रौद्योगिकी स्तर वाली मशीनरी सब्सिडी के लाभ के लिए पात्र नहीं होगी। सभी पात्र मशीनरी के निर्माण और वर्ष या तो मशीन पर अथवा मशीन पर संलग्न नाम पट्ट पर स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

3.2 मशीन निर्माता अथवा उनके प्राधिकृत एजेंटों से सीधे खरीदी गई मशीन को इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए विचार किया जाएगा। तथापि, यह लाभ पैरा 4.2.6 के अनुसार खरीदी गई परिधान मशीनरी के लिए भी उपलब्ध होगा।

4 पात्रता की सामान्य शर्तें

4.1 इकाइयों के प्रकार:

4.1.1 कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी (संशोधन), 2015 के अंतर्गत अथवा कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास उक्त अधिनियम के संशोधन में किए गए प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत कंपनियां/इकाइयां और उन एमएसएमई इकाइयों, जिन्हें एमएसएमई मंत्रालय के निर्देशों द्वारा संचालित किया जाएगा अथवा वे इकाइयां जो पंजीकरण के कार्यकलाप को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हुए संबंधित राज्य सरकार के निदेशालयों के साथ पंजीकृत हैं, को छोड़कर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के पास औद्योगिक उद्यम जापन (आईडृएम) की पावती है, ही इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी (गैर-एमएसएमई इकाइयों के मामले में)।

4.1.2 मौजूदा इकाइयां और नई इकाइयां किसी व्यक्तिगत कंपनी के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर सब्सिडी के लिए पात्र होगी। तथापि, यदि कंपनी ने आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त कर लिया है तो वह किसी व्यक्तिगत कंपनी के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर शेष राशि की ही पात्र होगी,

4.1.3 हथकरघा, रेशम, पटसन इकाइयों सहित वस्त्र इकाइयां इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

4.2 पात्र वस्त्र मशीनरी के प्रकार:

4.2.1 एटीयूएफएस योजना के अंतर्गत केवल विनिर्माता अथवा उनके प्राधिकृत एजेंटों के नाम दर्शाते हुए निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए नई बैंच मार्क वाली मशीनरी को अंतिम रूप दिया जाएगा और तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटरिंग समिति (टीएएमसी) की सिफारिश पर

वस्त्र आयुक्त द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को अधिसूचित मशीनरी को अनुमति दी जाएगी। वस्त्र आयुक्त क्रमशः पटसन, हथकरघा और रेशम क्षेत्र के लिए पटसन आयुक्त, विकास आयुक्त (हथकरघा) और सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड से पात्र मशीनरी की सूची प्राप्त करेगा।

4.2.2 एटीयूएफएस के अंतर्गत पात्र मशीनरी की लागत का 20% के मूल्य तक मशीन के साथ प्राप्त उपस्कर/संलग्नक/नमूना मशीनों/कलपुर्जे भी पात्र होंगे।

4.2.3 एक क्षेत्र के लिए पात्र मशीनरी अन्य क्षेत्रों/कार्यकलापों के लिए भी पात्र है बशर्ते इसकी पात्रता किसी विशिष्ट क्षेत्र/कार्यकलाप के लिए सीमित न हो।

4.2.4 वस्त्र आयुक्त द्वारा उस वर्ष 1 अप्रैल को अधिसूचित नहीं की गई कोई अन्य मशीनरी की पात्रता को भी, यदि आवश्यक समझा जाएगा तो टीएएमसी की सिफारिश पर बाद में शामिल किया जा सकता है।

4.2.5 विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) जारी किए जाने को इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र बेन्चमार्क मशीनरी की सूची से संबद्ध किया जाएगा जिन्हें बजटीय प्रावधान और देयताओं के आधार पर और टीएएमसी की सिफारिश पर प्रत्येक वर्ष संशोधित किया जाएगा।

4.2.6 मशीन विनिर्माताओं अथवा उनके प्राधिकृत एजेंटों से सीधे खरीदी गयी मशीनरी (आयातित और स्वदेशी) पर इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए विचार किया जाएगा। तथापि, यह लाभ देश के भीतर स्थित प्राधिकृत स्टाकिस्ट/कस्टम वेयर हाऊस से खरीदी गई परिधान/अपैरल/मेड-अप्स विनिर्माण के लिए अपेक्षित नई आयातित स्टिचिंग मशीनों के लिए भी उपलब्ध होगा बशर्ते कि यह खरीद उस व्यक्ति से की गई हो जिसने उसे मशीन विनिर्माताओं अथवा उनके प्राधिकृत एजेंटों से सीधे खरीदा हो ऐसी मशीनरी इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होगी। ऐसी मशीन जिसे एक बार भी उपयोग किया गया हो और/अथवा परीक्षण के लिए भी उपयोग किया गया हो, उसे इस योजना के अंतर्गत कदापि अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.2.7 खरीद की तारीख से तात्पर्य स्वदेशी तथा आयातित मशीनों दोनों के मामले में वाणिज्यिक बीजक की तारीख है।

4.2.8 वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटित मशीन पहचान कोड (एमआईसी) को संबंधित मशीन(ों) पर स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिस पर इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी का दावा किया जाता है।

4.2.9 सहायतार्थ पात्रता मानदण्ड:

(i) ऊपर पैरा 4.1.1 में यथा निर्दिष्ट कंपनियां ही इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी।

(ii) वस्त्र मद(दों) के रूप में निर्मित उत्पाद का संकेत देने वाले संबंधित प्राधिकरण के साथ पंजीकरण एक पूर्व-आवश्यकता है जिसे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) को मशीनरी का सत्यापन करते समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.3 अन्य पात्र निवेश

निर्दिष्ट मशीनरी के अलावा किया गया निवेश इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

4.4 पात्र सब्सिडी के लिए मानक:

4.4.1 एटीयूएफएस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्तिगत इकाई को पात्र निवेश पर, नीचे निर्दिष्ट दरों तथा समग्र सब्सिडी की सीमा के अनुसार पूँजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान की जाएगी:-

क्र.सं.	क्षेत्र	पूँजी निवेश सब्सिडी की दरें (सीआईएस)	अलग-अलग इकाई के अनुसार सीआईएस
1.	परिधान, तकनीकी वस्त्र	पात्र मशीनों पर 15%	30 करोड़ रु.*
2.	एकदम नए शटल-रहित करघों के लिए बुनाई (प्रीपेरेटरी बुनाई एवं निटिंग सहित), प्रसंकरण, पटसन, रेशम तथा हथकरघा	पात्र मशीनों पर 10%	20 करोड़ रु.*
3(क)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्रों-यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूँजी निवेश पात्र परियोजना लागत से 50% अधिक है।	पात्र मशीनों पर 15%	30 करोड़ रु.*
3(ख)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्रों-यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूँजी निवेश 50% से कम है तो सब्सिडी सीमा 20 करोड़ रु. होगी।	पात्र मशीनों पर 10%	20 करोड़ रु.*

*यदि आवेदक ने आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत पहले ही सब्सिडी प्राप्त कर ली है तो वह एक व्यक्तिगत कंपनी के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर शेष राशि ही प्रदान करने का पात्र होगा। एटीयूएफएस के अंतर्गत किसी व्यक्तिगत कंपनी द्वारा समग्र निवेश की अधिकतम सब्सिडी सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए ऊपर निर्दिष्ट किए अनुसार सीमित होगी।

4.5 सब्सिडी के मानक:

- 4.5.1 एटीयूएफएस के अंतर्गत पूँजी निवेश सब्सिडी उस निवेश पर, सन्तोषजनक स्थापना/शुरूआत तथा उत्पादन आरंभ होने के पश्चात ही, एकमुश्त पूरी रिलीज की जाएगी।
- 4.5.2 इस योजना के अंतर्गत लाभ उपलब्ध होंगे यदि पात्र मशीनरी अधिसूचित ऋणदाता एजेंसी से आवधिक ऋण लेकर खरीदी गयी है।
- 4.5.3 संस्थागत वित्तपोषण के साथ किए गए निवेश के मामले में ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी। क्रेता क्रेडिट, यूज़ेंस क्रेडिट और विक्रेता क्रेडिट लेकर किया गया निवेश इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा जब तक कि सब्सिडी का दावा करने से पूर्व लाभग्राही द्वारा समग्र राशि का भुगतान न कर दिया गया हो अथवा इस योजना में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा सत्यापन के समय उसका ठोस दस्तावेजी प्रमाण न प्रस्तुत कर दिया गया हो।

4.6 अंतिम तिथि:

- 4.6.1 आवधिक ऋण की स्वीकृति की तारीख ऋण प्रदान करने वाली एजेंसी के पत्र की तारीख होगी जिसके माध्यम से आवधिक ऋण की स्वीकृति की सूचना उद्यमी को दी गयी है।
- 4.6.2 यदि ऋणदाता एजेंसी द्वारा आवधिक ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है और उसके बाद ऋण दाता एजेंसी ने आवधिक ऋण को अन्य ऋणदाता एजेंसी(यों) को वितरित/डाउन सेल कर दिया है अथवा कंसोर्टियम फाइनेन्स के अंतर्गत आवधिक ऋण स्वीकृत कर दिया है, आवधिक ऋण स्वीकृत की तारीख निम्नानुसार होगी:
 - (i) आवधिक ऋण को डाउन-सेल करने के मामले में प्रथम ऋण दाता, जिसने आरम्भ में आवधिक ऋण स्वीकृत किया है, द्वारा आवधिक ऋण की स्वीकृति की तारीख संगत तारीख होगी और वही ऋण प्रदाता एजेंसी के पत्र की तारीख होगी जिसके माध्यम से आवधिक ऋण की स्वीकृत की तारीख की सूचना कंपनी को दी गयी है।
 - (ii) कंसोर्टियम फाइनेन्स के मामले में, कंसोर्टियम का प्रमुख इस योजना के अंतर्गत पात्र आवधिक ऋण की राशि सहित स्वयं तथा कंसोर्टियम के अन्य सदस्यों के लिए इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पात्रता का मूल्यांकन करेगी। तथापि, इस मामले में आवधिक ऋण की स्वीकृति की तारीख कंसोर्टियम में पिछले ऋणदाता एजेंसी जो आवधिक ऋण स्वीकृत करता है, के पत्र की तारीख होगी, जिसके माध्यम से कंपनी को स्वीकृति की सूचना दी गयी है।
- 4.6.3 इस योजना के अंतर्गत परियोजना के लिए किसी मल्टीपल फाइनेन्स की अनुमति नहीं है। लाभग्राही को अनुबंध 'क' के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में इस संबंध में वर्चन पत्र देना होगा।
- 4.6.4 उपर्युक्त प्रत्येक मामले में यथानुपात आधार पर प्रत्येक ऋणदाता एजेंसी के ऋण वाले/आवेदक के खाते में सीआईएस का संवितरण किया जाएगा।
- 4.6.5 यदि जहां आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत ऋण दाता एजेंसियों द्वारा आवधिक ऋण स्वीकृत किया गया है किन्तु आवधिक ऋण की स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है और उन मामलों में जहां यूआईडी आवेदन दिनांक 12.01.2016 की आधी रात तक आई-एटीयूएफएस का प्रयोग करके वस्त्र आयुक्त के सर्वर में अभी अपलोड नहीं किया गया है, ऐसे मामले दिनांक 13.01.2016 के संकल्प सं. 6/5/2015-टफस के माध्यम से अधिसूचित एटीयूएफएस योजना के अनुसार ही लाभ की पात्र होगी। ऐसे पात्र मामलों के आवेदकों को एटीयूएफ योजना (ब्यौरा नीचे दिया गया है) के निर्धारित फार्मेट के अनुसार आई-एटीयूएफएस साफ्टवेयर का प्रयोग करके वस्त्र आयुक्त के सर्वर में यूआईडी आवेदन अपलोड करने की आवश्यकता होगी। इन आवेदनों को दिनांक 13.01.2016 के संकल्प सं.6/5/2015-टफस के जारी होने की तारीख से छः महीने के भीतर अर्थात दिनांक 12.07.2016 तक, पहले आओ - पहले पाओ आधार पर और बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता की शर्त पर विचार किया जाएगा।

4.7 ऋण की स्वीकृति से पहले निवेश का कवरेज:

आवधिक ऋण की स्वीकृति की तारीख से पूर्व यूनिट द्वारा मशीन की लागत के लिए मार्जिन मनी तक अग्रिम/टोकन भुगतान किया जा सकता है। तथापि, आवधिक ऋण की स्वीकृति की तारीख को अथवा उसके बाद खरीदी गयी मशीनें, अन्य नियम एवं शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी।

4.8 अन्य योजनाओं के लाभ:

वस्त्र इकाइयों को, जब तक विशेष रूप से मना न किया जाए, इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ के अलावा, राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की अनुमति है।

4.9 इकाई के प्रबंधन का विलय/अधिकार में लेना:

कंपनियों/इकाइयों के विलय अथवा किसी दूसरी इकाई/कंपनी द्वारा इकाईयों/कंपनीयों को अधिकार में लेने के मामले में नई इकाई/कंपनी इस योजना के अंतर्गत इस शर्त के अधीन सब्सिडी की शेष राशि, यदि कोई बकाया हो, प्राप्त करने की हकदार होगी, कि विलय/अधिकार में लेने की अनुमति या तो कंपनियों के पंजीयक द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा दी गई है और नई इकाई/कंपनी ने विलय/अधिकार में ली गयी इकाई/कंपनी की सभी देयताओं और परिसम्पत्तियों को अधिकार में ले लिया है और संबंधित बैंक ने भी मौजूदा कंपनी/इकाई जिसने उसे अधिकार में लिया है, के नाम में पूर्ववर्ती कंपनी/इकाई का आवधिक ऋण भी हस्तान्तरित कर दिया है। तथापि, ऐसे मामलों में नई इकाई/कंपनी आई-एटीयूएफएस साफ्टवेयर के माध्यम से विलय की गयी कंपनी/इकाई का प्रोफाइल परिवर्तित करने के लिए सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अनुबंध 'ख' के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वस्त्र आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

5. वित्तीय मानदंड:

5.1 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के अंतर्गत नीचे दी गयी नियम एवं शर्तों के अध्यधीन ऋण प्रदान किए जाएंगे:

5.1.1. प्रतिशूलि, ऋण इक्विटी अनुपात, पहले वर्ष की लाभ की स्थिति, निवल मूल्य आदि जैसे वित्तीय मानदंड ऋणदाता एजेंसी के मौजूदा मानदंडों के अनुसार होंगे।

5.1.2. चूंकि यह योजना क्रेडिट लिंक है, उद्यमी को इस योजना के अंतर्गत पात्र बनने के लिए कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 50% के रूप में मर्शीनरी के आवधिक ऋण घटक को बनाया रखना अपेक्षित होगा।

5.1.3. इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक, राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी), राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसी), अधिसूचित बैंक और आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी वित्त पोषण के लिए पात्र हैं।

5.1.4. दिनांक 04.10.2013 के संकल्प सं 6/19/2013-टफ्स के अनुसार आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत शामिल ऋण दाता एजेंसियां स्वतः इस योजना के अंतर्गत शामिल हो जाएंगी और नए ऋण दाता एजेंसीयों को अनुबंध 'ग' के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आई-एटीयूएफएस साफ्टवेयर के माध्यम से वस्त्र आयुक्त, मुंबई को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा ताकि उस एटीयूएफएस के अंतर्गत ऋण दाता एजेंसी को अधिसूचित किया जा सके।

5.1.5 विदेशी मुद्रा ऋण: इस योजना के अंतर्गत लाभ हेतु इंडियन बैंक की विदेशी शाखा/विदेशी बैंक वाली भारतीय शाखा से विदेशी मुद्रा ऋण की सुविधा के लिए पात्र होंगे। तथापि, ऋण खाते का संचालन भारतीय शाखा से किया जाना चाहिए ताकि भारतीय शाखा में आवेदक के ऋण खाते में भारतीय रूपए में सब्सिडी की राशि स्थानांतरित करना संभव हो सके।

5.2 योजना के अंतर्गत आवधिक ऋण की अवधि

5.2.1 योजना के लाभ की सुविधा के लिए स्वीकृत किए गए आवधिक ऋण की अवधि एसएसआई इकाइयों के लिए मोरेटोरियम अवधि सहित 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अन्य श्रेणियों के लिए 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

5.2.2 सब्सिडी के गलत उपयोग को रोकने के लिए आशा की जाती है कि इकाई को कम से कम ऊपर निर्दिष्ट आवधिक ऋण की अवधि के लिए कार्य करना चाहिए।

5.3 संघ (कंसोर्टियम) वित्त के मामले में, योजना के अंतर्गत अवधि ऋण की पात्र राशि सहित संघ (कंसोर्टियम) के प्रमुख और अन्य सदस्यों के लिए भी परियोजना की पात्रता का निर्धारण करेगा।

5.4 एक ऋणदाता एजेंसी से दूसरी ऋणदाता एजेंसी को एटीयूएफएस ऋण का स्थानांतरण

एक ऋण प्रदाता एजेंसी से दूसरी ऋण प्रदाता एजेंसी को टीयूएफएस ऋण का स्थानांतरण इस योजना के अंतर्गत ऋण खाते की बकाया मूलधन राशि केवल एक बार एक ऋण प्रदाता एजेंसी से दूसरी ऋण प्रदाता एजेंसी को स्थानांतरित किया जा सकता है बशर्ते कि पोर्टफोलियो (अर्थात शेष मूलधन राशि) अपरिवर्तित रहती है।

5.5 रूपए आवधिक ऋण को विदेशी मुद्रा ऋण तथा विलोमतः परिवर्तन:

रूपया आवधिक ऋण (आरटीएल) को विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) तथा विलोमतः परिवर्तन की अनुमति है।

6. क्रियान्वयन तंत्र:

6.1 योजना का क्रियान्वयन वस्त्र आयुक्त द्वारा अपने क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के राज्य/क्षेत्रीय स्तर के कार्यालय प्रत्येक राज्य में स्थापित किए गए हैं जो प्राथमिकता पर एटीयूएफएस का क्रियान्वयन एवं मॉनीटर करेंगे। योजना का क्रियान्वयन 5 चरण प्रक्रियाओं में किया जाएगा:

चरण 1: कंपनी/इकाई/आवेदक द्वारा राज्य/वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय जो ऋण दाता एजेंसी द्वारा आवधिक ऋण की स्वीकृती प्रदान करेगा, को प्रस्तुत किए गए आवेदन की प्रति सहित आवधिक ऋण का आवेदन प्रस्तुत करना।

चरण 2: योजना के अंतर्गत सब्सिडी के प्राधिकरण-पूर्व के लिए आई-टप्स सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हुए ऋण प्रदाता एजेंसी के माध्यम से कंपनी/इकाई/आवेदक द्वारा वस्त्र आयुक्त को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) के लिए आवेदन और यूआईडी को जारी करना।

चरण 3: मशीनरी की स्थापना।

चरण 4: इकाई द्वारा वस्त्र आयुक्त को सब्सिडी दावे की ऑनलाइन प्रस्तुति और वस्त्र आयुक्त द्वारा दावों को वस्त्र मंत्रालय को अव्यैशित करना।

चरण 5: आवेदक के खाते में वस्त्र मंत्रालय द्वारा पात्र सब्सिडी को जारी करना।

6.2 क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग तंत्र की प्रक्रिया संलग्न अनुबंध 'घ' में दी गई है।

6.3 चरण-वार प्रक्रिया का विस्तृत व्योरा निम्नानुसार है:

6.3.1 चरण 1: कंपनी/इकाई/आवेदक द्वारा आवधिक ऋण आवेदन को प्रस्तुत करना और ऋण प्रदाता एजेंसी द्वारा आवधिक ऋण की स्वीकृति:

(I) इस योजना के अंतर्गत आवेदक/सहायता मांगने वाली इकाई इस योजना के अंतर्गत आवधिक ऋण की स्वीकृति के लिए ऋणदाता एजेंसी से संपर्क करेगी। आवेदक मशीनरी के आवधिक ऋण के घटक को कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 50% रखेगा ताकि वह इस योजना के अंतर्गत पात्र हो जाए।

(II) इस योजना के अंतर्गत सहायता मांगने वाला आवेदक/इकाई कंपनी का पैन नम्बर और कंपनी पंजीकरण संख्या आदि और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जैसे व्यौरे के साथ आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके प्रपत्र-1 (भाग-1) में स्वतः व्यौरे भरेगा के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा। आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उक्त व्यौरों को प्रस्तुत करने के पश्चात वस्त्र आयुक्त द्वारा एक एटीयूएफएस संदर्भ संख्या जारी की जाएगी जो आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक प्रणाली जनित संख्या होगी। यदि आवेदक को आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के प्रयोग पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो आवेदक निर्धारित किए गए प्रपत्र में आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विवरण अपलोड करने में वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय की सहायता ले सकता है और वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय आवेदक को हैंड होल्डिंग सेवाओं के भाग के रूप में अपना आवेदन अपलोड करने में उसकी सहायता करेगा।

(III) ऋणदाता एजेंसी आवेदक को आवधिक ऋण की स्वीकृति की सूचना देगी। आवधिक ऋण की स्वीकृति की तिथि ऋणदाता एजेंसी के पत्र की तिथि होगी जिसके द्वारा आवधिक ऋण की स्वीकृति से उद्यमी को सूचित किया गया है। तथापि, ऋणदाता एजेंसी द्वारा आवधिक ऋण के डाउन सैलिंग और कंर्सेटियम वित्त के मामले में, अवधि ऋण की स्वीकृति की तिथि पैरा 4.7.3, 4.7.4 तथा 4.7.5 के अनुसार होगी।

6.3.2 चरण 2: योजना के अंतर्गत सब्सिडी के प्राधिकरण-पूर्व के लिए आई-टप्स सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हुए ऋण प्रदाता एजेंसी के माध्यम से कंपनी/इकाई/आवेदक द्वारा वस्त्र आयुक्त को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) के लिए आवेदन और यूआईडी को जारी करना:

आवेदक आवधिक इकाई ऋणदाता एजेंसी(यों) द्वारा आवधिक ऋण की स्वीकृति प्रदान किए जाने के तत्काल पश्चात संशोधित डीपीआर, यदि संशोधित किया गया है, सहित आवधिक ऋण की स्वीकृति की तारीख से 6 महीने के भीतर आई-एटीयूएफएस का प्रयोग करके प्रपत्र-1 (भाग-II एवं III) में व्यौरे प्रस्तुत करेगा। यदि उद्यमी को आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के प्रयोग पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो आवेदक निर्धारित किए गए प्रपत्र-1 (भाग-II एवं III) में आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विवरण अपलोड करने में वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय की सहायता ले सकता है और वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय उसे अपना आवेदन अपलोड करने में सहायता करेगा।

6.3.2.1 आई-एटीयूएफएस के माध्यम से आवेदन की समयबद्ध प्रक्रिया की पद्धति के साथ-साथ स्वतः अलर्ट तंत्र स्थापित किया गया है। अलर्ट की पद्धति नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार ट्रेफिक लाइट पद्धति पर तैयार की गई है:

क्र. सं.	कार्यकलाप की समाप्ति के लिए समय सीमा का % रेंज	प्रस्तुत किए गए आवेदन का रंग
1.	1% - 75% समय	ग्रीन
2.	75% - 90% से अधिक	येलो
3.	90% से अधिक - 100% तक	रेड

6.3.2.2 आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर में आवेदन की प्राप्ति के लिए टीयूएफएस पंजीकरण संख्या के जारी करने और उसके यूआईडी संख्या हेतु प्राधिकरण-पूर्व पद्धति वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई में चलाई जाएगी। यूआईडी संख्या जारी करने संबंधी आवेदन पर योजना के अंतर्गत पात्रता एवं निधि की उपलब्धता के अध्यधीन वस्त्र आयुक्त का कार्यालय स्थित केन्द्रीय सर्वर पर आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर प्राप्त हुए क्रम के अनुसार पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाएगा। तथापि, उन आवेदक (कों) को वरीयता दी जाएगी जिसमें ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी/मशीनरी स्थापित की गई है।

6.3.2.3 उन आवेदनों को वरीयता दी जाएगी जिनमें ऊर्जा बजट प्रौद्योगिकी/मशीनरी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यह वरीयता ऊर्जा बजट मशीनरी के साथ आवेदक को यूआईडी संख्या जारी करने के लिए पृथक कतार प्राप्त करके दी जाएगी और उन आवेदकों को इस पृथक कतार में पहले आओ-पहले पाओ आधार पर यूआईडी संख्या जारी की जाएगी। इसलिए यदि 'एन' वां आवेदक के पश्चात (एन+1)वां आवेदक ऊर्जा बचत मशीनरी के साथ आएगा तो वह ऊर्जा बचत मशीनरी के लिए यूआईडी आवेदकों की कतार में पहला होगा और इसलिए उसे नियमित कतार में प्राथमिकता दी जाएगी।

6.3.2.4 आवधिक ऋण की स्वीकृति और आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र-1 में अन्य विवरण अपलोड करने तथा आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत करते ही ई-मेल और एसएमएस सुविधा द्वारा आवेदक को एक पावती स्वतः जारी की जाएगी।

6.3.2.5 संबंधित ऋणदाता एजेंसी निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-1) में लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यौरे का सत्यापन करेगी। यदि ऋण प्रदाता एजेंसी द्वारा अपेक्षित आंकड़े सभी प्रकार से पूर्ण पाए जाते हैं तो वह उक्त आंकड़ों और आवेदक द्वारा प्रपत्र-1 में प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के अंदर आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर में वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को निर्धारित किए गए प्रपत्र (प्रपत्र-2) में विवरण को अपलोड करेगा। दो महीने की समय सीमा में आवेदक द्वारा प्रपत्र-1 में संशोधन समय शामिल है, यदि अपेक्षित है।

6.3.2.6 यदि आवेदक द्वारा आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदन को ऋण प्रदाता एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 45 दिनों के भीतर जांच नहीं की गई है, तो ऋण प्रदाता एजेंसी (यों) को आई-एटीयूएफएस के माध्यम से प्रणाली जनित येलो अलर्ट भेजा जाएगा। यह मामले को तत्कालिक आधार पर हाथ में लेने के लिए ऋण प्रदाता एजेंसी (यों) को अलर्ट करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि अगले नौ (9) दिनों में संबंधित ऋण प्रदाता एजेंसी (यों) द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ऋण प्रदाता एजेंसी (यों) के संबंधित अधिकारी (यों) के साथ मामले को उठाने के लिए उनके कार्यकारी निदेशक/सीजीएम को एक प्रणाली जनहित रेड अलर्ट भेजा जाएगा ताकि मामले को तत्काल आगे बढ़ाया जा सके। यदि ऋण प्रदाता एजेंसी (यों) आई-एटीयूएफएस के माध्यम से आवेदन की प्राप्ति की तिथि से दो महीने के अंदर आवेदन प्रस्तुत करने में असफल होती है, तो इसे उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन समझा जाएगा।

6.3.2.7 यूआईडी आवेदन जो सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए हैं, निर्धारित किए गए प्रपत्र (प्रपत्र-3) के अनुसार अनिवार्य विवरण की जांच के पश्चात यूआईडी संख्या के आबंटन हेतु वस्त्र आयुक्त का कार्यालय में एक (1) महीने के अंदर आगे बढ़ाया जाएगा और यूआईडी जारी किया जाएगा। यूआईडी संख्या प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई सूचना/दस्तावेज की सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक और संबंधित ऋण प्रदाता एजेंसी (यों) की होगी।

6.3.2.8 यदि कोई स्पष्ट विसंगति होती है तो यूआईडी आवेदन को आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदक और/अथवा संबंधित ऋण प्रदाता एजेंसी को संशोधन और पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाएगा। आवेदन को पुनः प्रस्तुत करने की अधिकतम अवधि एक महीने होगी और इसे पुनः पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाएगा।

6.3.2.9 वस्त्र आयुक्त का कार्यालय में संबंधित अधिकारियों को एक प्रणाली जनित येलो अलर्ट भेजा जाएगा, यदि ऋण प्रदाता एजेंसी से प्राप्त आवेदन पर तेइस (23) दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यदि ऋण प्रदाता एजेंसी से प्राप्त आवेदन के सत्ताइस (27) दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उनके नियंत्रक अधिकारी को प्रणाली जनित रेड अलर्ट भेजा जाएगा और नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पर तत्काल समय पर आवश्यक कार्रवाई की गई है।

6.3.2.10 आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर में यूआईडी संख्या जारी करने के लिए केवल आवेदन प्रस्तुत करने से योजना के अंतर्गत यूआईडी संख्या और सब्सिडी जारी करने के लिए इकाई हकदार नहीं होगी। वस्त्र आयुक्त द्वारा यूआईडी संख्या जारी करने के पश्चात ही कोई इकाई योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र होगी।

6.3.2.11 आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर इस तरह बनाया गया है कि कोई यूआईडी जारी नहीं की जा सकती यदि उस इकाई (प्राधिकरण पूर्व आरआरटीयूएफएस सहित) की सब्सिडी सीमा पूरी हो गई है अथवा/और बजट प्रावधान खत्म हो गया है।

6.3.2.12 आंकड़ा संबंधी सत्यनिष्ठा और योजना के किसी संभावित दुरुपयोग को रोकने की सुनिश्चितता के उद्देश्य से वस्त्र आयुक्त के वेब पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए और संबंधित ऋण प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रमाणित आंकड़े को

अपरिवर्तनीय माना जाएगा और सब्सिडी भुगतान पात्र सब्सिडी के प्रत्यक्ष मूल्यांकन अथवा अपरिवर्तनीय आंकड़े, जो भी कम हो, के अनुसार माना जाएगा।

6.3.2.13 जारी की गई यूआईडी में किसी स्पष्ट गलती अथवा इसके क्रियान्वयन के दौरान परियोजना में संशोधन के मामले में, एटीयूएफएस के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन यूआईडी जारी करने की तिथि से एक साल के अंदर वस्त्र आयुक्त द्वारा मामला दर मामला के आधार पर यूआईडी विवरण में एक बारगी सुधार करने पर विचार किया जाएगा/अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि सब्सिडी में कोई वृद्धि नहीं होगी।

6.4 चरण 3: मशीनरी की स्थापना

6.4.1 इस योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट केवल बैंच मार्क पात्र मशीनरी को ही इकाई द्वारा स्थापित किया जाएगा।

6.4.2 आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंचमार्क वाली सभी पात्र मशीनरी के विनिर्माण का वर्ष, विनिर्माता का नाम और क्रमांक संख्या मशीन (नों) पर स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की गई है। कुल मिलाकर, एक 'मशीन पहचान कोड' (एमआईसी) वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटित की जाएगी जो इस योजना के अंतर्गत खरीदी गई प्रत्येक मशीन के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। यह एमआईसी मशीनरी पर अनिवार्य रूप से उत्कीर्ण किया जाएगा और समय-समय पर प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान सत्यापित की जाएगी।

6.4.3. यह अधिदेश है कि मशीन क्रमांक संख्या 'शिपिंग दस्तावेजों अर्थात् 'वाणिज्यिक बीजक' अथवा 'लदान बिल' अथवा 'हवाई भाड़ा बिल' पर स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए अथवा यह आयातित मशीनरी के मामले में 'आयात पत्र' में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। घरेलू खरीद के मामले में, मशीन क्रमांक संख्या 'वाणिज्यिक बीजक' में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत 01.04.2016 से यह जरूरत का अनिवार्य हिस्सा है और आवेदक को एमआईसी संख्या सौंपना अनिवार्य होगा। इसलिए इस योजना के अंतर्गत इस सूचना की गैरमौजूदगी के कारण लाभ हेतु मशीनरी अयोग्य ठहराई जाएगी।

6.4.4 एमआईसी का निर्णय देश-कोड, राज्य/प्रांत कोड, मशीन विनिर्माता कोड (जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है), मशीन विनिर्माता के अधिकृत एजेंट कोड, वाणिज्यिक बीजक संख्या, आयात पत्र संख्या और लदान बिल संख्या (केवल आयातिक मशीनरी के मामले में), मशीन क्रमांक संख्या आदि के आधार पर किया जाएगा।

6.4.5 उक्त प्रणाली जनित एमआईसी आवेदक को वस्त्र आयुक्त द्वारा तत्काल आवंटित की जाएगी जब वह मशीनरी के संस्थापन/शुरूआत के पश्चात संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) सत्यापन हेतु अनुरोध करेगा।

6.4.6 यूआईडी के अंतर्गत शामिल की गई मशीनों के संस्थापन/शुरूआत अवधि ऋण की स्वीकृति की तिथि से एक (1) वर्ष के भीतर जिसे वस्त्र आयुक्त के अनुमोदन से उचित औचित्य के साथ मामला दर मामला आधार पर दो (2) वर्षों तक विस्तार योग्य है, की जाएगी। इसके लिए चार्टड इंजीनियर से एक प्रमाण पत्र भी किया जाएगा जिसे संस्थापित मशीनरी के प्रत्यक्ष सत्यापन के समय जेआईटी को प्रस्तुत भी किया जाएगा।

6.4.7 यदि आवेदक मशीनरी के संस्थापन/इसकी शुरूआत की प्रक्रिया को तेज करने हेतु आवधिक ऋण की स्वीकृति तिथि से दस (10) माह की अवधि के दौरान संस्थापित मशीनरी, जिसके लिए यूआईडी प्राप्त किया गया था, के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु अपना अनुरोध प्रस्तुत नहीं करता है तो आवेदक को पंजीकृत ई-मेल अथवा एसएमएस के माध्यम से पहला प्रणाली जनित अनुस्मारक भेजा जाएगा।

6.5 चरण 4: इकाई द्वारा वस्त्र आयुक्त के समक्ष सब्सिडी दावे प्रस्तुत करना तथा उनका अनुमोदन।

6.5.1 मशीनरी के संतोषजनक संस्थापन/प्रारंभ किए जाने और वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू होने के उपरांत, आवेदक तत्काल वस्त्र आयुक्त के समक्ष निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-4) में आवधिक ऋण की स्वीकृति की तारीख से 1 वर्ष के भीतर प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु अपने अनुरोध को प्रस्तुत करेगा जोकि एक जेआईटी द्वारा आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किया जाएगा। यह समय सीमा वस्त्र आयुक्त के अनुमोदन के साथ मामला दर मामला आधार दो (2) वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। वस्त्र आयुक्त ऐसे विस्तार को दिए जाने के कारणों को लिखित में रिकार्ड करेगा।

6.5.2 यदि आवेदक आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-4) में जेआईटी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु मशीनरी के संस्थापन के बाद आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो आवेदक को जारी की गई यूआईडी स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा इसके उपरांत इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी हेतु इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.5.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी लाभार्थी इकाई ने निर्धारित सीमा से अधिक की सब्सिडी प्राप्त नहीं की है, आवेदक को लाभार्थी इकाई द्वारा आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत प्राप्त की गई सब्सिडी के व्याप्रों को दर्शाते हुए इकाई के लेटर हेड (प्रपत्र-5) पर एक घोषणा प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। यदि आवेदक ने पूर्व में आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त कर ली हो, तो वह केवल एकल इकाई हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत शेष राशि के लिए ही पात्र होगा।

6.5.4 वस्त्र आयुक्त, योजना के अंतर्गत संस्थापित मशीनों के प्रौद्योगिक स्तर के सत्यापन तथा निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-6) में योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप पात्रता एवं पात्र सब्सिडी राशि के सत्यापन हेतु एक संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) का गठन करेगा जिसमें वस्त्र आयुक्त, संबंधित ऋणप्रदाता एजेंसी, एक वस्त्र अनुसंधान संघ तथा एक उद्योग संघ के अधिकारी/प्रतिनिधि शामिल होंगे।

6.5.5 जेआईटी इन मशीनरी के संस्थापन तथा वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत की जेआईटी हेतु अनुरोध प्राप्त होने के अधिकतम अठासी (88) दिनों के अंदर संस्थापित मशीनरी के चित्रों और सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-6) में जांच तथा सत्यापन करेगी। इसके अलावा, जेआईटी को आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्यक्ष सत्यापन किए जाने के दो (2) दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तथा इसे इसकी एक प्रति वस्त्र आयुक्त को भी प्रेषित करनी होगी।

6.5.6 यदि जेआईटी, जेआईटी हेतु अनुरोध प्राप्त होने के सत्तर (70) दिनों के अंदर आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके अपनी जांच को पूरा नहीं करता है तथा इसे निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-6) में अपलोड नहीं करता है तो वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय के कार्यालय-प्रभारी को प्रणाली जनित येत्रो एलर्ट प्रेषित किया जाएगा। यदि वह आवेदक से जेआईटी सत्यापन हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पचासी (85) दिनों के अंदर कार्रवाई करने में विफल रहता है तो, प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्रवाई हेतु उसके नियंत्रण अधिकारी सहित संबंधित कार्यालय-प्रभारी को प्रणाली जनित एक रेड एलर्ट प्रेषित किया जाएगा।

6.5.7 वस्त्र आयुक्त का कार्यालय जेआईटी से वस्त्र आयुक्त के अनुमोदन/नामंजूरी हेतु जेआईटी रिपोर्ट प्राप्त होने के एक माह के अंदर निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-7) में सब्सिडी दावे पर कार्रवाई करेगा।

6.5.8 यदि आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जेआईटी रिपोर्ट की प्राप्ति के तेहस (23) दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संबंधित निदेशक/संयुक्त वस्त्र आयुक्त/अपर वस्त्र आयुक्त को एक प्रणाली जनित येत्रो एलर्ट प्रेषित किया जाएगा। यदि, वे जेआईटी रिपोर्ट प्राप्त होने के सत्ताइस (27) दिनों के अंदर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो वस्त्र आयुक्त तथा अपर वस्त्र आयुक्त को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली जनित रेड एलर्ट प्रेषित किया जाएगा।

6.5.9 वस्त्र आयुक्त का कार्यालय वस्त्र आयुक्त के अनुमोदन के उपरांत अनुमोदित दावों हेतु बिल तैयार करेगा तथा आई-एटीयूएफएस के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) को सब्सिडी दावों हेतु चालान प्रस्तुत करेगा।

6.6 चरण-5: वस्त्र मंत्रालय द्वारा आवेदक के चालू ऋण खाते में पात्र सब्सिडी को जारी किया जाना।

6.6.1 वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) वस्त्र आयुक्त से (प्रपत्र-8) के अनुसार आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त हुए दावों पर कार्रवाई करेगा तथा निधि की उपलब्धता की शर्त के अध्ययन, पात्र सब्सिडी को आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दावा बिल/चालान की प्राप्ति की तिथि से इक्कीस (21) दिनों के अंदर संबंधित ऋण प्रदाता एजेंसी द्वारा रखे जा रहे ऋण प्राप्तकर्ता/आवेदक के खाते में सीधे तौर पर जारी करेगा। इकाई का खाता इकाई के पैन नंबर तथा आधार नंबर (जहां कहीं भी लागू हो) से संबद्ध होना चाहिए।

6.6.2 पूरी राशि केवल तभी जारी की जाएगी जब आवेदक ने एटीयूएफएस के अंतर्गत केवल एक ऋण प्रदाता एजेंसी से ऋण प्राप्त किया हो। तथापि यदि आवेदक ने आवधिक ऋण की डाउन सेलिंग अथवा कंसोर्टियम फाइनेंसिंग की सुविधा प्राप्त की हो तो सब्सिडी राशि को संबंधित ऋण प्राप्तकर्ता के खाते में यथा अनुपात आधार पर जमा कर दिया जाएगा।

6.6.3 यदि प्राप्त दावा बिलों/चालानों पर आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से इसकी प्राप्ति के सत्रह (17) दिनों के अंदर कार्रवाई न की गई हो तो वस्त्र मंत्रालय के संबंधित उपनिदेशक/निदेशक को प्रणाली जनित येत्रो एलर्ट जारी किया जाएगा। यदि इन पर वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से दावा प्राप्ति के उन्नीस (19) दिनों के अंदर कार्रवाई न की गई हो तो संयुक्त सचिव (एटीयूएफएस)/अपर सचिव (एटीयूएफएस) को इन पर पैरा-6 में उल्लिखित समय-सीमा तथा प्रोसेस फ्लो चार्ट (अनुबंध-8) के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली जनित रेड एलर्ट प्रेषित किया जाएगा।

6.6.4 ऋण प्राप्तकर्ता/आवेदक के खाते में डीबीटी मोड में सब्सिडी जारी किए जाने को सब्सिडी राशि का एक उपयुक्त प्रयोग माना जाएगा और इसके बाद किसी उपयोगिता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. निगरानी प्रणाली:-

इस योजना का प्रचालन एक द्विस्तरीय निगरानी प्रणाली के साथ किया जाएगा जिसमें तकनीकी परामर्शदात्री - सह-निगरानी समिति (टीएएमसी) तथा अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी) शामिल होंगे।

7.1 तकनीकी परामर्शदात्री - सह-निगरानी समिति (टीएएमसी): वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी परामर्शदात्री - सह-निगरानी समिति (टीएएमसी) का गठन किया जाएगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए सरकार तथा उद्योग से सदस्यों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। टीएएमसी का गठन एवं कार्य अनुबंध-ड. पर संलग्न है।

7.1.1 मशीनरी की सूची में जोड़ने/हटाने के संबंध में संशोधन टीएएमसी के द्वारा किया जाएगा।

7.1.2 यदि योजना के अंतर्गत किसी इकाई अथवा मशीनरी की पात्रता के संबंध में ऋण प्रदाता एजेंसी/उद्यमियों द्वारा व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण से संबंधित कोई प्रश्न उठाया जाता है तो टीएएमसी का निर्णय अंतिम होगा।

7.1.3 टीएएमसी क्षेत्र-वार प्रगति सहित योजना की प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा करेगी तथा मंत्रालय और आईएमएससी को वैमासिक आधार पर अवगत कराएगी।

7.2 अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी):

7.2.1 वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में एक आईएमएससी का गठन किया जाएगा जिसमें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग तथा वित्तीय सेवाएं विभाग), भारी उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, नीति आयोग, चयनित ऋण प्रदाता एजेंसियों, वस्त्र उद्योग के संघों आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आईएमएससी आर्थिक मामलों पर मंत्रीमंडलीय समिति के अनुमोदन के अनुरूप योजना के प्रभारी क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देशों को तैयार करने तथा निगरानी हेतु उत्तरदायी होगी। आईएमएससी का गठन तथा कार्य अनुबंध-च पर संलग्न है।

7.2.2 आईएमएससी योजना की प्रगति की अद्वार्षिक आधार पर समीक्षा करेगी तथा इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

8. यूआईडी के निरस्तीकरण हेतु प्रावधान:-

8.1 योजना के अंतर्गत जारी की गई यूआईडी को उन मामलों में निरस्त कर दिया जाएगा जहां:-

8.1.1 आवेदक, एक संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किए जाने के लिए आवधिक ऋण की स्वीकृति की तिथि से दो (2) वर्ष के अंदर मशीनरी के संस्थापन के बारे में सूचित करने से विफल रहता है। आवेदक को जारी की गई यूआईडी स्वतः निरस्त कर दी जाएगी तथा इस पर इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी लाभों के लिए आगे विचार नहीं किया जाएगा।

8.1.2 आवेदक किसी अन्य कारण से योजना के अंतर्गत लाभ नहीं प्राप्त करने का निर्णय लेता है और इस संबंध में आई-एटीयूएफएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए संबंधित ऋण प्रदाता एजेंसी के माध्यम से जारी की गई यूआईडी के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध को अपलोड कर सकता है। यह अनुरोध निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-9) में किया जाना चाहिए।

8.1.3 किसी अन्य स्तर पर आवेदन के निरस्त हो जाने पर यूआईडी स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।

9. दुरुपयोग से बचाव के उपाय:-

9.1 योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

9.1.1 इस योजना के अंतर्गत जारी की गई यूआईडी पर सृजित की गई परिसंपत्तियों तथा उनके प्रौद्योगिकीय स्तर पर प्रत्यक्ष सत्यापन एक संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा जिसमें वस्त्र आयुक्त, संबंधित ऋण प्रदाता एजेंसियों, वस्त्र अनुसंधान संघ तथा उद्योग संघ के अधिकारी/प्रतिनिधि शामिल होंगे। जेआईटी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता तथा पात्र सब्सिडी राशि का प्रमाणन करेगी।

9.1.2 यह अनिवार्य किया गया है कि सभी पात्र मशीनरी के मॉडल, विनिर्माण के वर्ष, विनिर्माता का नाम तथा क्रम संख्या को मशीन/मशीनों पर स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। इसके अलावा वस्त्र आयुक्त द्वारा 'मशीन पहचान कोड' (एमआईसी) भी आवंटित किया जाएगा जोकि इस योजना के अंतर्गत खरीदी गई प्रत्येक मशीन हेतु एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। यह एमआईसी मशीनरी पर लिखना अनिवार्य होगा तथा अलग-अलग समय पर प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान इसका सत्यापन किया जाएगा।

9.1.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी लाभार्थी इकाई निर्धारित सीमा से अधिक सब्सिडी प्राप्त नहीं कर रही है, आवेदक को आरआरटीयूएफएस तथा एटीयूएफएस के अंतर्गत लाभार्थी इकाई द्वारा प्राप्त की जा रही सब्सिडी के विवरण को दर्शाते हुए इकाई के लेटर हेड पर कंपनी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

9.1.4 वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी संस्थापित/शुरू की गई मशीनरी समय-समय पर आकस्मिक आधार पर निरीक्षण करेंगे।

9.1.5 मंत्रालय द्वारा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए सैंपल आधार पर थर्ड पार्टी इंजीनियरिंग परामर्शदाताओं को शामिल किया जाएगा।

9.1.6 यह अपेक्षा की जाती है कि इकाई कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक कार्य करेगी। 3 वर्षों तक इकाई के कार्यचालन की निगरानी के लिए ऋण प्रदाता एजेंसी/यों को एसएसआई इकाई के मामले में मॉरोटोरियम अवधि सहित न्यूनतम पुनर्जदायगी अवधि को 3 वर्ष तथा अन्य इकाइयों के मामले में 5 वर्ष निर्धारित करना होगा।

10. शिकायत निवारण प्रणाली:

10.1 इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-10) में प्राप्त हुई सभी शिकायतों का निवारण वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक शिकायत समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें वस्त्र मंत्रालय, ऋण प्रदाता एजेंसियों तथा उद्योग संघों आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

10.2 एटीयूएफएस नीति संबंधी मामलों तथा एटीयूएफएस की व्याख्या आदि से संबंधित शिकायतों को निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-11) में सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा जो इनका समाधान करेंगे।

11. दिशानिर्देशों में संशोधन:

वित्तीय मामलों से जुड़े हए इन दिशानिर्देशों में कोई भी संशोधन व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के पूर्व अनुमोदन के द्वारा ही किया जाएगा। वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य मामलों से संबंधित संशोधन आईएमएससी के अनुमोदन द्वारा किए जा सकते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को प्रेषित की जाएं।

पुष्पा सुब्रह्मण्यम
अपर सचिव
अनुबंध-क

एकाधिक वित्तपोषण न होने का वचन-पत्र
(इकाई के लेटर हैड पर)

दिनांक :

हम _____ (लाभार्थी इकाई का नाम) एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि कोई मशीनरी अथवा उसका कोई भाग, जिसके लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत लाभों के लिए दावा किया गया है, हेतु इस बैंक तथा/अथवा किसी अन्य बैंक (बैंकों)/ऋणप्रदाता एजेंसी/एजेंसियों/वित्तीय संस्थानों से एक बार से अधिक ऋण प्राप्त नहीं किया है।

सभी परियोजनाओं तथा प्राप्त किए गए ऋणों जहां हमारे द्वारा टीयूएफएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए गए हैं, का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना राशि (परियोजना लागत)	परियोजना हेतु प्राप्त किए गए ऋण (संवितरित ऋण की राशि)	ऋणप्रदाता बैंक/वित्तीय संस्थान/ऋणप्रदाता एजेंसी
कुल				

हम यह वचन देते हैं कि ऊपर उल्लिखित तथ्यों में किसी प्रकार की गलती पाए जाने पर, ऋणप्रदाता एजेंसी अथवा सरकार द्वारा हम पर लगाए गए दण्डात्मक व्याज सहित संपूर्ण सब्सिडी राशि की प्रत्यक्ष रूप से सरकार को अथवा सरकार के निदेश के अनुसार ऋणप्रदाता एजेंसी के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरकार अथवा ऋणप्रदाता एजेंसी भी पात्रता को रद्द करने, ब्लैक लिस्ट करने आदि, जैसा भी उचित हो, के लिए प्राधिकृत होंगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम
कृते (लाभार्थी इकाई का नाम)
(कृपया कंपनी/इकाई की सील/रबर स्टैप लगाएं)

* टीयूएफएस (प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना) का तात्पर्य तथा इसमें टीयूएफएस, एमटीयूएफएस, आरटीयूएफएस आरआरटीयूएफएस एवं एटीयूएफएस शामिल हैं।

टीयूएफएस संदर्भ संख्या _____

अनुबंध-ख

एक बैंक/ऋण प्रदाता एजेंसी से दूसरी ऋण प्रदाता एजेंसी तक आवधिक ऋण को टेकओवर करने हेतु अनुरोध

नोट : दूसरी ऋण प्रदाता एजेंसी में परिवर्तन के समय इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई ऋणप्रदाता एजेंसी एटीयूएफएस के अंतर्गत शामिल है।

क्र.सं.	व्याख्या	विवरण	संलग्न सहायक दस्तावेज
1.	यूआईडी संख्या एवं तिथि		
2.	वर्तमान बैंक का नाम		
3.	प्रारंभिक बैंक द्वारा स्वीकृत कुल आवधिक ऋण (रूपए में)		
4.	टीयूएफएस के अंतर्गत ऋण खाते में शेष राशि जिसे अन्य बैंक द्वारा टेक ओवर किया जा रहा है		
5.	नए बैंक का नाम		
6.	पिछले बैंक द्वारा किस तिमाही तक दावों को दर्ज किया गया है		
7.	क्या टीयूएफएस के अंतर्गत अन्य बैंक द्वारा खाते को टेक ओवर करने के लिए पिछले बैंक द्वारा एनओसी जारी किया गया है		
8.	नए बैंक द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के विवरण के साथ नए बैंक द्वारा टेक ओवर किए गए आवधिक ऋण की वास्तविक राशि		
9.	वह तिमाही जिससे नया बैंक दावे प्रस्तुत करेगा		
10.	बैंक में परिवर्तन का कारण		

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत की गई सूचना सही है और इकाई के पास उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर है जिनका सत्यापन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

दिनांक

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम एवं पदनाम)

नोट: कृपया प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर के साथ कंपनी/इकाई की सील/रबर स्टैंप लगाएं।

अनुबंध - ग

एटीयूएफएस के अंतर्गत ऋणप्रदाता एजेंसी को शामिल करने हेतु प्रपत्र

(आई-एटीयूएफएस के सॉफ्टवेयर के माध्यम से वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत किया जाना)

1.	बैंक का नाम	
2.	पता	
3.	आईएफएससी कोड	
4.	एमआईसीआर कोड	
5.	संपर्क व्यक्ति का नाम	
6.	दूरभाष नं. (कार्यालय)	
7.	मोबाइल	
8.	ई-मेल आईडी	
9.	फैक्स नं.	

10.	ब्रांच का नाम	
11.	ब्रांच का आईएफएससी कोड	
12.	ब्रांच का एमआईसीआर कोड	
13.	संपर्क व्यक्ति	
14.	दूरभाष नं. (कार्यालय)	
15.	मोबाइल	
16.	ई-मेल आईडी	
17.	फैक्स नं.	

दिनांक:

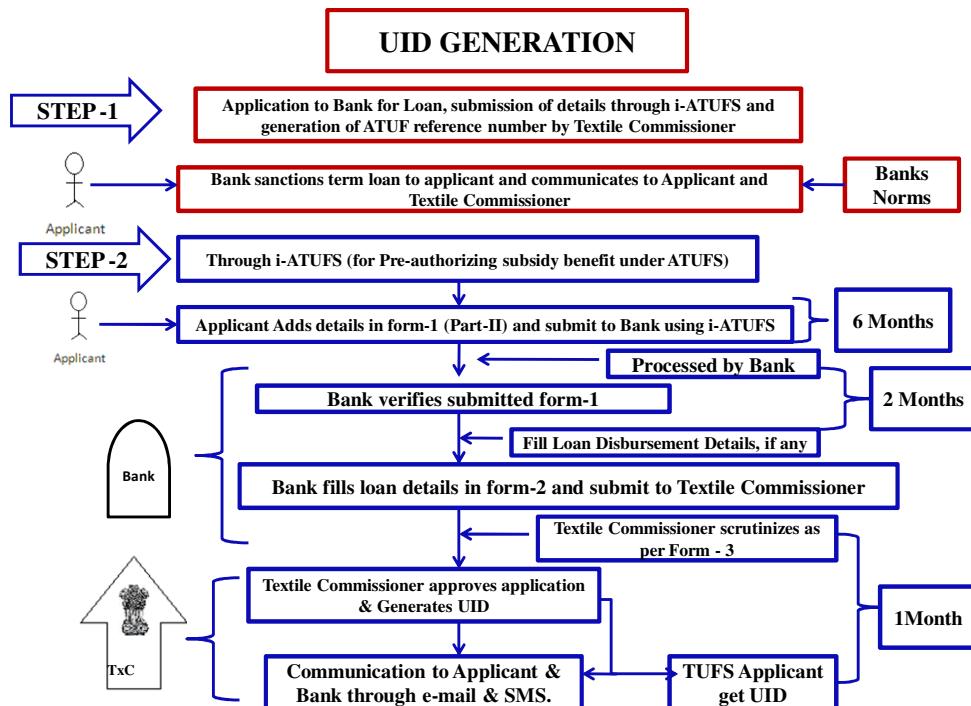
हस्ताक्षर

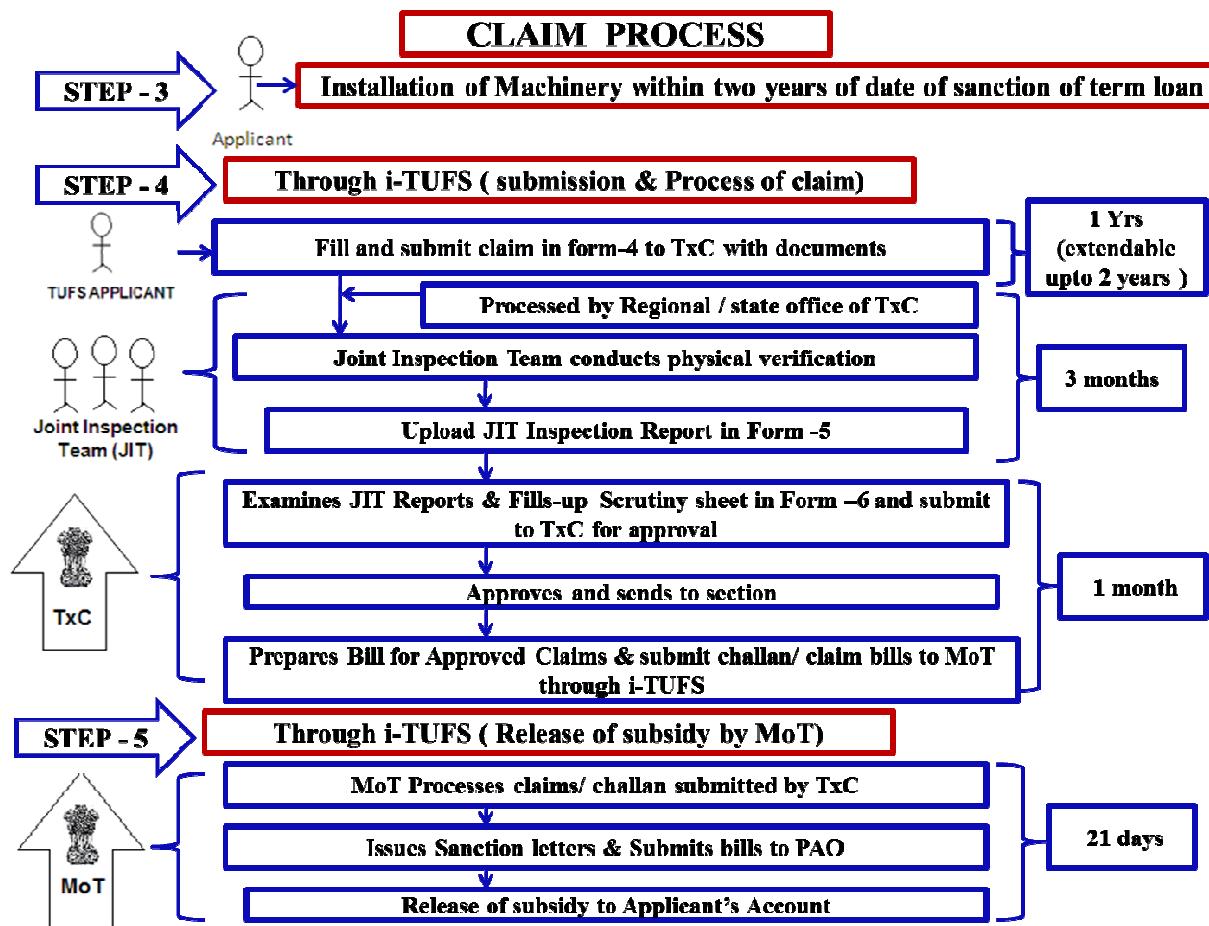
सील के साथ नाम एवं पदनाम

संलग्नकों का विवरण:

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी बैंकिंग लाईसेंस की प्रति
- आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने हेतु आरबीआई द्वारा जारी पत्र की प्रति
- मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, यदि लागू हो तो, के अंतर्गत पंजीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी प्रति
- पैन/टैन संख्या की प्रति
- पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रति
- अन्य संबंधित जानकारी, यदि कोई हो।

अनुबंध- घ





अनुबंध-८

टीएमसी का गठन

1.	वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई	अध्यक्ष
2.	निदेशक (एटीयूएफएस), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
3.	पटसन आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, कोलकाता	सदस्य
4.	आौद्योगिक सलाहकार, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
5.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (आईडब्ल्यूएमएफ), मुंबई	सदस्य
6.	अध्यक्ष, भारतीय ऊनी मिल परिसंघ (आईडब्ल्यूएमएफ), मुंबई	
7.	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडिया आर्ट सिल्क विविंग इंडस्ट्री	सदस्य
8.	अध्यक्ष, भारतीय स्पिनर्स संघ (आईएसए), मुंबई	सदस्य
9.	अध्यक्ष, दक्षिण भारत स्पिनर्स संघ (एसआईएसपीए), कोयम्बटूर	सदस्य
10.	अध्यक्ष, लुधियान निटवियर क्लब, लुधियाना	सदस्य
11.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र मशीनरी विनिर्माता संघ (टीएमएआई), मुंबई	सदस्य
12.	अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल संघ (आईजेरेमए), कोलकाता	सदस्य

13.	अध्यक्ष, क्लोटिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई), मुंबई	सदस्य
14.	अध्यक्ष, विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पेडिकिसल), मुंबई	सदस्य
15.	अध्यक्ष, कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टेक्सप्रोसिल), मुंबई	सदस्य
16.	अध्यक्ष, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), गुडगांव	सदस्य
17.	अध्यक्ष, सिंथेटिक एवं रेयान टेक्सटाइल्स संवर्धन परिषद, मुंबई	सदस्य
18.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, आईडीबीआई बैंक, मुंबई	सदस्य
19.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), लखनऊ	सदस्य
20.	अध्यक्ष, दक्षिण भारत मिल संघ, कोयम्बूर	सदस्य
21.	अध्यक्ष, भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ (आईटीटीए), मुंबई	सदस्य
22.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली	सदस्य
23.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
24.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
25.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
26.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, एनसीटीसी, नई दिल्ली	सदस्य
27.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, बैंक ऑफ बडौदा, मुंबई	सदस्य
28.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, इंडियन ओवरसीज बैंक, मुंबई	सदस्य
29.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
30.	प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, पंजाब नेशनल बैंक, मुंबई	सदस्य
31.	निदेशक, बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई	सदस्य
32.	एटीयूएफएस के प्रभारी अपर/संयुक्त वस्त्र आयुक्त, वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई	सदस्य सचिव

2. टीएमसी क्षेत्र-वार प्रगति के साथ-साथ योजना की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी करेगी और मंत्रालय तथा आईएमएससी को त्रैमासिक आधार पर सूचित करेगी।

3. टीएमसी पात्र मशीनरी को हर वर्ष 1 अप्रैल को अद्यतन तथा विनिर्दिष्ट करेगी।

अनुबंध-च

आईएमएससी का गठन

1.	केंद्रीय वस्त्र मंत्री	अध्यक्ष
2.	सचिव, वस्त्र मंत्रालय	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
4.	सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	सदस्य
5.	सचिव, वाणिज्य विभाग	सदस्य
6.	सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य
7.	सचिव, भारी उद्योग विभाग	सदस्य
8.	सचिव, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय	सदस्य

9.	उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
10.	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
11.	वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई	सदस्य
12.	पटसन आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, कोलकाता	सदस्य
13.	विकास आयुक्त (हथकरघा), नई दिल्ली	सदस्य
14.	सलाहकार, (वस्त्र प्रभारी), नीति आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
15.	सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलुरु	सदस्य
16.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई	सदस्य
17.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिड्नी	सदस्य
18.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईएफसीआई	सदस्य
19.	अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	सदस्य
20.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र मशीनरी विनिर्माता संघ (टीएमएमएआई), मुंबई	सदस्य
21.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई), नई दिल्ली	सदस्य
22.	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडिया आर्ट सिल्क विविंग इंस्ट्री, सूरत	सदस्य
23.	अध्यक्ष, भारतीय ऊनी मिल परिसंघ (आईडब्ल्यूएमएफ), मुंबई	सदस्य
24.	अध्यक्ष, विद्युतकरघा विकास एवं नियांत संवर्धन परिषद (पेडिक्सिल), मुंबई	सदस्य
25.	अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल संघ (आईजे एमए), कोलकाता	सदस्य
26.	अध्यक्ष, क्लोरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
27.	अध्यक्ष, भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ (आईटीटीए), मुंबई	सदस्य
28.	अध्यक्ष, दक्षिण भारत स्पिनर्स संघ, कोयम्बटूर	सदस्य
29.	अध्यक्ष, दक्षिण भारत मिल संघ, कोयम्बटूर	सदस्य
30.	अपर/संयुक्त सचिव (एटीयूएफएस प्रभारी)	सदस्य सचिव

2. आईएमएससी सीसीईए अनुमोदन के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देशों को तैयार करने और उनकी मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी होगी। आईएमएससी योजना की प्रगति की अर्द्ध वार्षिक आधार पर समीक्षा करेगी तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

3. वित्तीय मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों के संबंध में योजना में कोई भी संशोधन आईएमएससी के अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है।

प्रपत्र -1

(लाभार्थी द्वारा जमा किया जाए)

पार्ट-I

टिप्पणी:

- कृपया सही विकल्प, जहां कहीं लागू हो, पर (✓) करें।
- राशि केवल रूपए में लिखी जाए। यदि राशि हजार/लाख अथवा करोड़ में लिखी जाएगी, तो आवेदन संशोधन के लिए वापस किया जाएगा और लाभार्थी प्राधिकृत पूर्व सब्सिडी में वरिष्ठता क्रम की हानि हो सकती है।
- जिस लाभार्थी ने आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत किसी आवधिक ऋण के लिए ऑनलाइन प्रपत्र 1 भाग । पहले ही भर दिया है उसे दोबारा प्रपत्र 1 का भाग । जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, यदि सूचना में कोई परिवर्तन नहीं है। हालांकि उसे प्रपत्र 1 के भाग II से भाग IV में अनिवार्य रूप से अन्य सभी विवरण भरना होगा।

क. i. आवेदक के बैंक/संस्था का नाम	
ii. आवेदक के बैंक/संस्था का पता	
iii. आईएफएससी कोड	
iv. एसटीडी कोड सहित दूरभाष	
v. फैक्स	
vi. ई-मेल आईडी	
ख. i. बैंक के संपर्क अधिकारी का नाम	
ii. मोबाइल	
iii. फैक्स	
iv. ई-मेल आईडी	
ग. आवधिक ऋण के लिए बैंक हेतु आवेदन की तिथि	

क. कंपनी/फर्म की सूचना

कंपनी/फर्म का नाम					
		नाम	पैन	डीआईएन	आधार कार्ड
1. प्रवर्तकों/निदेशकों/ मालिकों/साझीदारों के नाम					
2.	संपर्क व्यक्ति का नाम				
	दूरभाष				
	मोबाइल				
	फैक्स				
	ई-मेल आईडी				
3.	कंपनी/फर्म का संयंत्र (त्रों) का पता (ते) सहित पिन कोड				
	एसटीडी कोड सहित दूरभाष				
	फैक्स				
	ई-मेल आईडी				

4.	पंजीकृत कार्यालय पता सहित पिन कोड			
	एसटीडी कोड सहित दूरभाष			
	फैक्स			
	ई-मेल आईडी			
5.	यूनिट का पैन.			
6.	क्या यह कंपनी/फर्म	एमएसई है (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006)	गैर-एमएसई है (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006)	
7.	प्रबंधन अर्थात् स्वामित्व/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/ पब्लिक लिमिटेड कंपनी/सहकारी/अन्य?			
8.	क) क्या यह विद्यमान कंपनी/फर्म अथवा एक नई कंपनी/फर्म है?	विद्यमान	<input type="checkbox"/>	नई <input type="checkbox"/>
ख)	कृपया शुरू करने की तिथि बताएं	<hr style="display: inline-block; width: 100px; vertical-align: middle;"/> / <hr style="display: inline-block; width: 100px; vertical-align: middle;"/> / <hr style="display: inline-block; width: 100px; vertical-align: middle;"/>		
		(दिन / माह / वर्ष)		
9.	क. क्षेत्र			
i)	विद्यमान			
ii)	विस्तार पश्चात्			
ख.	अपने वर्तमान कार्यकलापों सहित कंपनी/फर्म की संक्षिप्त पृष्ठभूमि			
ग.	विनिर्मित किए जा रहे/किए जाने वाले उत्पाद			
घ.	उत्पादों का अंतिम प्रयोग एप्लीकेशन			

ख. वर्तमान परियोजना संबंधी सूचना

[कृपया विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अपलोड करें जिस पर बैंक ने आवधिक ऋण प्रदान किया गया है]

1. वर्तमान परियोजना का संक्षिप्त विवरण			
2. क्षेत्र	बुनाई प्रिप्रेटरी/बुनाई/निटिंग/प्रसंस्करण/तकनीकी वस्त्र/परिधान		
3. परियोजना पूरी करने की बढ़ी हुई तिथि	<hr style="display: inline-block; width: 100px; vertical-align: middle;"/> / <hr style="display: inline-block; width: 100px; vertical-align: middle;"/> / <hr style="display: inline-block; width: 100px; vertical-align: middle;"/>		
	(दिन / माह / वर्ष)		

प्रपत्र 1

भाग II

क. परियोजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले मुख्य संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण: (राशि रूपए में)

क्र. सं.	मशीनरी/उपकरण का विवरण	मशीनरी मद्दै का की सं.	क्या मशीनरी की खरीद आवधिक ऋण की स्वीकृति से पूर्व अथवा पश्चात की गई है (जो भी कॉलम लागू है सही का निशान लगाएं) कृपया संख्या एवं तिथि सहित प्रपत्र बीजक/अंतिम बीजक का विवरण लिखें)	कुल लागत (मशीन-वार)	*मशीन/उपकरण की मूल लागत (मशीन-वार))	मिंट के संबंध में जीआर के अनुसार अनुबंध सं. एवं मद संख्या	कॉलम (11) में विनिर्दिष्ट अनुसार मशीन/उपकरण की वास्तविक विशेषताएं/विवरण के साथ-साथ मिंट संबंधी विशेषताएं/विवरण	क्या यह संपूर्ण मशीन के रूप में अधिप्राप्त की गई अथवा यह विद्यमान मशीन का आंशिक उन्नयन/आंशिक प्रतिस्थापन है? (जो भी कॉलम लागू है सही का निशान लगाएं)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

नोट:

* स्वदेशी मशीनरी उपकरण के संबंध में मूल कीमत (मशीन-वार) और आयातित मशीनरी/उपकरण के संबंध में सीआईएफ कीमत मशीन-वार

क.	स्वीकृत किया गया कुल आवधिक ऋण	रु. _____ (कृपया बैंकों से प्राप्त हुए आवधिक ऋण(ों) के स्वीकृति पत्र(ों) की एक प्रतिलिपि अपलोड करें)
ख.	प्रवर्तकों का अंशदान	रु. _____, परियोजना लागत का ____%
ग.	आवधिक ऋण खाता सं.	केवल अंकीय संख्या
घ.	क्या आवधिक ऋण अन्य बैंक(कों)/संस्था(ओं) द्वारा शेयर किया जा रहा है?	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
ड.	यदि हां, शेयरिंग पैटर्न दर्शाएं	बैंक/संस्था का नाम <input type="text"/> राशि (रूपए में) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> कुल <input type="text"/>
	परियोजना के क्रियान्वयन के आरंभ की तिथि	____/____/____ (दिन / माह/ वर्ष)
	इकाई के आधुनिकीकरण का स्तर/प्रतिशतता	इस योजना से पहले <input type="checkbox"/> इस योजना के पश्चात <input type="checkbox"/>

प्रपत्र-1 (जारी)

भाग-III

1. यूनिट द्वारा आज की तिथि (1999 के बाद से) तक लिए गए टफस ऋण और सब्सिडी लाभ पर सूचना और अब तक प्राप्त सुधारः

अब तक प्राप्त टफस ऋण और प्राप्त सब्सिडी का व्यौरा						टफस परियोजना कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अंजित लाभ					
माह/वर्ष	परियोजना लागत	स्वीकृत आवधिक ऋण	बैंक/एलए	*क्षेत्र	प्राप्त सब्सिडी राशि	*जोड़ी गई/प्रतिस्थापित की गई क्षमता	कारोबार में वृद्धि (%)	लाभ में वृद्धि (%)	नियोत में वृद्धि (%)	गुणवत्ता में सुधार **	प्राप्त की गई आधुनिकीकरण की सीमा (%)***

नोट: *1. क्षेत्र एवं क्षमता विवरण प्रदान किए गए ड्रॉप-डाउन-मेनू से चयन किया जाएगा।

**2. लाभार्थी इकाई द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार (अच्छा/बहुत अच्छा/उत्कृष्ट आदि)

***3. प्राप्त आधुनिकीकरण की सीमा लाभार्थी द्वारा स्व-मूल्यांकन के अनुसार होगा।

2. आरआरटफस के अंतर्गत यूनिट द्वारा लिए गए टफस ऋण और सब्सिडी लाभ पर सूचना:

क्र.सं.	खाता सं.	टीयूएफ संदर्भ सं. और यूआईडी नं.	पूर्ण अवधि के लिए अधिकृत सब्सिडी रूपए में	आवेदन के समय तक प्राप्त सब्सिडी रूपए में

3. लाभार्थी का वैयक्तिक विवरण

(जहां कहीं लागू हो कृपया सही का निशान लगाएं)

I. मालिक के मामले में

लिंग	पुरुष/ महिला	
क्या अनु.जा./अनु.ज.जा. से संबंधित हैं	हां <input type="checkbox"/> अजा/अजजा <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
क्या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>

II. साझीदार फर्म के मामले में

साझीदारों की संख्या		
लिंग (संख्या)	पुरुष <input type="checkbox"/>	महिला <input type="checkbox"/>
अनु.जा./अनु.ज.जा. (संख्या)	अजा/अजजा <input type="checkbox"/>	अन्य <input type="checkbox"/>
अल्पसंख्यक समुदाय (संख्या)	अल्पसंख्यक <input type="checkbox"/>	अन्य <input type="checkbox"/>

III. लिमिटेड कंपनी के मामले में

एमडी सहित निदेशकों की संख्या		
लिंग (संख्या)	पुरुष <input type="checkbox"/>	महिला <input type="checkbox"/>
अनु.जा./अनु.ज.जा. (संख्या)	अजा/अजजा <input type="checkbox"/>	अन्य <input type="checkbox"/>
अल्पसंख्यक समुदाय (संख्या)	अल्पसंख्यक <input type="checkbox"/>	अन्य <input type="checkbox"/>

सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम (एमएसई) पर सूचना

नीचे मद सं. 1 से 4 केवल एमएसई इकाइयों द्वारा भरी जाए (दूसरे शब्दों में गैर-एमएसई इकाइयां नीचे मद सं. 1 से 4 छोड़ दी जाए)	

रोजगार पर सूचना (संख्या में)

विद्यमान रोजगार			इस परियोजना के अंतर्गत सृजित किए जाने वाले रोजगार			इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात कुल रोजगार		
प्रबंधकीय	पर्यवेक्षकीय	कामगार	प्रबंधकीय	पर्यवेक्षकीय	कामगार	प्रबंधकीय	पर्यवेक्षकीय	कामगार

क्षमता का विवरण

क्षेत्र	वर्तमान स्थापित क्षमता	प्रस्तावित विस्तार [नेट] / नई क्षमता	परियोजना के पूरा होने पर स्थापित क्षमता
1. ट्रिविस्टिंग/टी.एफ.ओ. (मशीनों की संख्या में)			
2. वार्पिंग (मशीनों की संख्या में)			
3. फाइबर डाइंग (कि.ग्रा./माह में)			
4. यार्न डाइंग (कि.ग्रा./माह में)			
5. साइजिंग (मशीनों की संख्या में)			
6. शटल रहित करघे (करघों की संख्या में)			
7. (प्रोजेक्टाइल/रैपियर/एयर-जेट/वाटर-जेट)			
8. निटिंग (मशीनों की संख्या में)			
9. वुवन फैब्रिक डाइंग (मीटर/माह में)			
10. निटेड फैब्रिक डाइंग (कि.ग्रा./माह में)			
11. वुवन फैब्रिक प्रिंटिंग (मीटर/माह में)			
12. निटेड फैब्रिक प्रिंटिंग (मीटर/माह में)			
13. गारमेंटिंग/मेड-अप्स (नग की संख्या/माह में)			
14. तकनीकी वस्त्र (कृपया अंतिम उत्पाद का उल्लेख करें)			
क. वुवन ख. नॉन-वुवन ग. निटेड			
15. कोई अन्य			

परियोजना लागत का व्यौरा:

मट	रुपया में	
	कुल लागत	मूल कीमत [अर्थात् कर संघटक जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयात शुल्क आदि को छोड़कर]
भूमि		
कारखाना भवन		
प्रारंभिक और संचालन पूर्व खर्च		
कार्यशील पूँजी के लिए मनी मार्जिन		
मुख्य संयंत्र एवं मशीनरी		
अन्य स्थायी निवेश		
कुल		

आवधिक ऋण की स्वीकृति की तिथि से पूर्व हुआ व्यय

क्या आवधिक ऋण की स्वीकृति से पूर्व कोई व्यय हुआ है	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
--	------------------------------	-------------------------------

जो हां, आवधिक ऋण की स्वीकृति की तिथि से पूर्व मशीनरी/उपकरण पर हुए व्यय का व्यौरा

(रूपण)

दिनांक	मशीनरी/उपकरण [प्रपत्र में दी गई सूचना के अनुरूप यहां विवरण प्रस्तुत किया जाए]		कुल लागत (मशीन-वार)	मूल/सीआईएफ कीमत (मशीन-वार) [अर्थात् कर संघटक जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयात शुल्क आदि को छोड़कर]	व्यय हई राशि (मशीन-वार)	क्य मशीन-वार भुगतान किया गया (कृपया 'हां अथवा 'नहीं' में उल्लेख करें)	निधि का स्रोत
	आयातित	स्वदेशी					
1	2	3	4	5	6	7	8
	कुल (I)						

आवधिक ऋण की स्वीकृति की तिथि से पूर्व परियोजना पर हुआ कुल व्यय: रुपए _____ .

प्रपत्र-1 (जारी)

भाग-IV

सत्यापित किया जाता है कि:

- प्रपत्र 1 के भाग-I, भाग-II और भाग-III में दी गई सूचना सही हैं और यूनिट के पास उपलब्ध दस्तावेज संबंधी साक्ष्य के आधार पर दी गई हैं जिसे किसी भी समय अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सत्यापित की जा सकती है।
- मैं/हम एतद्वारा यह सत्यापित करता (करते) हूं (हैं) कि यूनिट/फर्म संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित की गई समग्र सीमा के अंदर योजना के अंतर्गत सब्सिडी दावे के लिए पात्र हैं।
- मैं/हम _____ (लाभार्थी यूनिट का नाम) एतद्वारा यह सत्यापित करता (करते) हूं (हैं) कि कोई मशीनरी अथवा उसका कोई हिस्सा जिसके लिए टीयूएफएस के अंतर्गत दावा किया जा रहा है/दावा किया गया है (टीयूएफएस, एमटीयूएफएस, आरटीयूएफएस और आरआरटीयूएफएस सहित) इस बैंक और अन्य कोई बैंकों/ऋणप्रदाता एजेंसियों/वित्तीय संस्थानों से एक से अधिक वार ऋण निधि नहीं दी गई है। विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (विनिर्दिष्ट प्रपत्र में) की एक प्रति अपलोड की गई है जिसे सब्सिडी संबंधी दावे के समय मूल रूप में जेआईटी को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- मैं/हम एतद्वारा यह सत्यापित करता (करते) हूं (हैं) कि कथित उद्देश्य के लिए ली गई सब्सिडी एटफस पर सरकारी संकल्प में उल्लिखित अनुसार मानक प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए ही उपयोग की जाएगी। यदि कंपनी/यूनिट के दस्तावेजों और परिसंपत्तियों के सत्यापन के दौरान अथवा बाद में किसी स्तर पर कोई अंतर पाया जाता है, तो एटफस के अंतर्गत लिया गया लाभ बैंक(कों)/सरकार को इसकी प्राप्ति की तिथि से लागू दंडात्मक व्याज सहित लौटा दिया जाएगा।
- मैं/हम उपर्युक्त सूचना में चूक/गलत सूचनाओं, यदि कोई, के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँगा (रहेंगे)। यदि उपर्युक्त दी गई सूचना में कोई अंतर होता है, मैं/हम एतद्वारा इसकी सूचना बैंक/सरकार को देंगे।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें-----आरआरटफ्स और एटफ्स के अंतर्गत आवेदन करने की तिथि को रु.----- की राशि के लिए पूर्व अधिकृत किया गया है तथा आरआरटफ्स और एटफ्स के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में रु.----- प्राप्त किए गए हैं।

7. मैं/हम-----यह वचन देते हैं कि यूनिट न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संचालित की जाएगी और इस आवधिक ऋण की मोराटोरियम अवधि सहित न्यूनतम पुनर्भुगतान अवधि 3 वर्ष है।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

दिनांक :

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पद)

नोट :

कृपया अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर सहित कंपनी/यूनिट की सील/रबड़ की मोहर लगाएं

विशिष्ट विवरण सहित सभी मदे भरें।

प्रपत्र-2

ऋण प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र

[जहां कहीं लागू हो कृपया सही विकल्प पर (✓) करें]

(ऋण प्रदाता एजेंसी की शाखा द्वारा भरा जाना है)

1.	क्या प्रपत्र-1 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सही है और दस्तावेजों से सत्यापित होती है	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
2.	बैंक/संस्था द्वारा अवधि ऋण आवेदन की प्राप्ति की तिथि	_____ / _____ / _____ (दिन/माह/वर्ष)
3.	प्रत्यायोजित प्राधिकारी (बोर्ड/ऋण समिति आदि) द्वारा अवधि ऋण की स्वीकृति की तिथि	_____ / _____ / _____ (दिन/माह/वर्ष)
4.	कंपनी/फर्म को स्वीकृति की सूचना की तिथि	_____ / _____ / _____ (दिन/माह/वर्ष)
5.	क. कुल स्वीकृत अवधि ऋण	रु. _____
	ख. प्रवर्तकों का अंशदान	रु. _____ ; परियोजना लागत का ___%
6.	परियोजना पूरा होने की अनुमानित तिथि	_____ / _____ / _____ (दिन/माह/वर्ष)
7.	क्रियान्वयन अवधि	_____ वर्ष _____ माह
8.	प्रथम संवितरण की तिथि	_____ / _____ / _____ (दिन/माह/वर्ष)
9.	क. पुनर्भुगतान शुरू होने की तिथि	_____ / _____ / _____ (दिन/माह/वर्ष)
	ख. पुनर्भुगतान खत्म होने की तिथि	_____ / _____ / _____ (दिन/माह/वर्ष)
	ग. पुनर्भुगतान अवधि	_____ वर्ष _____ माह
	[अर्थात मद सं. 9ख - मद सं. 9क]	

10	अवधि ऋण खाता संख्या		
11	क. क्या अवधि ऋण अन्य बैंकों/संस्थाओं द्वारा शेयर किया जा रहा है?	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
	ख. यदि हां, शेयरिंग पैटर्न दर्शाएं	बैंक/संस्था का नाम	राशि (रु.)
		कुल	
	ग. कंसोर्टियम वित्त पोषण के मामले में अग्रणी बैंक का नाम?		

सत्यापित किया जाता है कि:

प्रपत्र 1 के भाग-I, भाग-II और भाग-III में आवेदक द्वारा दी गई सूचना हमारे बैंक के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर सही पाई गई है।

यह भी सत्यापित किया जाता है कि इस आवधिक ऋण की मोराटोरियम अवधि सहित न्यूनतम पुनर्भुगतान अवधि 3 वर्ष है।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

दिनांक :

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पद)

प्रपत्र-3

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा यूआईडी जारी करने के लिए जांच सूची के लिए प्रपत्र (क्र.सं. 1 से 20 प्रणाली जनित है)

1.	i) आवेदन की स्थिति ii) त्रुटि की तिथि और समय iii) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा त्रुटि का कारण	(प्रणाली जनित)
2.	i) पुनः आवेदन की तिथि (तिथि और समय) (ऋण प्रदाता एजेंसी द्वारा यूआईडी आवेदन देते समय स्वतः जनित) ii) नोडल एजेंसी द्वारा अनुपालन - टिप्पणी	(प्रणाली जनित)
3.	अनुमोदन की तिथि (तिथि और समय) (ऋण प्रदाता एजेंसी द्वारा यूआईडी आवेदन देते समय स्वतः जनित)	(प्रणाली जनित)
4.	अनुमोदन/प्रतिक्षा सूची संख्या	(प्रणाली जनित)
5.	यूनिट का नाम और पता	(प्रणाली जनित)
6.	यूनिट का ई-मेल आईडी	(प्रणाली जनित)
7.	पैन नम्बर	(प्रणाली जनित)
8.	अवधि ऋण की स्वीकृति की तिथि	(प्रणाली जनित)
9.	परियोजना लागत रूपए में	(प्रणाली जनित)
10.	दावा किया गया क्षेत्र	(प्रणाली जनित)
12.	परियोजना पूरा होने की अनुमानित तिथि	(प्रणाली जनित)
13.	बैंक का नाम और पता, शाखा कोड	(प्रणाली जनित)
14.	स्वीकृत अवधि ऋण रूपए में	(प्रणाली जनित)

15.	प्रवर्तक का अंशदान रूपए में	(प्रणाली जनित)
16.	अवधि ऋण खाता संख्या	(प्रणाली जनित)
17.	पात्र मशीनों की मूल लागत रूपए में	(प्रणाली जनित)
18.	पात्र मशीनों पर पात्र सब्सिडी मूल्य रूपए में	(प्रणाली जनित)
19.	आरआरटफस के अंतर्गत अधिकृत-पूर्व एवं ली गई टीयूएफएस सब्सिडी	(प्रणाली जनित)
20.	एटफस के अंतर्गत अधिकृत-पूर्व कुल सब्सिडी रूपए में	(प्रणाली जनित)
21.	क्या एक ही पैन वाला एक जैमा आवेदन और ऑनलाइन प्रणाली में स्वीकृत किया गया एक जैसा अवधि ऋण है (स्वतः)	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
22.	क्या आवेदन अवधि ऋण की स्वीकृति की तिथि से छह महीने के भीतर जमा करा दिया गया है	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
23.	क्या चयनित किया गया क्षेत्र सही है	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
24.	क्या सब्सिडी का अपेक्षित प्रकार सही है	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
25.	क्या निर्दिष्ट की गई सब्सिडी सही है	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
26.	क्या क्षेत्र एवं मशीन डीपीआर से मिलान कर रही है (कार्यकारी सार, परियोजना की लागत एवं वित्त पोषण का सार्धन)	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
27.	क्या पैन की प्रतिलिपि संलग्न है और आवेदन में पैन के विवरण से मिलान कर रही है	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
28.	क्या आवेदक द्वारा 'कोई बहु वित्त प्रमाणपत्र नहीं' संलग्न किया गया है	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
29.	आवेदन की जांच की गई नाम एवं पदनाम तिथि एवं समय	
30.	आवेदन संस्थापित किया गया नाम एवं पदनाम तिथि एवं समय	

प्रपत्र-4

एटीयूएफएस के अंतर्गत आवेदक द्वारा संस्थापित मशीनों के लिए संयुक्त निरीक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

1.	टफस संदर्भ संख्या	(प्रणाली से स्वतः जनित)
2.	यूआईडी संख्या एवं तिथि	(प्रणाली से स्वतः जनित)
3.	यूनिट की कंपनी का पंजीकरण विवरण अथवा उपर्युक्त प्राधिकारी के साथ पंजीकरण विवरण	कृपया एक प्रति अपलोड करें
4.	नए बिजली बिल की प्रतिलिपि	कृपया एक प्रति अपलोड करें
5.	साझीदार फर्म के मामले में साझीदार डीड	कृपया एक प्रति अपलोड करें

6	मालिक/साझीदार/सहकारी फर्म के लिए लीज डीड / संपत्ति दस्तावेज						कृपया एक प्रति अपलोड करे				
7	अवधि ऋण का तिथि-वार वास्तविक संवितरण (कृपया बैंक का प्रमाणित विवरण भी अपलोड किया जाए)										
8	मार्जिन मनी और अवधि ऋण के लिए बैंक का विवरण						कृपया एक प्रति अपलोड करे				
9	मशीन (नों) के वाणिज्यिक बीजक (कों) की प्रतिलिपि (यां) (यूनिट को ए-टफ्स में बीजक संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना है और इसे अपलोड भी करना है)										
यूआईडी प्राप्त करते समय अनुमानित मशीन का नाम	संख्या	अनुमानित मूल लागत रूपए में	खरीदी गई एवं स्थापित की गई ¹ वास्तविक मशीन	वास्तविक सं.	वाणिज्यिक बीजक के अनुसार वास्तविक मूल लागत रूपए में	विनिर्माता का नाम	विनि- र्माण का वर्ष	वाणि- ज्यिक बीजक सं.	आयात पत्र	उद्गम देश	
	i.										
	ii										
	iii										
	iv										
	v										
10	मशीनरी बदलने का औचित्य (यदि वास्तविक मशीन अनुमानित मशीन से अलग है)										
11	आयात पत्र संख्या एवं तिथि (आयातित मशीन(नों) के मामले में)						कृपया एक प्रति(यां) भी अपलोड करे				
12	टीआर-6 चालान (भुगतान की गई सीमा शुल्क के लिए) (आयातित मशीन(नों) के मामले में)						कृपया एक प्रति(यां) भी अपलोड करे				
13	बैंक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उद्गम देश (आयातित मशीन(नों) के मामले में)						कृपया एक प्रति(यां) भी अपलोड करे				
14	लदान बिल संख्या एवं तिथि (आयातित मशीन(नों) के मामले में)						कृपया एक प्रति(यां) भी अपलोड करे				
15	बैंक द्वारा प्रमाणित एलसी (आयातित मशीन(नों) के मामले में)						कृपया एक प्रति(यां) भी अपलोड करे				
16	बैंक द्वारा प्रमाणित डेबिट सूचना (आयातित मशीन(नों) के मामले में)						कृपया एक प्रति(यां) भी अपलोड करे				
17	बैंक द्वारा प्रमाणित स्विफ्ट/टेलीग्राफिक ट्रांसफर रसीद (आयातित मशीन(नों) के मामले में)						कृपया एक प्रति(यां) भी अपलोड करे				
18.	प्राप्त किए गए यूआईडी के अंतर्गत शामिल सभी मशीनों की स्थापना पूरा करने की तिथि:										
19.	टफ्स आवेदक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत करने की तिथि						(प्रणाली से स्वतः जनित)				
20.	वास्तविक रोजगार सृजित						कुल:				
	i. पुरुष:			ii. महिला			i ii				
	iii. अजा, अज्जा			iv अल्पसंख्यक			iii iv				

नोट: बैंक संचालन से संबंधित सभी दस्तावेज संबंधित बैंक द्वारा पृष्ठांकन किया जाना चाहिए जहां से अवधि ऋण की सुविधा ली गई है। प्रमाणित किया जाता है कि:

इस प्रपत्र में प्रस्तुत की गई सूचना सही है और यूनिट के पास उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है जिसे किसी भी समय अधिकृत अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

दिनांक :

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम)

नोट : कृपया अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ कंपनी/यूनिट की सील/रबड़ की मोहर लगाई जाए।

विशेष विवरण सहित सभी मर्दे भरी जाएं।

प्रपत्र-5

जेआईटी के समय यूनिट द्वारा की जाने वाली घोषणा

(यूनिट के पत्रशीर्ष पर)

8. यह प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें-----आरआरटफस और एटफस तथा एटफस के अंतर्गत आवेदन करने की तिथि को रु.----- की राशि के लिए पूर्व अधिकृत किया गया है तथा आरआरटफस और एटफस के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में रु.----- प्राप्त किए गए हैं।
9. मैं/हम _____ (लाभार्थी यूनिट का नाम) एतद्वारा यह सत्यापित करता (करते) हूं (हैं) कि कोई मशीनरी अथवा उसका कोई हिस्सा जिसके लिए टीयूएफएस के अंतर्गत दावा किया जा रहा है/दावा किया गया है, इस बैंक और अन्य कोई बैंकों/ऋणप्रदाता एजेंसियों/वित्तीय संस्थानों से एक से अधिक बार ऋण निधि नहीं दी गई है। विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (परिशिष्ट-1) के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रपत्र में) की एक प्रति अपलोड की गई है जिसे सब्सिडी संबंधी दावे के समय मूल रूप में जेआईटी को प्रस्तुत किए जाएंगे।
10. मैं/हम एतद्वारा यह सत्यापित करता (करते) हूं (हैं) कि कथित उद्देश्य के लिए तो गई सब्सिडी एटफस पर सरकारी संकल्प में उल्लिखित अनुसार मानक प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए ही उपयोग की जाएगी। यदि कंपनी/यूनिट के दस्तावेजों और परिसंपत्तियों के सत्यापन के दौरान अथवा बाद में किसी स्तर पर कोई अंतर पाया जाता है, तो एटफस के अंतर्गत लिया गया लाभ बैंक(ों)/सरकार को इसकी प्राप्ति की तिथि से लागू दंडात्मक व्याज सहित लौटा दिया जाएगा।
11. मैं/हम-----यह वचन देते हैं कि यूनिट न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संचालित की जाएगी और इस आवधिक ऋण की मोराटोरियम अवधि सहित न्यूनतम पुनर्भुगतान अवधि 3 वर्ष है।

(हस्ताक्षर)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पद)

प्रपत्र-6

संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा एटीयूएफएस के अंतर्गत मशीनरी की स्थापना और शुरुआत पर प्रमाणपत्र

1. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय में यूनिट के आवेदन की प्राप्ति की तिथि :
2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा आबंटित की गई यूआईडी संख्या एवं तिथि :
3. निरीक्षण की तिथि :

4. निरीक्षण की गई यूनिट का नाम और पिन कोड सहित पता तालुका/तहसील/मंडल: ज़िला: राज्य: पिनकोड़:	
दूरभाष/मोबाइल	
फैक्स	
ई-मेल आईडी	
यूनिट का पैन नं.	
एसएसआई पंजीकरण/ईएम की सं. और तिथि	
संपर्क व्यक्ति का नाम संपर्क नं.:	

	क्या यूनिट यूआईडी आवेदन में उल्लिखित पते पर कार्यशील पाई गई।	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
5.	यदि नहीं, तो यूनिट का वास्तविक पता तालुका/तहसील/मंडल: जिला: राज्य: पिनकोड़:	
6.	क) क्या यूनिट द्वारा प्रपत्र 1 में प्रस्तुत और बैंक द्वारा प्रमाणित किया गया ब्यौरा सही पाया गया है अथवा नहीं। ख) यदि नहीं कृपया उल्लेख करें ग) क्या प्रपत्र 5 में घोषणा यूनिट से प्राप्त की गई है और संलग्न की गई है।	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
7.	क्षेत्र	
8	क. क्या प्रपत्र 4 में निर्दिष्ट की गई सभी मशीनें स्थापित की हुई पायी गयी और एटफस के अंतर्गत पात्र हैं। ख. यदि नहीं कृपया उल्लेख करें	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
9	क. क्या प्रपत्र 4 में निर्दिष्ट की गई सभी मशीनों पर वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा आबंटित किया गया एमआईसी कोड पाया गया है। ख. यदि नहीं कृपया उल्लेख करें	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
10.	एटफस के अंतर्गत निर्धारित की गई पात्र मशीनरी की कुल लागत प्रवर्तकों का अंशदान संवितरित किया गया लोन	रु. _____ रु. _____ (____ %) रु. _____ (____ %)
	एटफस के अंतर्गत संस्थापित/शुरू की गई मशीनें (परिशिष्ट में दिए गए अनुसार मशीन का विवरण प्रस्तुत किया जाए)	15%/ 10%
	क्या जेआईटी ने सब्सिडी जारी करने की सिफारिश की है	हां/ नहीं
	यदि हां, तो पात्र निवेश	रु. _____
	यदि नहीं, उसका कारण	
11.	पात्र सब्सिडी राशि (सीआईएस)	रु. _____
12.	रोजगार	

मालिक / यूनिट के अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर सहित सील (जेआईटी सदस्यों के नाम एवं पदनाम तथा हस्ताक्षर)

प्रपत्र-6 के लिए परिशिष्ट

एटीयूएफएस के अंतर्गत मशीनरी की स्थापना एवं शुरुआत पर प्रमाणपत्र

मशीन-वार विवरण एवं व्यौरा

मशीन का प्रकार	
एटफस अनुबंध के अनुसार मशीन संदर्भ क्रमांक संख्या	
आयातित अथवा स्वदेशी	
मशीनों की संख्या	
मशीन विनिर्माता का नाम एवं पता	
मशीन शुरू करने की तिथि	
निर्मित	
मॉडल	
विनिर्माण का वर्ष मशीन क्रमांक संख्या	
मशीन की विशिष्टताएं	
उद्गम देश (आयातित के मामले में)	
निर्यातक देश (आयातित के मामले में)	
वाणिज्यिक बीजक संख्या एवं तिथि तथा मशीन की कीमत (प्रतियां संलग्न की गई)	
लदान बिल संख्या एवं तिथि (प्रतियां संलग्न की गई)	
आयात पत्र संख्या एवं तिथि (प्रतियां संलग्न की गई)	
ई-कॉमर्स पोर्टल (आईसगेट) में आयात पत्र का ऑनलाइन सत्यापन	
किए गए भुगतान का विवरण (प्रतियां संलग्न की गई) भुगतान का माध्यम (एलसी/स्विफ्ट /टीटी/सीएडी/आरटीजीएस/एनईएफटी चेक/मांगपत्र/पोस्टल ॲडर आदि) भुगतान की राशि एवं तिथि	

जेआईटी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं मुहर की फोटो प्रति संलग्न और आवेदक परियोजना के अंतर्गत किए गए दावे की स्थापित मशीन दर्शाएं			
क्या मशीनें वाणिज्यक बीजक में उल्लिखित विशिष्टताओं के अनुसार स्थापित/शुरू की गई हैं।	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	
जेआईटी की टिप्पणी, यदि कोई हो			

(जेआईटी सदस्यों के नाम एवं पदनाम तथा हस्ताक्षर)

(कंपनी/फर्म के हस्ताक्षर)

प्रपत्र-7

दावे संबंधी प्रक्रिया के लिए प्रपत्र

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय में यूनिट के आवेदन की प्राप्ति की तिथि :

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा आबंटित की गई यूआईटी संख्या एवं तिथि :

निरीक्षण की तिथि:

1	निरीक्षण की गई यूनिट का नाम और पिन कोड सहित पता तालुका/तहसील/मंडल: जिला: राज्य: पिनकोड़:	
	दूरभाष/मोबाइल	
	फैक्स	
	ई-मेल आईटी	
	यूनिट का पैन नं.	
	एसएसआई पंजीकरण/ईएम की सं. और तिथि	
	संपर्क व्यक्ति का नाम संपर्क नं.:	
2	जेआईटी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन की तिथि	____ / ____ / ____ (दिन / माह/ वर्ष)
3	ऑनलाइन प्रणाली में जेआईटी रिपोर्ट को अपलोड करने की तिथि	____ / ____ / ____ (दिन / माह/ वर्ष)
4	क) क्या यूनिट द्वारा प्रस्तुत की गई और बैंक द्वारा प्रमाणित किया गया अन्य सभी विवरण जेआईटी द्वारा सही पाया गया है अथवा नहीं।	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>

	ख) यदि नहीं कृपया उल्लेख करें				
	ग) क्या इस अंतर का समाधान किया गया /जायज ठहराया गया।	हां	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>
5	क. क्या प्रपत्र 4 में निर्दिष्ट की गई सभी मशीनें स्थापित की हुईं पायी गयी और जेआईटी द्वारा एटफस के अंतर्गत पात्र घोषित की गई हैं।	हां	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>
	ख. यदि नहीं कृपया उल्लेख करें				
6	क. क्या प्रपत्र 4 में निर्दिष्ट की गई सभी मशीनों पर वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा आबंटित किया गया एमआईसी कोड जेआईटी द्वारा पाया गया है।	हां	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>
	ख. यदि नहीं कृपया उल्लेख करें				
7	जेआईटी के अनुसार एटफस के अंतर्गत पात्र पाई गई मशीन की कुल लागत संबिंदी की राशि 15% अथवा 10% की दर से जारी की जानी है	रु.			
8	तकनीकी अधिकारी सहायक निदेशक उप निदेशक निदेशक संयुक्त वस्त्र आयुक्त / अपर वस्त्र आयुक्त वस्त्र आयुक्त				

प्रपत्र- 8

दावा जारी करने के लिए प्रपत्र

वस्त्र आयुक्त (सक्षम प्राधिकारी) के अनुमोदन की तिथि	
वस्त्र मंत्रालय को चालान प्रस्तुत करने की तिथि	
संयुक्त सचिव/अपर सचिव (टीयूएफएस)- वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदन की तिथि	
आंतरिक वित्त विंग - वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदन की तिथि	
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तिथि	
भुगतान एवं लेखा अधिकारी (वस्त्र) को बिल भेजने की तिथि	
लाभार्थी के खाते/बैंक में जमा होने की तिथि	

प्रपत्र-9

भाग I (लाभग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

संबंधित ऋणदाता एजेंसी के माध्यम से एटीयूएफएस के अंतर्गत जारी यूआईडी रद्द करना

नोट : दूसरी ऋण प्रदाता एजेंसी में परिवर्तन के समय इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई ऋणप्रदाता एजेंसी एटीयूएफएस के अंतर्गत शामिल है।

1.	यूआईडी संख्या	स्वतः तैयार की गई
2.	यूआईडी अनुमोदन की तारीख	स्वतः तैयार की गई
3.	इकाई का नाम	स्वतः तैयार की गई
4.	इकाई का पता	स्वतः तैयार की गई
5.	इकाई की ई-मेल आईडी	स्वतः तैयार की गई
6.	पैन संख्या	स्वतः तैयार की गई
7.	आवधिक ऋण स्वीकृति की तारीख	स्वतः तैयार की गई
8.	परियोजना लागत रूपए में	स्वतः तैयार की गई
9.	दावा किया गया क्षेत्र	स्वतः तैयार की गई
10.	ऋणदाता एजेंसी का नाम	स्वतः तैयार की गई
11.	ऋणदाता एजेंसी का पता	स्वतः तैयार की गई
12.	ऋणदाता एजेंसी का शाखा कोड	स्वतः तैयार की गई
13.	स्वीकृत आवधिक ऋण रूपए में	स्वतः तैयार की गई
14.	प्रमोटर का अंशदान रूपए में	स्वतः तैयार की गई
15.	आवधिक ऋण का खाता संख्या	स्वतः तैयार की गई
16.	यूआईडी के अनुसार पूर्व प्राधिकृत कुल सब्सिडी मूल्य रूपए में	स्वतः तैयार की गई
17.	जारी की गई यूआईडी रद्द किए जाने का कारण	

प्रमाणित किया जाता है कि:

इस प्रपत्र में दी गई सूचना सही हैं एवं सत्य हैं और मैं/हम _____ वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा जारी की गई उक्त यूआईडी को निरस्त करने का अनुरोध करते हैं। इसके अलावा मैं/हम वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा जारी की गई उपरोक्त यूआईडी के संबंध में कभी किसी सब्सिडी का पूर्ण अथवा आंशिक दावा नहीं करेंगे।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

दिनांक

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम एवं पदनाम)

नोट : कृपया प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर के साथ कंपनी/इकाई की सील/रबर स्टैंप लगाएं।

प्रपत्र-9 (जारी)

भाग II (ऋणदाता द्वारा जारी की जाए)

संबंधित ऋणदाता एजेंसी द्वारा एटीयूएफएस के अंतर्गत जारी यूआईडी रद्द करना

प्रमाणित किया जाता है कि :

आवेदक द्वारा प्रपत्र-8 के भाग-I में दी गई सूचना हमारे बैंक के पास उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर सही पाई गई है।

प्रपत्र-8 के भाग-I में आवेदक इकाई द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों से, मैं/हम _____ एतद्वारा आवेदक इकाई को वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा जारी यूआईडी संख्या रद्द करने की सिफारिश करते हैं।

प्रपत्र-10

एटफस के क्रियान्वयन से संबंधित ऑनलाइन शिकायत के लिए प्रपत्र

i.	शिकायत संख्या (स्वतः जनित)	
ii.	शिकायत तिथि (स्वतः जनित)	
iii.	आवेदक यूनिट का नाम	
iv.	आवेदक यूनिट का पता	
v.	दूरभाष	
vi.	फैक्स	
vii.	ई-मेल आईडी	
viii.	संपर्क अधिकारी का नाम	
ix.	संपर्क अधिकारी का पदनाम	
x.	मोबाइल	
xi.	फैक्स	
xii.	ई-मेल आईडी	
xiii.	ऋणदाता एजेंसी का नाम	
xiv.	ऋणदाता एजेंसी का पता	
xv.	यूआईडी नं.	
xvi.	यूआईडी जारी करने की तिथि	
xvii.	अवधि ऋण की राशि	
xviii.	क्षेत्र	
xix.	एटफस के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायत का विवरण	
xx.	अतिरिक्त विवरण, यदि कोई	
xxi.	सहायक दस्तावेजों की प्रतियां	कृपया स्कैन की गई प्रति अपलोड करें

स्थान:

तिथि:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

प्रपत्र-11

एटफस के अंतर्गत नीति संबंधी मामलों और उनका स्पष्टीकरण से संबंधित ऑनलाइन शिकायत के लिए प्रपत्र

i.	शिकायत संख्या (स्वतः जनित)	
ii.	शिकायत तिथि (स्वतः जनित)	
iii.	आवेदक यूनिट का नाम	
iv.	आवेदक यूनिट का पता	
v.	दूरभाष	
vi.	फैक्स	
vii.	ई-मेल आईडी	

viii.	संपर्क अधिकारी का नाम	
ix.	संपर्क अधिकारी का पदनाम	
x.	मोबाइल	
xi.	फैक्स	
xii.	ई-मेल आईडी	
xiii.	ऋणदाता एजेंसी का नाम	
xiv.	ऋणदाता एजेंसी का पता	
xv.	यूआईडी नं.	
xvi.	यूआईडी जारी करने की तिथि	
xvii.	अवधि ऋण की राशि	
xviii.	क्षेत्र	
xix.	एटप्स के अंतर्गत नीतिगत मामले और उनका स्पष्टीकरण से संबंधित ऑनलाइन शिकायत का विवरण	
xx.	अतिरिक्त विवरण, यदि कोई	
xxi.	सहायक दस्तावेजों की प्रतियां	कृपया स्कैन की गई प्रति अपलोड करें

स्थान:

तिथि:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2015

संकल्प

सं.8-1/2015-संस्कृत-II—इस मंत्रालय के दिनांक 27.08.2015 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत परिषद् का पुनर्गठन करते हुए अध्यक्ष तथा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि परिषद् के गठन को संशोधित करके सहयोजित कुलाधिपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति को पदेन सदस्य श्रेणी के अंतर्गत लाया जाए। यह निर्णय भी लिया गया है कि परिषद् का अध्यक्ष किसी अन्य संस्कृत विद्वान को परिषद् की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकता है।

2. तदनुसार श्री एन.गोपालस्वामी, कुलाधिपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को सहयोजित तथा श्री चमु कृष्ण शास्त्री, वरिष्ठ परामर्शदाता (भाषाएं) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय संस्कृत परिषद् में विशेष अतिथि के रूप में नामित किया गया है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सुखबीर सिंह संधु
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2016

संकल्प

सं. एफ. 4-3/2015-यू-3—जबकि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद का अंतिम गठन 15 अक्टूबर, 2012 को किया गया था और परिषद की अवधि 14 अक्टूबर, 2015 को समाप्त हो गई है, केन्द्र सरकार ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के संगम ज्ञापन

के नियम 3 और नियमावली के अंतर्गत भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष और सदस्य सचिव जिनका कार्यकाल नीचे दिया गया है, को छोड़कर तीन वर्ष का होगा। परिषद का तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठन किया जाता है:-

क. अध्यक्ष प्रो. एस.आर. भट्ट (20 अक्टूबर, 2015 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए)

ख. विभिन्न संगठनों से आठ प्रतिनिधि:-

- i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि
- ii. भारतीय दार्शनिक कांग्रेस के दो प्रतिनिधि
- iii. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि
- iv. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि
- v. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का एक प्रतिनिधि
- vi. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि
- vii. वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग

ग. भारत सरकार द्वारा नामित 12 सदस्य:-

- i. प्रो. कुमुम जैन, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र, राजस्थान विश्वविद्यालय
- ii. प्रो. जटाशंकर तिवारी, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
- iii. प्रो. एक्स.पी. माओ, प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय
- iv. डॉ. के.अरविंद राव, निदेशक, अद्वैत अकादमी, हैदराबाद
- v. प्रो. एस.आर. लीला, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, संस्कृत, बैंगलोर विश्वविद्यालय
- vi. प्रो. वी. कुटुम्बा शास्त्री, पूर्व कुलपति, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय
- vii. प्रो. आर.सी. सिन्हा, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र, पटना विश्वविद्यालय
- viii. प्रो. धर्मानन्द शर्मा, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय
- ix. प्रो. नरेश कुमार अम्बास्था, विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र, पीकेआरएम कॉलेज, धनबाद
- x. प्रो. हरेराम त्रिपाठी, प्रोफेसर, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय) दिल्ली
- xi. प्रो. ओम प्रकाश पांडे, पूर्व विभागाध्यक्ष, संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएं, लखनऊ विश्वविद्यालय
- xii. डॉ. राजाराम शुक्ला, प्रोफेसर वैदिक दर्शन, बीएचयू वाराणसी

घ. परिषद द्वारा चार प्रख्यात दर्शनशास्त्रियों को सहयोजित किया जाएगा।

ड. उत्तर प्रदेश सरकार के दो प्रतिनिधि; और

च. प्रो. मानेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य सचिव, आईसीपीआर (उन्हें दिनांक 18.11.2013 से तीन वर्ष की अवधि के लिए आईसीपीआर का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था।)

आदेश

एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रवीण कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 29th February 2016

RESOLUTION

No.6/19/2013-TUFS—The guidelines containing financial and operational parameters and implementation mechanism for Revised Restructured Technology Upgradation Fund Scheme (RRTUFS) were notified vide this Ministry's Resolution of even number dated 04.10.2013. In partial modification of the said guidelines, the following amendments are made for considering the UID applications pending since 17.09.2014 until 12.01.2016:

1. FINANCIAL PARAMETERS

- 1.1. Budget Allocation: The budget allocation under the scheme for issuance of UIDs for pending Unique Identification Number (UID) applications under Revised Restructured Technology Upgradation Fund Scheme (RRTUFS) which had been uploaded in the i-TUFS software since 17.09.2014 until 12.01.2016 midnight is Rs. 4005 crore including administrative cost @ 1% of said allocation.
- 1.2. An amount of Rs. 8666 crore is also earmarked to consider the claims against the committed liabilities of the sanctioned cases under erstwhile Modified TUFS (List-I & List-II), RTUFS and RRTUFS upto 31st March 2022. The committed liabilities of the cases sanctioned under erstwhile Modified TUFS (List-I & List-II) and RTUFS are under re-conciliation.
- 1.3. It is reiterated that the total subsidy outflow on the Standalone Spinning Sector would not exceed 26%.

2. OPERATIONAL PARAMETERS:

- 2.1. An i-TUFS software has been put in place. The lending agencies and individual applicants had uploaded the details of term loan sanctioned under RRTUFS from 17.09.2014 to 12.01.2016 midnight for issuance of UID under RRTUFS.
- 2.2. Such applications for issuance of UID numbers will be considered on a first-come-first-served basis, as per the sequence in which they are received in the i-TUFS software on the central server at the Office of the Textile Commissioner, subject to eligibility and availability of funds under the scheme.
- 2.3. With reference to para V. 1(vi) of the Resolution ibid on RRTUFS, no change of segment and loan amount will be allowed in respect of UID applications already uploaded and pending from 17.09.2014 to 12.01.2016 midnight.
- 2.4. The correctness of the information/documents submitted for obtaining UID number will be the responsibility of the applicant and the lending agency(ies) concerned.
- 2.5. Installation of all machinery by the unit:
 - 2.5.1. The applicant should ensure that make, year of manufacture, name of the manufacturer and serial number of all the eligible machinery are clearly inscribed on the machine(s). Moreover, a "Machine Identification Code" (MIC) will be allotted by the Textile Commissioner, which will be a unique identification number for each machine procured under the scheme. This MIC shall be mandatorily inscribed on the machinery and shall be verified during the physical verification at different times.
 - 2.5.2. Through the MIC issued, the details could be deduced regarding the textile segment, the country code of the manufacturer, the state/province code of the place where machinery will be installed, the machine manufacturer code (as indicated in scheme), an authorized agent code of the machine manufacturer, the commercial invoice number, the bill of entry number and the bill of lading number (in case of imported machinery), the machine serial number etc.

3. PROVISIONS FOR CANCELLATION OF UID:

- 3.1. UID issued under the scheme shall be cancelled in cases where:
 - 3.1.1. The applicant decides not to avail benefits under the scheme for any reason for which he/she may upload request for cancellation of the issued UID through concerned lending agency using i-TUFS software. This request should be made in the prescribed Format-1.
 - 3.1.2. The application gets rejected at any stage, the UID shall be suomoto cancelled.

4. SAFEGUARDS AGAINST MISUTILIZATION:

To prevent misutilization of the subsidy being provided under the scheme, following safeguards are put in place:

- (a) It is made mandatory that make, year of manufacture, name of the manufacturer and serial number of all the eligible machinery and MIC number allotted by the Textile Commissioner are clearly inscribed on the machine(s).
- (b) A Joint Inspection Team (JIT) to be constituted by the Textile Commissioner will physically verify the machinery installed/assets created by the unit as stratified sample cases under the scheme while examining claims for reimbursement.

5. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM:

- 5.1. All grievances received in prescribed format related to implementation of this scheme shall be redressed by a Grievance Committee set up under the chairpersonship of the Textile Commissioner with the representatives from the Ministry of Textiles, Lending Agencies and industry associations etc.
- 5.2. The grievances related to policy matter and interpretations thereof shall be required to be submitted in the prescribed format to the Secretary, Ministry of Textiles, Government of India who will redress the same.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that copies of the Resolution may be communicated to the concerned Ministries/Departments/Organizations.

PUSHPASUBRAHMANYAM
Additional Secy.

FORMAT-1

Part I (To be submitted by beneficiary)

CANCELLATION OF ISSUED UID UNDER ATUFS THROUGH CONCERNED LENDING AGENCY

1.	UID Number	Auto generated
2.	UID Approval date	Auto generated
3.	Name of the unit	Auto generated
4.	Address of the unit	Auto generated
5.	e-mail ID of the unit	Auto generated
6.	PAN number	Auto generated
7.	Date of sanction of term loan	Auto generated
8.	Project cost in Rs.	Auto generated
9.	Segment claimed	Auto generated
10.	Lending Agency name	Auto generated
11.	Lending Agency address	Auto generated
12.	Lending Agency Branch Code	Auto generated
13.	Term loan Sanctioned in Rs.	Auto generated
14.	Promoter's Contribution in Rs.	Auto generated
15.	Term Loan account number	Auto generated
16.	Total Subsidy value pre authorized as per UID in Rs.	Auto generated
17.	Reason for Cancellation of issued UID	

Certified that:

The information furnished in this format is true & correct and I/We ----- request the cancellation of the aforesaid UID issued by Office of the Textile Commissioner. Further I/We ----- shall not claim any subsidy full or in part thereof with respect to the aforesaid UID issued by Office of the Textile Commissioner, at any time.

Place: _____ (Signature)

Date : _____ (Name and designation of the authorised signatory)

Note : Please affix seal/rubber stamp of the Company/Unit along with signature of the authorized signatory.

Part II (To be submitted by Lending Agency)

CANCELLATION OF ISSUED UID UNDER ATUFS THROUGH CONCERNED LENDING AGENCY

Certified that:

The information furnished in by the applicant in PART—I of FORMAT-1 is found correct on the basis of records available with our bank.

In view of reasons submitted by the applicant unit in the Part I of Format 8, I/We ----- hereby recommend for the Cancellation of UID number issued by Office of the Textile Commissioner to the applicant unit.

Place: _____ (Signature)

Date : _____ (Name and designation of the authorised signatory with seal)

RESOLUTION

No.6/5/2015-TUFS—The Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) has been notified by the Ministry of Textiles vide Resolution of even number dated 13.01.2016. In accordance to the said Resolution, the Guidelines of ATUFS i.e. financial and operational parameters and implementation mechanism for ATUFS during its implementation period from 13.01.2016 to 31.03.2022 are laid down as under:

1. OBJECTIVE:

- 1.1. In order to promote ease of doing business in the country and achieve the vision of generating employment and promoting exports through "Make in India" with "Zero effect and Zero defect" in manufacturing, it has been decided that the Government would provide credit linked Capital Investment Subsidy (CIS) under Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS).
- 1.2. The scheme would facilitate augmenting of investment, productivity, quality, employment, exports along with import substitution in the textile industry. It will also indirectly promote investment in textile machinery (having benchmarked technology) manufacturing.

2. Definitions under the Scheme

- 2.1 Technology Upgradation would mean induction of state-of-the-art or near-state-of-the-art technology by the textile industry. Technology levels of the machinery will be updated and specified annually by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC). Machinery with technology levels lower than that specified, are not permitted for funding under the ATUFS Scheme.
- 2.2 Capital Investment Subsidy (CIS) would mean the subsidy at the prescribed rate for the segment on investment made in 'Fixed Capital Investment' for purchases of the benchmarked new machinery for each segment under this scheme, which will be determined on the basic cost of the benchmarked machinery after its installation by the entity.
- 2.3 Garment/Apparel/Made-ups would mean wearable or non-wearable stitched fabrics of which at least two sides of the fabrics are stitched using sewing machinery.
- 2.4 Technical Textiles would mean textile materials and products used primarily for their technical performance and functional properties rather than their aesthetic or decorative characteristics, where function is the primary criterion. Technical textiles include textiles for automotive applications, Medical Textiles, Geotextiles, Agrotextiles, Protective Clothing, Pack Tech etc.
- 2.5 ATUFS benefit is available for the benchmarked machinery under the scheme covering the following activities:-
 - (a) Weaving, Weaving Preparatory and knitting
 - (b) Processing of fibres, yarns, fabrics, garments and made-ups

- (c) Technical textiles
- (d) Garment/made-up manufacturing
- (e) Handloom Sector
- (f) Silk Sector
- (g) Jute Sector.

3. ELIGIBILITY CRITERIA FOR GRANT OF CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY

3.1 The Capital Investment Subsidy under ATUFS will be available for investment on eligible benchmarked machinery in the specified segments. Eligible benchmarked machinery will be updated and specified annually as on 1st April by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC). The Textile Commissioner shall notify the list of eligible benchmarked machinery after approval of the TAMC. Machinery with technology levels lower than those specified under the scheme will not be eligible for subsidy benefits. Make and Year of manufacture of all the eligible benchmarked machinery should either be clearly indicated on machine or on a name plate attached to the machine.

3.2. Machinery purchased directly from the machine manufacturers or their authorized agents will be considered for benefits under the scheme. However, the benefit would also be available to the garmenting machinery purchased as per para 4.2.6.

4. General Eligibility Conditions:

4.1 TYPE OF UNITS:

4.1.1 Entities/Units registered under the Companies Act, 1956 or under the Companies Act, 2013 or under the Companies (Amendment) Act, 2015 or as per the provisions in the amendments of the said Acts with the Registrar of the Companies, which have an acknowledgement of Industrial Entrepreneur Memorandum (IEM) with the Department of Industrial Policy and Promotion except MSME units which will be as per the instructions of the Ministry of MSME or units which are registered with the concerned Directorates of the State Government showing clearly the activity for which the unit is registered, will only be eligible to get benefit under this scheme. In case of non-MSME units,

4.1.2 Existing units and new units will be eligible for subsidy within the overall ceiling fixed for an individual entity. However, in case the entity has availed subsidy under RRTUFS, it will be eligible for only the balance amount within the overall ceiling fixed for an individual entity.

4.1.3 Textile units including Handloom, Silk, Jute units are eligible to get benefits under this scheme.

4.2 TYPE OF ELIGIBLE TEXTILE MACHINERY :

4.2.1 Under the ATUF Scheme, only new benchmarked machinery for the specified segments indicating the names of the manufacturers or their authorized agents shall be finalized and notified every year as on 1st April by the Textile Commissioner on the recommendation of Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) will be permitted. Textile Commissioner will obtain list of eligible benchmarked machinery from Jute Commissioner, DC (Handloom) and Member Secretary, Central Silk Board for Jute, Handloom and Silk sectors respectively. No second hand machinery is permitted under this scheme.

4.2.2. Accessories/attachments/sample machines/spares received along with the machinery upto a value of 20% of the machinery cost eligible under ATUFS will also be eligible.

4.2.3 Machinery eligible for one segment is eligible for other segment(s)/activity(ies) also unless its eligibility is specifically restricted for a particular segment/activity.

4.2.4 Eligibility of any other textile machinery not notified by Textile Commissioner for the year as on 1st April may also be included subsequently on the recommendation of TAMC, if considered essential.

4.2.5 The issuance of Unique Identification Numbers (UIDs) will be linked to the list of benchmarked machinery eligible for subsidy under the scheme which will be revised based on the budgetary provision and liabilities, and recommendation of the TAMC every year.

4.2.6. Machinery (imported and indigenous) purchased directly from the machine manufacturers or their authorized agents will be considered for benefit under the scheme. However, the benefit will also be available in case new imported stitching machines required for garmenting/apparel/made-ups manufacturing are purchased from the authorized stockist/custom warehouse located within the country, provided the purchase is made by the consignee/from a person who has purchased the same directly from the machine manufacturers or their authorized agents. Such machinery will also be eligible for benefit under this scheme. Under no circumstances, the machinery which has been used even once and/or even for testing purpose will be allowed under this scheme.

4.2.7 The purchase date means the commercial invoice date both in case of domestic and imported machines.

4.2.8 Machine Identification Code (MIC) allotted by the Textile Commissioner should be mandatorily inscribed on the respective machine(s) on which subsidy under this scheme is claimed.

4.2.9 **ELIGIBILITY CRITERIA FOR ASSISTANCE:**

(i) Entities as specified in para 4.1.1. above will only be eligible to get benefit under this scheme.

(ii) Registration with the concerned authority indicating product manufactured as textiles item(s) is a prerequisite, which is to be produced at the time of verification of machinery to the Joint Inspection Team (JIT), for availing benefit under the scheme.

4.3. **OTHER INVESTMENTS ELIGIBLE:**

Investment made other than the specified machinery will not be eligible under this scheme.

4.4. **NORMS FOR ELIGIBLE SUBSIDY:**

4.4.1 Every eligible individual entity will be paid Capital Investment Subsidy (CIS) under ATUF scheme, on the eligible investment, as per the rates and the overall subsidy cap indicated below:

Sl. No.	Segment	Rate of Capital Investment Subsidy (CIS)	CIS per individual entity
1.	Garmenting, Technical Textiles	15% on eligible Machines	Rs. 30 crore*
2.	Weaving for brand new Shuttle-less Looms (including weaving preparatory and knitting), Processing, Jute, Silk and Handloom.	10% on eligible Machines	Rs. 20 crore*
3(a)	Composite unit/Multiple Segments - If the eligible capital investment in respect of Garmenting and Technical Textiles category is more than 50% of the eligible project cost.	15% on eligible Machines	Rs. 30 crore*
3(b)	Composite unit/Multiple Segments - If the eligible capital investment in respect of Garmenting and Technical Textiles category is less than 50% of the eligible project cost.	10% on eligible Machines	Rs. 20 crore*

*In case the applicant had availed subsidy earlier under RRTUFS, he will be eligible for only the balance amount within the overall ceiling fixed for an individual entity. The maximum subsidy for overall investment by an individual entity under ATUFS will be restricted as indicated above for respective segments.

4.5. **SUBSIDY NORMS:**

4.5.1. The capital investment subsidy under ATUFS will be released in full in one go on eligible investment, only after satisfactory installation/commissioning and commencement of production.

4.5.2 Benefits under the scheme shall be available only if the eligible benchmarked machinery is purchased by availing term loan from a notified lending agency.

4.5.3 Subsidy will be provided only in case of investment made with institutional finance. Investment made by availing Buyers Credit, Usance Credit and Sellers Credit will not be eligible for availing benefits under the scheme unless the entire amount is paid up by the beneficiary before claiming the subsidy and concrete documentary proof is produced for the same at the time of Joint Inspection Team (JIT) verification within the prescribed timelines defined in the scheme.

4.6. **CUT-OFF DATE:**

4.6.1. The date of sanction of term loan shall be the date of the letter of the lending agency vide which the sanction of term loan is communicated to the entrepreneur.

4.6.2. In case the term loan is sanctioned by a lending agency and thereafter the lending agency distributes/down-sells the term loan to other lending agency(ies) or has sanctioned term loan under consortium finance, the date of sanction of the term loan shall be as under:

(i) In case of down-selling the term loan, the date of sanction of term loan by the first lending agency, which has sanctioned the term loan initially, shall be relevant date and the same shall be the date of letter of the first lending agency vide which the date of sanction of term loan is communicated to the entity.

(ii) In case of consortium finance, the consortium leader shall assess eligibility of the project under the scheme for itself and also for other members of the consortium including the amount of term loan eligible under the scheme. However, in this case the date of sanction of the term loan shall be the date of letter of the last lending agency in the consortium, vide which the sanction of loan is communicated to the entity.

4.6.3. No multiple finance for a project is allowed under this scheme. The beneficiary will be required to give an undertaking in this regard in the prescribed format as per Annexure-A.

4.6.4. In each of the above cases CIS will be disbursed to the account of the loanee/applicant of each lending agency on pro-rata basis.

4.6.5. In case where term loan had been sanctioned by the lending agency(ies) under RRTUFS but the period of one year from the date of sanction of the term loan is not yet over and in those cases where the UID applications have not yet been uploaded in Textile Commissioner server using i-TUFS upto 12.01.2016 midnight, such cases will be eligible only for benefits as per the ATUF Scheme notified vide Resolution No. 6/5/2015-TUFS dated 13.01.2016. The applicants of such eligible cases would be required to upload UID applications into the Textile Commissioner server using i-ATUFS software as per the prescribed format of ATUF Scheme as given in para 6 below. These applications would be considered within six months from the date of issuance of Resolution No. 6/5/2015-TUFS dated 13.01.2016 i.e. upto 12-07-2016 on first-cum-first-served basis and subject to the availability of budgetary provisions.

4.7. **COVERAGE OF INVESTMENT PRIOR TO SANCTION OF THE LOAN:**

Advance/token payment up to the margin money for machine cost can be paid by the unit prior to the date of sanction of term loan. However, machines purchased on or after date of sanction of the term loan only will be eligible under the scheme subject to fulfillment of other terms and conditions.

4.8. **BENEFIT OF OTHER SCHEMES:**

Textile units are permitted to avail of benefits of State Governments' Schemes, in addition to the benefit provided under this scheme, unless specifically disallowed.

4.9. **MERGER/TAKE-OVER OF MANAGEMENT OF THE UNIT:**

In case of merger of the companies/units or take-over of the unit(s)/company (ies) by another unit/company, the new unit/company will be entitled to get the remaining balance of subsidy, if due, under the scheme subject to the condition that the merger/take over is either permitted by the Registrar of the Companies or by an order of the Hon'ble High Court and the new unit/company has taken over all the liabilities and assets of the merged/taken over company/unit and the respective bank has also transferred the term loan of the earlier unit/company in the name of the existing company/unit which has taken over. However, in such cases, the new unit/company shall submit a request in the prescribed format as per Annexure-B with all the supporting documents to the Textile Commissioner for changing the profile of the merged company/unit through the i-ATUFS software.

5. **FINANCIAL NORMS:**

5.1. Under the ATUFS, capital investment subsidy will be provided subject to terms and conditions given below:

5.1.1. Financial norms like security, debt-equity ratio, previous year's profit position, net worth etc. will be as per the prevalent norms of concerned lending agency.

5.1.2. Since the Scheme is credit linked, the entrepreneur will be required to keep the term loan component of machinery at a minimum of 50% of the total project cost, to become eligible under the scheme.

5.1.3. All Public Sector Banks, State Financial Corporations (SFCs), State Industrial Development Corporations (SIDCs), Scheduled Banks and NBFCs registered with RBI are eligible for funding under the scheme.

5.1.4. The lending agencies covered under RRTUFS as per Resolution No. 6/19/2013-TUFS dated 04.10.2013 will be automatically covered under this scheme and new lending agency(ies) shall be required to submit their application in the prescribed format as per Annexure-C to the Textile Commissioner, Mumbai through i-ATUFS software in order to notify the lending agency under ATUFS.

5.1.5. Foreign Currency Loan: Foreign Currency Loan availed of from overseas branch of the Indian Bank/Foreign bank having Indian branch will be eligible for benefits under this scheme. However, the loan account should be operational from the Indian branch also so as to make it possible to transfer the subsidy amount in Indian Rupee into the loan account of the applicant in the Indian branch.

5.2. Period of Term Loan under the Scheme :

5.2.1. The term loan sanctioned for availing the benefit of the scheme should not be for less than three years including moratorium period for SSI units and not less than 5 years for other categories.

5.2.2. To prevent misutilisation of the subsidy, it is expected that the unit should at least function for the minimum period of term loan specified above.

5.3. In case of consortium finance, the consortium leader shall assess eligibility of the project under the scheme for itself and also for other members of the consortium including the amount of term loan eligible under the scheme.

5.4. Transferring the ATUFS loan from one lending agency to another lending agency:

The outstanding principal amount of the loan account under this scheme from one lending agency can be transferred to another lending agency only once subject to the condition that portfolio (i.e., balance principal amount) remains unchanged.

5.5. Conversion of rupee term loan into foreign currency loan and vice-versa:

Conversion of Rupee Term Loan (RTL) into Foreign Currency Loan (FCL) and vice-versa is permitted.

6. IMPLEMENTATION MECHANISM:

6.1. The scheme would be executed/implemented by the Textile Commissioner through its Regional/State Offices. A state/regional level office of the office of Textile Commissioner is being set up in each state which will implement and monitor ATUFS on priority. Implementation of the scheme will be done in a five-step process:

Step 1: Submission of the term loan application by the entity/unit/applicant along with a copy submitted to the State/Regional office of the Textile Commissioner who will facilitate sanction of the term loan by the Lending Agency.

Step 2: Application for Unique Identification Number (UID) by the entity/unit/applicant to the Textile Commissioner through the lending agency using i-ATUFS software for pre-authorization of subsidy under the scheme and issuance of UID.

Step 3: Installation of machinery.

Step 4: Submission of the subsidy claim online by the Unit to the Textile Commissioner and forwarding of the claims by Textile Commissioner to the Ministry of Textiles.

Step 5: Release of the eligible subsidy by the Ministry of Textiles to the applicant's account.

6.2. The processes flow of implementation and monitoring mechanism are indicated in the enclosed Annexure D.

6.3. Step-wise processes are detailed as under:

6.3.1. Step 1: Submission of the term loan application by the entity/unit/applicant and sanction of the term loan by the Lending Agency:

(i) The applicant/unit seeking assistance under the scheme shall approach the lending agency for sanction of term loan under the scheme. The applicant shall keep the term loan component of machinery at a minimum of 50% of the total project cost, to become eligible under the scheme.

(ii) The applicant/unit seeking assistance under the scheme shall also simultaneously fill-in details in Format-1 (Part-I) using i-ATUFS software along with details such as PAN number of the company and company registration number etc. and Detailed Project Report (DPR). After submission of said details using i-ATUFS software, an ATUFS reference number will be issued by the Textile Commissioner which will be a system generated number through the i-ATUFS software. In case, an applicant requires guidance on using the i-ATUFS software, the applicant may take the assistance of the Regional/State office of the Textile Commissioner in uploading details through i-ATUFS software in the prescribed format and Regional/State office of the Textile Commissioner shall facilitate him to upload his application as a part of handholding services to the applicant.

(iii) The lending agency shall communicate the sanction of the term loan to the applicant. The date of sanction of term loan shall be the date of the letter of the lending agency vide which the sanction of term loan is communicated to the entrepreneur. However, in case of down-selling of the term loan by the lending agency and in case of consortium finance, the date of sanction of the term loan shall be as per Paras 4.7.3., 4.7.4 and 4.7.5.

6.3.2 Step 2: Application for Unique Identification Number (UID) by the entity/unit/applicant to the Textile Commissioner through the lending agency using i-ATUFS software for pre-authorization of subsidy under the scheme and issuance of UID:

The applicant/unit shall, immediately after sanction of the term loan by the lending agency(ies), further submit details in Format-1 (Part-II & III) using i-ATUFS software alongwith revised DPR, if revised, within six months from the date of sanction of term loan. In case, an entrepreneur requires further guidance on using the i-ATUFS software, the entrepreneur may take the assistance of the Regional/State office of the Textile Commissioner in uploading details through i-ATUFS software in the prescribed Format-1 (Part-II & III) and Regional/State office of the Textile Commissioner, shall facilitate him to upload his application.

6.3.2.1. A system of time-bound processing of applications as well as automatic alert mechanism through i-ATUFS system has been put in place. The system of alerts has been developed on a traffic light system as indicated in Table below:

Sl. No.	%age range of timeline for completion of the activity	Colour of the submitted application
1.	1% - 75% time	Green
2.	More than 75% - 90%	Yellow
3.	More than 90% - upto 100%	Red

6.3.2.2 In i-ATUFS software pre-authorization system for issuance of TUFS registration number for receipt of the applications and UID numbers thereof will be in operation in the office of the Textile Commissioner, Mumbai. Applications for issuance of UID numbers will be considered on a first-come-first-served basis, as per the sequence in which they are received in the i-ATUFS software on the central server at the Office of the Textile Commissioner, subject to eligibility and availability of funds under the scheme.

6.3.2.3. Preference will be given to those applications wherein it is proposed to install energy saving technology/machinery. This preference will be given by having a separate queue for issuance of UID number to the applicant with energy saving machinery and those applicants will be issued UID number first-come-first-served basis in this separate queue. Therefore, if after n^{th} applicants, $(n+1)^{\text{th}}$ applicant comes with energy saving machinery he will be first in the queue of the UID applications for energy saving machinery and will therefore get a priority over the regular queue.

6.3.2.4. An acknowledgement shall be automatically issued through i-ATUFS by e-mail and by SMS facility to the applicant as soon as sanction of the term loan and other details are uploaded in Format-1 and submitted through i-ATUFS software by the applicant.

6.3.2.5. The concerned lending agency shall verify the details submitted by the beneficiary in the prescribed format (Format-1). If the requisite data is found complete in all respects by the lending agency, it will upload the said data and details in the prescribed format (Format-2) to the office of Textile Commissioner in the i-ATUFS software within 2 months from the date of submission of Format-1 by the applicant. The time limit of two months includes rectification time of Format-1 by the applicant, if required.

6.3.2.6. A System generated yellow alert through i-ATUFS software will be sent to the lending agency(ies) if application submitted by the applicant has not been scrutinized within forty-five (45) days from the date of submission of the application to the lending agency through i-ATUFS software. This will alert the lending agency(ies) to attend the case on an urgent basis. Further, if no action is taken by the concerned lending agency(ies) within another nine (9) days, a system generated red alert will be sent to their Executive Director/CGM for taking-up the matter with the concerned officer(s) of the lending agency(ies) so that the case is processed immediately. In case, the lending agency(ies) fails to submit application within two months from the date of receipt of the application through i-ATUFS software, it will be considered as breach of the said guidelines.

6.3.2.7. The UID applications which are found complete in all respects will be processed within one (1) month in the Office of the Textile Commissioner for allotment of UID numbers after checking the mandatory details as per the

prescribed format (Format-3) and UID shall be issued. The correctness of the information/documents submitted for obtaining UID number will be the responsibility of the applicant and the lending agency(ies) concerned.

- 6.3.2.8. If there is any apparent discrepancy, the UID application will be referred back through the i-ATUFS software to the applicant and/or concerned lending agency for rectification and re-submission. The re-submission of the application shall be within a maximum period of one (1) month and shall be considered again on first-come-first-served basis.
- 6.3.2.9. A System generated yellow alert will be sent to the concerned officers in the Office of Textile Commissioner in case application is not attended within twenty three (23) days of its receipt from the lending agency. In case, no action is taken by the Officer concerned within twenty seven (27) days of its receipt from the lending agency, system generated red alert will be sent to their controlling officer and the controlling officer shall ensure that the application is attended urgently to meet the timeline.
- 6.3.2.10. Mere submission of an application for issuance of a UID number in the i-ATUFS software will not entitle the unit for issue of UID number and subsidy under the scheme. A unit would become eligible for subsidy under the scheme only after it has been issued an UID number by the Textile Commissioner.
- 6.3.2.11. An i-ATUFS software is programmed such that no UID can be issued if the subsidy cap of that unit (including preauthorized RRTUFS subsidy) is reached or/and the budget provision is exhausted.
- 6.3.2.12. In order to ensure data integrity and prevent any possible misuse of the scheme, the data submitted by the beneficiary and certified by the concerned lending agency through web portal of the Textile Commissioner shall be treated as frozen and subsidy payment shall be considered strictly as per the physical assessment of eligible subsidy or as per the frozen data, whichever is less.
- 6.3.2.13. In case of any apparent mistake in the UID issued or in case of revision in the project during its implementation, one time correction of the UID details will be considered/permited on case to case basis by the Textile Commissioner within one year from the date of issuance of UID provided that there will be no increase in subsidy.

6.4. Step 3: Installation of machinery:

- 6.4.1. Only benchmarked eligible benchmarked machinery specified under the scheme will be installed by the unit.
- 6.4.2. The applicant should ensure that make, month/year of manufacture, name of the manufacturer and serial number of all the eligible benchmarked machinery are clearly indicated on the machine(s). Moreover, a "Machine Identification Code" (MIC) will be allotted by the Textile Commissioner, which will be a unique identification number for each machine procured under the scheme. This MIC shall be mandatorily inscribed on the machinery and shall be verified during the physical verification at different times.
- 6.4.3. It is mandated that the machine serial number should be expressly written on the shipping documents i.e. "Commercial Invoice" or "Bill of Lading" or the "Airways Bill" or the same is expressly written in the "Bill of Entry" in case of imported machinery. In case of domestic purchases, the machine serial number should be expressly mentioned in the "Commercial Invoice". This is an essential part of requirement under these guidelines w.e.f. 01.04.2016 and would be essential to assign the MIC number to the applicant. Therefore, absence of this information will make the machinery liable to be ineligible for benefit under this scheme.
- 6.4.4. Through the MIC issued, the details could be deduced regarding the textile segment, the country code of the manufacturer, the state/province code of the place where machinery will be installed, the machine manufacturer code (as indicated in scheme), an authorized agent code of the machine manufacturer, the commercial invoice number, the bill of entry number and the bill of lading number (in case of imported machinery), the machine serial number etc.
- 6.4.5. The system generated MIC will be allotted by the Textile Commissioner immediately to the applicant when he/she will submit request for conducting Joint Inspection Team (JIT) verification after installation/commissioning of the machinery.
- 6.4.6. The installation/commissioning of the machines covered under the UID shall be done within one (1) year from the date of sanction of term loan. However, the same will be extendable upto two (2) years on a case to case basis with the approval of the Textile Commissioner. The Textile Commissioner will record in writing the reasons for giving such extensions.
- 6.4.7. System generated first reminder will be sent to the applicant through registered e-mail and SMS in case the applicant does not submit his/her request for undertaking physical verification of the installed machinery within ten (10) months from the date of sanction of term loan, for expediting the installation/commissioning of the machinery for which UID was obtained.

6.5. Step 4: Submission of the subsidy claim online by the Unit to the Textile Commissioner and approval of the same.

6.5.1. After satisfactory installation/commissioning of the machinery and commencement of commercial production, the applicant shall immediately submit his/her request for the same in prescribed format (Format-4) to the Textile Commissioner i.e. within one year from the date of sanction of term loan for undertaking physical verification by a JIT using i-ATUFS software. This timeline is extendable upto two (2) years on case to case basis with the approval of the Textile Commissioner. The Textile Commissioner will record in writing the reasons for giving such extensions.

6.5.2. In case, the applicant fails to submit application after installation of the machinery within prescribed timelines for undertaking physical verification by a JIT in prescribed format (Format-4) using i-ATUFS software, the UID issued to the applicant will be automatically cancelled and will not be considered further for subsidy benefit under this scheme.

6.5.3. In order to ensure that no beneficiary unit avails subsidy beyond the prescribed ceiling, applicant will be required to furnish a declaration on unit's letter head (Format-5) indicating the details of the subsidy availed by the beneficiary unit under RRTUFS. In case the applicant had availed subsidy earlier under RRTUFS, he/she will be eligible for only the balance amount within the overall ceiling fixed for an individual entity.

6.5.4. The Textile Commissioner will constitute a Joint Inspection Team (JIT) comprising of the officers/representatives of the Textile Commissioner, respective lending agency, a Textile Research Association and an Industry Association to verify the technology level of the machine(s) installed under the scheme and certify the eligibility and eligible subsidy amount as per the guidelines of the scheme in prescribed format (Format-6).

6.5.5. The JIT will verify and certify the installation/commissioning of the machinery and commencement of the commercial production in the prescribed format (Format-6) along with all supporting documents and photographs of the installed machinery, within maximum eighty eight (88) days of the receipt of request for JIT. Further, JIT has to submit the report within two (2) days of conducting the physical verification through the i-ATUFS software and will also forward a copy thereof to the Textile Commissioner.

6.5.6. A system generated yellow alert will be sent to the Officer-Incharge of the concerned Regional/State Office of the Textile Commissioner, if JIT does not complete its verification and uploads the same in prescribed format (Format-6) using i-ATUFS software within seventy (70) days of receiving request for JIT verification. In case, he/she fails to act within eighty five (85) days of receiving request for JIT from the applicant, a system generated red alert to the concerned Officer-Incharge including his controlling officer will be sent for taking urgent action on a priority.

6.5.7. The Office of the Textile Commissioner will process the subsidy claim in the prescribed format (Format-7) after receiving the report from the JIT for approval/rejection by Textile Commissioner within one month of the receipt of JIT report.

6.5.8. A system generated yellow alert will be sent to the concerned Director/JTxC/ATxC, if the JIT report is not processed within twenty three (23) days of its receipt through i-ATUFS software. In case, they fail to act within twenty seven (27) days of receipt of the JIT report, a system generated red alert will be sent to the Textile Commissioner for ensuring urgent action on priority.

6.5.9. The Office of the Textile Commissioner will prepare bill for the approved claims and submit the challan for subsidy claim to Ministry of Textiles (MOT) through i-ATUFS after approval by Textile Commissioner.

6.6. Step 5: Release of the eligible subsidy by the Ministry of Textiles to the applicant's account.

6.6.1. Ministry of Textiles (MOT) will process the claims received through i-TUFS software from the Textile Commissioner as per (Format-8) and will directly release the eligible subsidy to the account of the loanees/applicant maintained with the same lending agency (ies) within 21 days from the date of receipt of the claim bill/challan through i-ATUFS software subject to the availability of funds. The account of the unit should be linked to the PAN number of the Unit and Aadhar number (wherever applicable).

6.6.2. Full amount will be released in case the applicant has taken loan from one lending agency only under ATUFS. However, in case the applicant has availed facility of down-selling of term loan or consortium financing, the subsidy amount will be credited into the account of the loanees on pro-rata basis.

6.6.3. A system generated yellow alert will be sent to the concerned Deputy Secretary/Director of the Ministry of Textiles, if the received claim bills/challans are not processed within seventeen (17) days of its receipt from the office of the Textile Commissioner through i-ATUFS software. In case, the same is not processed within nineteen (19) days of receipt of the claim bills from the office of the Textile Commissioner, a system generated red alert to the Joint

Secretary (ATUFS)/the Additional Secretary (ATUFS) will be sent for ensuring that the same are processed within given timeline as defined in para 6 and process flow chart (Annexure-D).

6.6.4 The release of the subsidy into the account of the loanee/applicant in DBT mode would be a deemed utilization of the amount of subsidy and no further utilization certificate would be necessary.

7. MONITORING MECHANISM:

The scheme will be administered with a two stage monitoring mechanism i.e. by Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) and Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC).

7.1 Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC):

A Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) under the Chairpersonship of Textile Commissioner will be constituted with technical experts from the Government and the industry covering the different segments, as members. The composition and functions of TAMC are given at Annexure-E.

7.1.1. Amendment in the list of machinery in terms of addition/deletion will be done by the TAMC.

7.1.2. If any question of interpretation or clarification is raised by the lending agency/entrepreneurs as to the eligibility of any unit or machinery under the scheme, the decision of the TAMC will be final.

7.1.3. The TAMC will also monitor and review the progress of the scheme including segmental progress and apprise the Ministry and IMSC quarterly.

7.2 Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC):

7.2.1. An IMSC will be constituted under the Chairpersonship of Minister of Textiles with the representatives of the Ministry of Finance (Dept. of Expenditure and Dept. of Financial Services), Department of Heavy Industry, Deptt. of Commerce, Deptt. of Industrial Policy & Promotion, NITI Aayog, selected lending agencies, Textile Industry Associations etc. IMSC would be responsible for monitoring and formulation of guidelines for effective implementation of the scheme in accordance with the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)'s approval. The composition and functions of IMSC are given at Annexure-F.

7.2.2. The IMSC will review the progress of the scheme half yearly and ensure its effective implementation.

8 PROVISIONS FOR CANCELLATION OF UID:

8.1. UID issued under the scheme shall be cancelled in cases where:

8.1.1. The applicant fails to submit intimation of installation of the machinery within two years from the date of sanction of term loan for undertaking physical verification by a Joint Inspection Team (JIT). The UID issued to the applicant will be automatically cancelled and will not be considered further for subsidy benefit under this scheme.

8.1.2. The applicant decides not to avail benefits under the scheme for any reason for which he/she may upload request for cancellation of the issued UID through concerned lending agency using i-ATUFS software. This request should be made in the prescribed format (Format - 9).

8.1.3. In case the application gets rejected at any stage for any other reason, the UID shall be suo-moto cancelled.

9 SAFEGUARDS AGAINST MISUTILIZATION:

9.1. To prevent misutilisation of the subsidy being provided under the scheme, the following safe-guard are put in place:

9.1.1. Assets created by the unit against the allotted UID under this scheme and technology level thereof will be physically verified by a Joint Inspection Team (JIT) comprising of the officers/representatives of the Textile Commissioner, representatives of respective lending agency, Textile Research Association and industry association. The JIT will certify the eligibility and eligible subsidy amount as per the guidelines of the scheme.

9.1.2. It is made mandatory that make, year of manufacture, name of the manufacturer and serial number of all the eligible benchmarked machinery are clearly indicated on the machine (s). Moreover, a "Machine Identification Code" (MIC) will be allotted by the Textile Commissioner, which will be a unique identification number for each machine procured under the scheme. This MIC shall be mandatorily inscribed on the machinery and shall be verified during the physical verification at different times.

9.1.3. In order to ensure that no beneficiary unit avails subsidy beyond the prescribed ceiling, applicant will be required to furnish a declaration duly signed by the authorized person of the entity on the unit's letter head indicating the details of the subsidy availed by the beneficiary unit under RRTUFS and ATUFS.

9.1.4. The Officers of the Ministry of Textiles will periodically inspect the machinery installed/commissioned by units, on a random basis.

9.1.5. Third Party Engineering Consultant(s) will be engaged by the Ministry to undertake inspection of the units availing benefits under the scheme on sample basis.

9.1.6. It is expected that the unit should atleast function for a minimum period of three years. To monitor the functioning of the unit for three years the lending agency (ies) should keep the minimum re-payment period including moratorium period as three years in case of SSI units and five years for other units.

10 GRIEVANCE REDERESSAL MECHANISM:

10.1. All grievances received in prescribed format (Format-10) related to implementation of this scheme shall be redressed by a Grievance Committee set up under the chairpersonship of the Textile Commissioner with the representatives from the Ministry of Textiles, Lending Agencies and industry associations etc.

10.2. The grievances related to ATUFS policy matter and interpretations on ATUFS shall be required to be submitted in the prescribed format (Format-11) to the Secretary, Ministry of Textiles, Government of India who will redress the same.

11. AMENDMENT OF GUIDELINES:

Any amendment of these guidelines involving financial issues may be done with the prior approval of the Expenditure Finance Committee (EFC). Amendment involving issues other than financial may be made with the approval of IMSC.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that copies of the Resolution may be communicated to the concerned Ministries/Departments/Organizations.

PUSHPA SUBRAHMANYAM
Additional Secretary

Annexure -A

NO MULTIPLE FINANCING UNDERTAKING

(On the letter head of unit)

Date:

We _____ (Name of the beneficiary unit) hereby certify that no machinery or any part thereof, for which benefits are claimed under ATUFS has availed loan from more than once from this bank and/or any other bank(s)/Lending Agency(ies)/Financial Institution(s).

Following are the details of all project(s) undertaken and loans availed where benefits under TUFS have been availed by us:

Sl. No.	NAME OF PROJECT	PROJECT AMOUNT (PROJECT COST)	LOAN(S) TAKEN FOR PROJECT (LOAN DISBURSED AMOUNT)	LENDING BANK(S)/F.I.(S)/L.A.(S)
TOTAL				

We also undertake that in the event of any inconsistency in the above mentioned facts, the entire subsidy along-with penal interest as imposed on us by the Lending Agency or Government shall be reimbursed to the Government directly or through the lending agency as per the direction of the Government. Government or Lending Agency is also authorized to take any other penal action like disentitlement, blacklisting, etc., as it may deem fit.

Signature of the Authorized signatory
Name and Designation
For and on behalf of (Name of the beneficiary unit)
(Please affix Seal/Rubber Stamp of the Company/unit)

* TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme) means and includes TUFS, MTUFS, RTUFS, RRTUFS and ATUFS

TUFS Ref. No._____

Annexure - B

Request for takeover of term loan from one Bank/lending agency to another lending agency

Note: While change over to another lending agency the unit has to ensure that the new lending agency is covered under ATUFS

Sl. No.	Description	Details	Supporting documents attached
1.	UID Number and Date		
2.	Name of the Current Bank		
3.	Total Term loan sanctioned by the initial Bank (in Rupees)		
4.	Outstanding Amount in the loan Account under TUFS which is being taken over by the other Bank		
5.	Name of the New Bank		
6.	Upto which quarter the claim has been lodged by previous Bank		
7.	Whether previous Bank has issued NOC for taking over the account by another Bank under TUFS		
8.	Actual Amount Of Term Loan Taken Over By New Bank with details of sanction letter issued by the new Bank		
9.	Quarter from which new Bank will submit claim		
10.	Reasons for change of Bank		

Certified that the information furnished above is true and correct and is based on the documentary evidence available with the unit, which may be verified by the designated officers at any time.

Place:

(Signature)

Date :

(Name and designation of the authorised signatory)

Note : Please affix seal/rubber stamp of the Company/Unit along with signature of the authorized signatory.

Annexure - C

FORMAT FOR INCLUSION OF LENDING AGENCY UNDER ATUFS

(To be submitted to the Textile Commissioner through i-ATUFS software)

1.	Name of the Bank	
2.	Address	
3.	IFSC Code	
4.	MICR Code	
5.	Name of the Contact Person	
6.	Contact No. (O)	
7.	Mobile No.	
8.	e-mail I.D.	
9.	Fax No.	
10.	Name of the Branch	
11.	IFSC Code of Branch	
12.	MICR Code of Branch	
13.	Contact Person	
14.	Contact No. (O)	
15.	Mobile No.	
16.	e-mail I.D.	
17.	Fax No.	

Signature

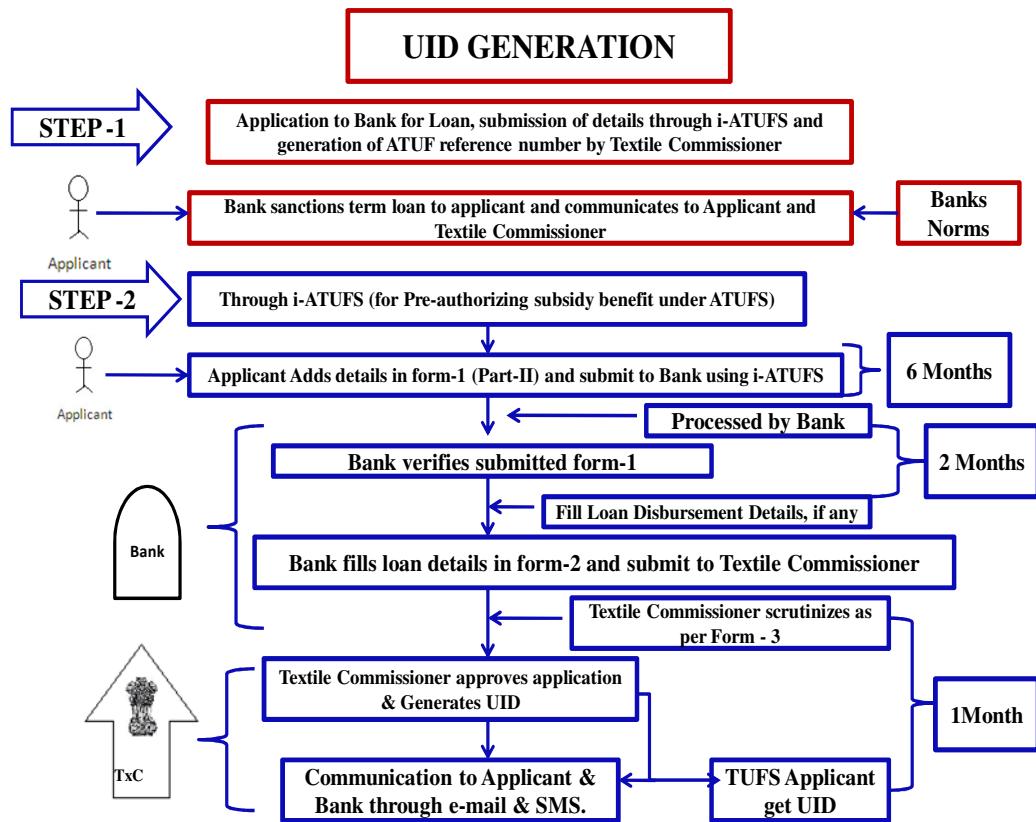
Date:

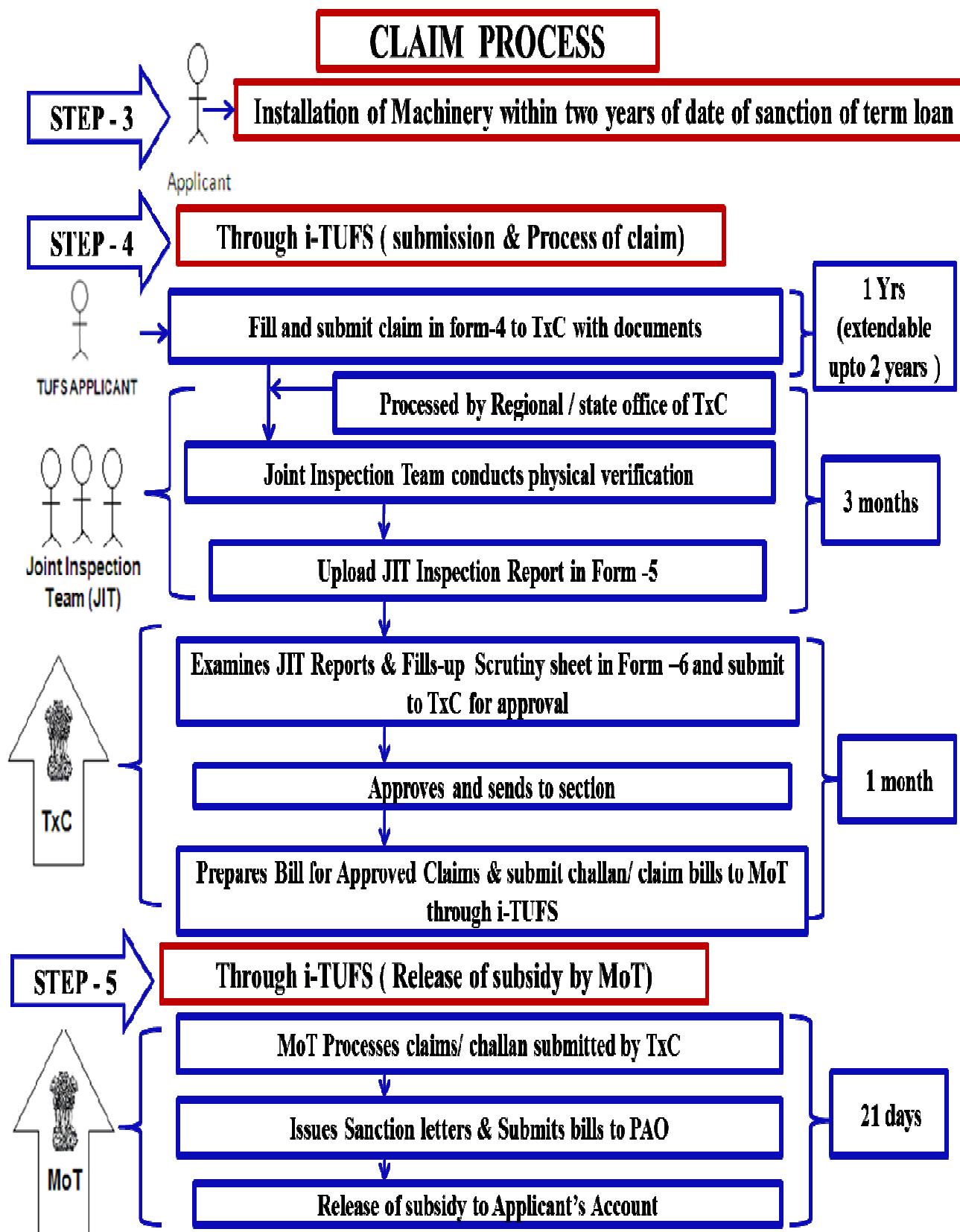
Name & Designation with Seal

List of enclosures :

1. Copy of Banking Licence issued by RBI under Banking Regulation Act, 1949.
2. Copy of letter issued by RBI for inclusion in the second schedule to the RBI Act, 1934.
3. Copy of letter issued by GOI for registration under Multi State Cooperatives Act, if applicable.
4. Copy of PAN/TAN No.
5. Copies of Audited Balance Sheet for the preceding 3 years.
6. Other relevant information, if any.

ANNEXURE-D





ANNEXURE—E

COMPOSITION OF TAMC

1.	Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai	Chairperson
2.	Director (ATUFS), Ministry of Textiles	Member
3.	Jute Commissioner, Ministry of Textiles, Kolkata	Member
4.	Industrial Adviser, Department of Heavy Industry, New Delhi	Member
5.	Chairman, Confederation of Indian Textile Industry, New Delhi	Member
6.	Chairman, Indian Woollen Mills Federation (IWMF) Mumbai	Member
7.	Chairman, Federation of Indian Art Silk Weaving Industry (FIASWI), Surat	Member
8.	President, Indian Spinners Association (ISA), Mumbai	Member
9.	President, South India Spinners Association (SISPA), Coimbatore	Member
10.	President, Ludhiana Knitwear Club, Ludhiana	Member
11.	Chairman, Textile Machinery Manufacturers Association of India (TMMAI), Mumbai	Member
12.	President, Indian Jute Mills Association (IJMA), Kolkata	Member
13.	Chairman, Clothing Manufacturers' Association of India (CMAI), Mumbai	Member
14.	Chairman, Powerloom Development and Export Promotion Council (PDEXCIL), Mumbai	Member
15.	Chairman, Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL), Mumbai	Member
16.	Chairman, Apparel Export Promotion Council (AEPC), Gurgaon	Member
17.	Chairman, Synthetic and Rayon Textiles Promotion Council, Mumbai	Member
18.	In-charge, TUFS Cell, IDBI Bank, Mumbai	Member
19.	In-charge, TUFS Cell, Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Lucknow	Member
20.	Chairman, The Southern India Mills' Association, Coimbatore	Member
21.	Chairman, Indian Technical Textile Association (ITTA), Mumbai	Member
22.	In-charge, TUFS Cell, Industrial Finance Corporation of India, New Delhi	Member
23.	In-charge, TUFS Cell, State Bank of India, Mumbai	Member
24.	In-charge, TUFS Cell, Central Bank of India, Mumbai	Member
25.	In-charge, TUFS Cell, Bank of India, Mumbai	Member
26.	In-charge, TUFS Cell, NCDC, New Delhi	Member
27.	In-charge, TUFS Cell, Bank of Baroda, Mumbai	Member

28.	In-charge, TUFS Cell, Indian Overseas Bank, Mumbai	Member
29.	In-charge, TUFS Cell, Union Bank of India, Mumbai	Member
30.	In-charge, TUFS Cell, Punjab National Bank, New Delhi	Member
31.	Director, Bombay Textile Research Association, Mumbai	Member
32.	Addl./Joint Textile Commissioner in-charge of ATUFS, Office of Textile Commissioner, Mumbai	Member Secretary

2. The TAMC will monitor and review the progress of the scheme including segmental progress and apprise the Ministry and the IMSC quarterly.

3. The TAMC will update and specify the eligible benchmarked machinery annually as on 1st April.

ANNEXURE-F

COMPOSITION OF IMSC

1.	Union Minister of Textiles	Chairperson
2.	Secretary, Ministry of Textiles	Vice Chairman
3.	Secretary, Department of Expenditure	Member
4.	Secretary, Department of Financial Services	Member
5.	Secretary, Department of Commerce	Member
6.	Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion	Member
7.	Secretary, Department of Heavy Industry	Member
8.	Secretary, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	Member
9.	Deputy Governor, Reserve Bank of India	Member
10.	Addl. Secretary & Financial Advisor, Ministry of Textiles	Member
11.	Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai	Member
12.	Jute Commissioner, Ministry of Textiles, Kolkata	Member
13.	Development Commissioner (Handlooms), New Delhi	Member
14.	Adviser, (in-charge of the textiles), NITI Aayog, New Delhi	Member
15.	Member Secretary, Central Silk Board, Bengaluru	Member
16.	Chairman & Managing Director, IDBI	Member
17.	Chairman & Managing Director, SIDBI	Member
18.	Chairman & Managing Director, IFCI	Member
19.	Chairman, State Bank of India	Member
20.	President, Textile Machinery Manufacturers Association of India (TMMAI), Mumbai	Member
21.	Chairman, Confederation of India Textile Industry (CITI), New Delhi.	Member

22.	Chairman, Federation of India Art Silk Weaving Industry, Surat.	Member
23.	Chairman, Indian Woolen Mills Federation (IWMF), Mumbai	Member
24.	Chairman, Powerloom Development & Export Promotion Council (PDEXCIL), Mumbai	Member
25.	Chairman, Indian Jute Mills Association (IJMA), Kolkata	Member
26.	President, Clothing Manufacturers Association of India, Mumbai	Member
27.	Chairman, Indian Technical Textile Association (ITTA), Mumbai	Member
28.	Chairman, South India Spinners Association, Coimbatore	Member
29.	Chairman, The Southern India Mills' Association, Coimbatore	Member
30.	Additional/Joint Secretary (in-charge of ATUFS)	Member-Secretary

2. IMSC would be responsible for monitoring and formulation of guidelines for effective implementation of the scheme in accordance with the CCEA approval. The IMSC will review the progress of the scheme half yearly and ensure its effective implementation.

3. Any amendment to the scheme involving issues other than financial may be made with the approval of IMSC.

FORMAT - 1

(To be submitted by beneficiary)

PART - I

NOTE:

1. Please tick (✓) the correct option wherever applicable
2. Amount must be entered in Rupee only. In case, it will be entered in thousand/lakh or crore, application will be returned for correction and beneficiary may lose seniority in pre-authorising subsidy)
3. The beneficiary who has already filled Format I Part I online for any term loan under RR-TUFS need not have to submit Part I of Format I again, if there is no change in the information. They may however has to fill up all other details invariably in Part II to Part IV of Format I.

A. i. Name of the applicant's Bank/Institution	
ii. Address of the applicant's Bank/Institution	
iii. <u>IFSC code</u>	
iv. Tel. No with STD code	
v. Fax No	
vi. E-mail ID	
B. i. Name of the bank's contact officer	
ii. Mobile No.	
iii. Fax No.	
iv. E-mail ID	
C. Date of application to Bank for Term Loan	

A. INFORMATION ON COMPANY/FIRM

Name of the company/firm					
1. Name of the promoters/directors/proprietors/partners		Name	PAN no.	DIN no.	Aadhar card no.
2.	Name of the contact person				
	Tel.No				
	Mobile No.				
	Fax No,				
3.	E-mail ID				
	Plant(s) Address(es) of the company/firm with pincode number				
4.	Tel.No with STD code				
	Fax No,				
	E-mail ID				
5.	Registered office address with pin code number:				
	Tel. No with STD code				
	Fax No,				
6.	E-mail ID				
	Unit's PAN No.				
	Whether it is a	MSE (As per MSMED Act 2006)	Non-MSE (As per MSMED Act 2006)		
7.	Management i.e. proprietorship/partnership/private limited company/public limited company/co-operative/others?				
8. a)	Whether it is an existing company/firm or a new company/firm?	Existing	<input type="checkbox"/>	New	<input type="checkbox"/>
	b) Please furnish its date of incorporation	_____/_____/_____ (dd/mm/yyyy)			
9.	a. Segment				
	i. Existing				
	ii. After Expansion				
	b. Brief background of the company/firm including its present activities				
c. Products being manufactured/to be manufactured					
d. End-use applications of the products					

B. INFORMATION ON THE PRESENT PROJECT

[Please upload Detailed Project Report (DPR) on which bank has extended term loan.]

1. Brief description of the present project		
2. Segment	Weaving preparatory/weaving/knitting/processing/technical textiles/garmenting	
3. Expected date of completion of the project	____/____/____ (dd/mm/yyyy)	

FORMAT 1

PART II

A. Main Plant & Machinery/Equipment Proposed to be installed under the Project:

(Amount in Rs.)

SR. NO.	DESCRIP TION OF THE MACHI NERY/E QUIPM ENT 9 digit code/sr. no.of the machine	NU MB ER OF MA CHI NER Y ITE MS	WHETHER MACHINERY PURCHASED BEFORE OR AFTER SANCTION OF THE TERM LOAN (TICK WHICHEVER COLUMN IS APPLICABLE)	TOTAL COST (MACH INE- WISE)	*Basic Cost of Machine /equipm ent (MACH INE- WISE)	ANNEXU RE NO. & ITEM NO. AS PER THE GR ON MINT	SPECIFIC ATIONS/ DESCRIPT ION OF THE MACHINE /EQUIPME NT AS INDICATE D IN THE GR ON MINT	ACTUAL SPECIFI CATION S/DESCR IPTION OF THE MACHIN E/EQUIP MENT VIS-À- VIS MINT RELATE D SPECIFI CATION S/ DESCRIP TION AS INDICAT ED IN COL.11]	WHETHER IT IS ACQUIRED AS A COMPLETE MACHINE OR IT IS PART- UPGRADATION/PART- REPLACEMENT OF AN EXISTING MACHINE? (TICK WHICHEVER COLUMN IS APPLICABLE)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

NOTE:

* Basic Price (Machine-Wise) In Respect Of Indigenous Machinery/Equipment and CIF Price (Machine-wise) in r/o
Imported Machinery/Equipment

	a. Total term loan(s) sanctioned	Rs. _____ (please upload a copy of term loan(s) sanctioned letter(s) received from the banks)	
	b. Promoters Contribution	Rs. _____ ; _____ % of the project cost	
	c. Term Loan Account No.	nuemonic number only	
	d. Whether the term loan is being shared by other Bank(s)/Institution(s)?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	e. If yes, indicate sharing pattern	Name of the Bank/Institution	Amount (in Rs.)
Total			
Date of commencement of implementation of the project	____ / ____ / ____ (dd/mm/yyyy)		
Degree/%age of Modernization of the unit	Before this project <input type="checkbox"/>	After this project <input type="checkbox"/>	

FORMAT-1 (Continued)

PART-III

1. INFORMATION ON TUFS LOANS AND SUSIDY BENEFITS AVAILED BY THE UNIT TILL DATE (FROM 1999 ONWARDS) AND IMPROVEMENTS ACHIEVED SO FAR:

Details of TUFS loan availed till date and Subsidy received						As a result of TUFS project implementation the benefit accrued					
Month/ year	Project cost	Term loan sanctioned	Bank/L A	*Segment	Amount of subsidy received	*Capacity added/replaced	Increase in turn over (%)	Increase in profit (%)	Increase in exports (%)	Improvement in quality**	Extent of modernisation achieved (%)***

Note: *1. Segment & Capacity details will be selected from drop-down-menu provided.

**2. As assessed by the beneficiary unit (may be good/very good/excellent etc)

***3. Extent of modernization achieved will as per self-assessment by beneficiary.

2. INFORMATION ON TUFS LOANS AND SUSIDY BENEFITS AVAILED BY THE UNIT UNDER RRTUFS:

Sr. No.	Account Number	TUF Ref. No. & UID No	Authorized Subsidy for Full Tenure in Rs.	Subsidy Received till filling application in Rs.

3. PERSONAL DETAILS OF BENEFICIARY OWNER

(Please tick wherever applicable)

I. IN THE CASE OF PROPREITORY

Gender	Male/Female		
Whether belongs to SC/ST	Yes <input type="checkbox"/>	SC/ST <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Whether belongs to minority community	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

II. IN THE CASE OF PARTNERSHIP FIRMS

Number of Partners		
Gender(Numbers)	Male <input type="checkbox"/>	Female <input type="checkbox"/>
SC/ST (Numbers)	SC/ST <input type="checkbox"/>	Others <input type="checkbox"/>
Minority Community(Numbers)	Minority <input type="checkbox"/>	Others <input type="checkbox"/>

III. IN THE CASE OF LIMITED COMPANIES

Number of Directors including MD		
Gender(Numbers)	Male <input type="checkbox"/>	Female <input type="checkbox"/>
SC/ST (Numbers)	SC/ST <input type="checkbox"/>	Others <input type="checkbox"/>
Minority Community(Numbers)	Minority <input type="checkbox"/>	Others <input type="checkbox"/>

INFORMATION ON MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSEs)

ITEMS 1 TO 4 BELOW TO BE FILLED FOR MSE UNITS ONLY [IN OTHER WORDS, ITEMS 1 TO 4 BELOW TO BE SKIPPED FOR NON-MSE UNITS]

INFORMATION ON EMPLOYMENT (in numbers)

Existing Employment			Employment to be generated under this project			Total After completion of this project		
Managerial	Supervisory	workers	Managerial	Supervisory	workers	Managerial	Supervisory	workers

DETAILS OF CAPACITY

Segment	Present installed capacity	Proposed expansion [net]/new Capacity	Installed capacity on completion of the project
1	2	3	4
1. Twisting/T.F.O. (in numbers of machines)			
2. Warping (in numbers of machines)			
3. Fibre Dyeing (in Kg./month)			
4. yarn Dyeing (in Kg./month)			
5. Sizing (in numbers of machines)			
6. Shuttle-less Looms (in nos of loom)			
7. (Projectile/Rapier/Air-jet/Water-Jet)			
8. Knitting (in numbers of machines)			
9. Woven Fabric Dyeing (in mtrs/month)			
10. Knitted fabric Dyeing (in Kg./month)			

1	2	3	4
11. Woven Fabric Printing (in mtrs/month)			
12. Knitted fabric Printing (in mtrs/month)			
13. Garmenting/made-ups (in nos. of pieces/month)			
14. Technical Textiles (Pl. specify the end product) a. Woven b. Non-woven c. Knitted			
15. Any other			

Break-up of the project cost:

Items	In Rs.	
	Total cost	Basic price [i.e. excluding tax component viz. sales tax/excise duty/import duty, etc.]
Land		
Factory buildings		
Preliminary and pre-operative expenses		
Margin money for working capital		
Main plant and machinery		
Other fixed investments		
Total		

EXPENDITURE INCURRED BEFORE THE DATE OF SANCTION OF TERM LOAN.

Whether any expenditure incurred for the project before sanction of term loan	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
---	------------------------------	-----------------------------

If yes, details of expenditure incurred on the machinery/equipment before date of sanction of the term loan

(Rs.)

Date	Machinery/equipment [Details to be furnished here in conformity with the information given in format]		Total cost (machine-wise)	Basic/CIF price (machine-wise) [i.e. excluding tax component viz. sales tax/excise duty/import duty, etc.]	Amount incurred (machine-wise)	Whether machine-wise payment made [Please mention 'Yes' or 'No']	Source of funds
	Imported	Indigenous					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (I)						

Total expenditure incurred on the project before date of sanction of the term loan : Rs._____.

FORMAT-1 (Continued)

PART-IV

Certified that:

1. The information furnished in PART-I, PART-II and PART III of FORMAT - 1 is true and correct and furnished based on the documentary evidences available with the unit, which may be verified by the designated authorities at any point of time.
2. I/we hereby certify that the unit/firm is eligible for claiming the subsidy under the scheme within the overall ceiling fixed for the respective category.
3. I/We _____ (Name of the beneficiary unit) hereby certify that no machinery or any part thereof, for which benefits are being claimed/taken under TUFS (includes TUFS, MTUFS, RTUFS and RRTUFS), has been loan funded more than once from this bank and any other banks/Lending Agencies/Financial Institutions. A copy of duly signed certificate (in specified format) is uploaded which will be produced to JIT in original at the time of claiming subsidy.
4. I/we hereby undertake that the subsidy availed for the stated purpose will be utilized only for installation of the benchmarked technology as mentioned in the Government Resolution on ATUFS. In case of any variation found during the verification of the documents and assets of the company/unit, or at any later stage, the benefits availed under ATUFS will be returned to bank(s)/Government with the applicable penal interest from the date of its receipt.
5. I/We shall own responsibility for omissions/misrepresentations, if any, in the above information. In case of any variation in the above furnished information, I/we hereby undertake to inform the same to the bank/Government.
6. It is certified that I/We -----have been pre-authorized for an amount of Rs.----- under RR-TUFS & A TUFS and as on date of filling this application under ATUFS and an amount of Rs.----- has been received as subsidy under RR-TUFS & A TUFS.
7. I/We -----undertake that the unit shall be operational for a minimum period of three years and the minimum re-payment period including moratorium period of this term loan is three years.

Place:

(Signature)

Date : (Name and designation of the authorised signatory)

Note :

Please affix seal/rubber stamp of the Company/Unit along with signature of the authorized signatory.

Fill in all the Items with specific details.

FORMAT- 2

Certificate by the Lending Agency

[Please tick (✓) the correct option wherever applicable]

(To be filled in by the Branch of the Lending Agency)

1.	Whether information furnished by the applicant in FORMAT- 1 is correct and verified from the documents	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.	Date of receipt of the term loan application by the Bank/Institution	_____/_____/_____ (dd/mm/yyyy)	
3.	Date of sanction of the term loan by the delegated authority (Board/Credit Committee, etc.)	_____/_____/_____ (dd/mm/yyyy)	
4.	Date of communication of sanction to the company/firm	_____/_____/_____ (dd/mm/yyyy)	
5.	a. Total Term Loan Sanctioned	Rs. _____	
	b. Promoter's Contribution	Rs._____ ;	___ % of the project cost

6.	Projected Date of completion of the project	____ / ____ / ____ (dd/mm/yyyy)	
7.	Implementation period	____ years ____ months	
8.	Date of first disbursement	____ / ____ / ____ (dd/mm/yyyy)	
9.	a. Repayment start date	____ / ____ / ____ (dd/mm/yyyy)	
	b. Repayment end date	____ / ____ / ____ (dd/mm/yyyy)	
	c. Repayment period [i.e. Item No. 9b minus Item No. 9a]	____ years ____ months	
10	Account Number of Term Loan		
11	a. Whether the term loan is being shared by other Bank(s)/Institution(s)?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	b. If yes, indicate sharing pattern	Name of the Bank/Institution	Amount (Rs.)
	c. In case of consortium financing, which is the lead bank?	Total	

Certified that:

The information furnished in by the applicant in PART—I, PART—II and Part III of FORMAT - 1 is found correct on the basis of records available with our bank.

It is also certified that the minimum re-payment period including moratorium period of this term loan is three years.

Place:

(Signature)

Date : (Name and designation of the authorised signatory)

FORMAT - 3

FORMAT FOR CHECK LIST FOR ISSUANCE OF UID BY OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER (Sl. No. 1 to 20 are System generated)

1.	i) Status of the Application ii) Date and Time of Deficient iii) Reason for making deficient by TxC	(System generated)
2.	i) Re-submission date (Date and Time) (auto created while UID application submitted by the Lending Agency) ii) Compliances by the Nodal Agency- comments	(System generated)

3.	Approval date (Date and Time) (auto created while UID application submitted by the Lending Agency)	(System generated)	
4.	Approval/Waitlist No	(System generated)	
5.	Name & Address of the unit	(System generated)	
6.	e-mail ID of the unit	(System generated)	
7.	PAN number	(System generated)	
8.	Date of sanction of term loan	(System generated)	
9.	Project cost in Rs.	(System generated)	
10.	Segment claimed	(System generated)	
12.	Expected date of completion of project	(System generated)	
13.	Bank name and address, Branch Code	(System generated)	
14.	Term loan Sanctioned in Rs.	(System generated)	
15	Promoter's Contribution in Rs.	(System generated)	
16.	Term Loan account number	(System generated)	
17.	Basic Cost of eligible machines in Rs.	(System generated)	
18.	Subsidy value entitled on eligible machines in Rs.	(System generated)	
19.	TUFS Subsidy Pre-authorised and availed under RRTUFS	(System generated)	
20.	Total pre-authorised subsidy under ATUFS in Rs.	(System generated)	
21.	Whether there is identical application having same PAN and same term loan sanctioned in online system (auto)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
22.	Whether application is submitted within six months from the date of sanction of term loan	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
23.	Whether selected segment is correct	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
24.	Whether required type of subsidy is correct	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
25.	Whether subsidy indicated is correct	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
26.	Whether segment & machines matching with DPR (Executive Summary, Cost of Project & Mean of Finance)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
27.	Whether copy of PAN found attached & matching with PAN details in application	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
28.	Whether "No Multiple Finance Certificate" is attached by the applicant	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
29.	Application checked by Name & Designation Date & Time		
30.	Application verified by Name & Designation Date & Time		

FORMAT-4

FORMAT FOR SUBMISSION OF REQUEST FOR CONDUCTING JOINT INSPECTION FOR THE INSTALLED MACHINES BY APPLICANT UNDER A TUFS

1.	TUFS Reference Number						(auto generated from system)				
2.	UID No. & date						(auto generated from system)				
3	Unit's company registration details or registration details with appropriate authority						Please upload a copy				
4	Copy of recent electricity bill						Please upload a copy				
5	Partnership deed in case of partnership firm						Please upload a copy				
6	Lease deed/property documents for proprietor/partnership/co-operative firm						Please upload a copy				
7	Date-wise actual disbursement of term Loan (Please also upload bank's certified statement)										
8	Bank's Statement for Margin Money and Term Loan						Please upload a copy				
9	Copy(ies) of Machine(s) commercial Invoice(s) .(Unit have to mention Invoice No & date in i-ATUFS and also upload the same.)										
	Name of Machine ry Projecte d While obtainin g UID	Num bers	Project ed Basic cost in Rs.	Actual machin ery Purcha sed & Install ed	Actual nos.	Actual Basic cost in Rs. as per Commer cial Invoice	Name of Mfr	Year of Mfr	Com merci al Invo ce no.	Bill of Entry	Count ry of Origin
	i.										
	ii										
	iii										
	iv										
v											
10	Justification for Change of Machinery (in case Actual Machine varies from Projected machine)										
11	Bill of entry number and date (in case of imported machine(s)						Please also upload a copy(ies)				
12	TR-6 Challans (for custom duty paid) (in case of imported machine(s)						Please also upload a copy(ies)				
13	Country of Origin duly certified by bank (in case of imported machine(s)						Please also upload a copy(ies)				
14	Bill of lading number & date (in case of imported machine(s)						Please also upload a copy(ies)				
15	LC certified by bank (in case of imported machine(s)						Please also upload a copy(ies)				
16	Debit advice certified by bank (in case of imported machine(s)						Please also upload a copy(ies)				
17	Swift/Telegraphic transfer receipt certified by bank (in case of imported machine(s)						Please also upload a copy(ies)				
18.	Date of completion of installation of all machines covered under UID obtained:										

19.	Date of submission of request by the TUFS applicant		(auto generated from system)	
20.	Actual employment generated		Total:	
	i. Men:	ii. Women	i.	ii
	iii. SC, ST	iv Minority	iii	iv

Note: All the documents related to banking operation should be endorsed by the concerned bank from where term loan is availed.

Certified that:

The information furnished in this format is true and correct and furnished based on the documentary evidences available with the unit, which may be verified by the designated officers at any point of time.

Place:

(Signature)

Date :

(Name and designation of the authorised signatory)

Note : Please affix seal/rubber stamp of the Company/Unit along with signature of the authorized signatory.

Fill in all the Items with specific details.

FORMAT-5

Declaration to be furnished by the unit at the time of JIT

(On unit's letterhead)

8. It is certified that I/We -----has been pre-authorized for an amount of Rs.----- under RR-TUFS & ATUFS and as on date of filling the application under ATUFS and an amount of Rs.----- has been received as subsidy under RR-TUFS & ATUFS.
9. I/We _____ (Name of the beneficiary unit) hereby certify that no machinery or any part thereof, for which benefits are being claimed/taken under TUFS, has been funded more than once from this bank and any other banks/Lending Agencies/Financial Institutions. A copy of duly signed certificate (in specified format as Appendix-II) is uploaded which will be produced to JIT in original at the time of claiming subsidy.
10. I/we hereby undertake that the subsidy availed for the stated purpose will be utilized only for installation of the benchmarked technology as mentioned in the Government Resolution on ATUFS. In case of any variation found during the verification of the documents and assets of the company/unit, or at any later stage, the benefits availed under ATUFS will be returned to bank(s)/Government with the applicable penal interest from the date of its receipt.
11. I/We -----undertake that the unit shall be operational for a minimum period of three years and the minimum re-payment period including moratorium period of this term loan is three years.

(Signature)

Name and Designation of the Authorised signatory with Seal.

FORMAT-6

CERTIFICATION ON INSTALLATION AND COMMISSIONING OF MACHINERY UNDER ATUFS BY JOINT INSPECTION TEAM (JIT)

1. Date of Receipt of Unit's Application in.O/o.Tx.C:
2. UID No. and Date allotted by O/o.Tx.C:
3. Date of Inspection:

4.	Name & Address of the unit inspected with pin code Taluka/Tahsil/Mandal: District: State: Pincode:	
	Phone No./Mobile No.	
	Fax No.	

	E-Mail ID		
	Unit PAN No.		
	SSI Reg./EM No. & Date		
	Name of Contact Person		
	Contact No.:		
5.	Whether the unit found working on the address mentioned in the UID application.	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	If not, then actual address of the unit. Taluka/Tahasil/Mandal: District: State: Pincode:		
6.	a) Whether details submitted in FORMAT 1 by the unit and certified by the bank are found correct or not	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	b) If not please specify		
	c) Whether Declaration in FORMAT 5 is obtained from the unit and attached	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
7.	Segment		
8	a. Whether all machines indicated in FORMAT 4 are found installed and are eligible under A TUFS	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	b. If not please specify		
9	a. Whether MIC code allotted by the TxC is found on all machines indicated in FORMAT 4	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	b. If not please specify		
10.	Total cost of eligible benchmarked machinery under ATUFS Promoter's Contribution Loan Disbursed	Rs._____ Rs._____ (____ %) Rs._____ (____ %)	
	Machines installed/commissioned under ATUFS (Machine details to be furnished as per given Appendix)	15%/10%	
	Whether JIT recommends for release of subsidy	Yes/No	
	If yes, then eligible investment	Rs._____	
	If No, reason thereof		
11.	Eligible subsidy amount (CIS)	Rs. _____	
12.	Employment		

Signature of the Owner/

Authorized Person of the Unit with seal

(JIT Members Name & Designation and signatures)

Appendix to FORMAT-6

Certification on Installation and Commissioning of Machinery under ATUFS

MACHINE WISE PARTICULARS & DETAILS

Machine Type		
Machine reference sr. no as per ATUFS Annexure		
Imported or Indigenous		
Number of Machines		
Name & Address of the machinery Manufacturer		
Date of commissioning of the machine(s)		
Make		
Model		
Year of Manufacture Machine sr. no		
Specification of the Machine		
Country of Origin (in case of Imported)		
Exporting Country (in case of Imported)		
Commercial Invoice No. & Date and Price of Machinery (Copies enclosed)		
Bill of Lading Number & Date (Copies enclosed)		
Bill of Entry Number & Date (Copies enclosed)		
Online Verification of Bill of Entry in E commerce portal (icegate)		
Details of Payment made (Copies enclosed) Mode of Payment (LC/SWIFT/TT/CAD/RTGS/NEFT CHEQUE/DD/PO etc) Amount & Date of payment		
Attach photographs duly signed & stamped by JIT and applicant displaying the installed machinery claimed under the project.		
Whether the machine(s) is/are installed/commissioned as per the specifications mentioned in the commercial invoice	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Remarks of JIT if any		

(JIT Members Name & Designation and signatures)

(Sign of company/firm)

FORMAT-7
FORMAT FOR PROCESSING CLAIMS

Date of Receipt of Unit's Application in O/o.Tx.C:

UID No. and Date allotted by O/o.Tx.C:

Date of Inspection by JIT:

1	Name & Address of the unit inspected with pin code Taluka/Tahasil/Mandal: District: State: Pincode:		
	Phone No./Mobile No.		
	Fax No.		
	E-Mail ID		
	Unit PAN No.		
	SSI Reg./EM No. & Date		
	Name of Contact Person Contact No.:		
2	Date of physical verification by JIT	____ / ____ / ____ (dd / mm / yyyy)	
3	Date of uploading of JIT report in the online system.	____ / ____ / ____ (dd / mm / yyyy)	
4	a) Whether all other details submitted by the unit and certified by the bank are found correct or not by JIT	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	b) If not please specify		
	c) Whether the deviation resolved/justified.	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
5	a. Whether all machines indicated in FORMAT 4 are found installed and declared eligible under A TUFS by JIT	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	b. If not please specify		
6	a. Whether MIC code allotted by the TxC is found on all machines indicated in FORMAT 4 by JIT	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	b. If not please specify		
7	Total cost of machinery found eligible under ATUFS as per JIT. Amount of subsidy to be released @ 15% or 10%	Rs.	
		Rs.	
8	Technical Officer Assistant Director Deputy Director Director JTxC/ATxC TxC		

FORMAT-8
FORMAT FOR RELEASING CLAIMS

Date of approval of Textile Commissioner (competent authority)	
Date of submission of Challan to MoT	
Date of approval of JS/AS (TUFS)—MoT	
Date of Approval of IFW-MoT	
Date of approval of competent authority	
Date of sending bills to PAO (Textiles)	
Date of credit into the beneficiary account/Bank	

FORMAT-9
Part I (To be submitted by beneficiary)

CANCELLATION OF ISSUED UID UNDER ATUFS THROUGH CONCERNED LENDING AGENCY

1.	UID Number	Auto generated
2.	UID Approval date	Auto generated
3.	Name of the unit	Auto generated
4.	Address of the unit	Auto generated
5.	e-mail ID of the unit	Auto generated
6.	PAN number	Auto generated
7.	Date of sanction of term loan	Auto generated
8.	Project cost in Rs.	Auto generated
9.	Segment claimed	Auto generated
10.	Lending Agency name	Auto generated
11.	Lending Agency address	Auto generated
12.	Lending Agency Branch Code	Auto generated
13.	Term loan Sanctioned in Rs.	Auto generated
14.	Promoter's Contribution in Rs.	Auto generated
15.	Term Loan account number	Auto generated
16.	Total Subsidy value pre authorized as per UID in Rs.	Auto generated
17.	Reason for Cancellation of issued UID	

Certified that:

The information furnished in this format is true & correct and I/We ----- request the cancellation of the aforesaid UID issued by Office of the Textile Commissioner. Further I/We ----- shall not claim any subsidy full or in part thereof with respect to the aforesaid UID issued by Office of the Textile Commissioner, at any time.

Place:

(Signature)

Date :

(Name and designation of the authorised signatory)

Note : Please affix seal/rubber stamp of the Company/Unit along with signature of the authorized signatory.

FORMAT-9 (Continued)

Part II (To be submitted by Lending Agency)

CANCELLATION OF ISSUED UID UNDER ATUFS THROUGH CONCERNED LENDING AGENCY

Certified that:

The information furnished in by the applicant in PART—I of FORMAT - 8 is found correct on the basis of records available with our bank.

In view of reasons submitted by the applicant unit in the Part I of Format 8, I/We ----- hereby recommend for the Cancellation of UID number issued by Office of the Textile Commissioner to the applicant unit.

Place:

Signature)

Date :

(Name and designation of the authorised signatory with seal)

FORMAT - 10

FORMAT FOR ONLINE GRIEVANCE RELATED TO IMPLEMENTATION OF ATUFS

i.	Grievance No (Auto generated)	
ii.	Grievance date (Auto generated)	
iii.	Name of the applicant unit	
iv.	Address of the applicant unit	
v.	Tel. No	
vi.	Fax No	
vii.	E-mail ID	
viii.	Name of the contact officer	
ix.	Designation of the contact officer	
x.	Mobile No.	
xi.	Fax No.	
xii.	E-mail ID	
xiii.	Name of the lending Agency	
xiv.	Address of the lending Agency	
xv.	UID Number	
xvi.	Date of issue of UID	
xvii.	Term loan Amount	
xviii.	Segment	
xix.	Details of Grievance related to implementation of A-TUFS	
xx.	Additional details, if any	
xxi.	Copies of supporting documents	Please upload a scanned copy

Place:

Date :

(Name and designation of the authorised signatory)

FORMAT - 11

FORMAT FOR ONLINE GREVIENCE RELATED TO POLICY MATTERS AND INTERPRETATION THEREOF
UNDER ATUFS

i.	Grievance No (Auto generated)	
ii.	Grievance date (Auto generated)	
iii.	Name of the applicant unit	
iv.	Address of the applicant unit	
v.	Tel. No	
vi.	Fax No	
vii.	E-mail ID	
viii.	Name of the contact officer	
ix.	Designation of the contact officer	
x.	Mobile No.	
xi.	Fax No.	
xii.	E-mail ID	
xiii.	Name of the lending Agency	
xiv.	Address of the lending Agency	
xv.	UID Number	
xvi.	Date of issue of UID	
xvii.	Term loan Amount	
xviii.	Segment	
xix.	Details of Grievance related to Policy matters and interpretation thereof under ATUFS	
xx.	Additional details, if any	
xxi.	Copies of supporting documents	Please upload a scanned copy

Place:

Date :

(Name and designation of the authorised signatory)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 24th November 2015

RESOLUTION

F.No-8-1/2015-Skt.II—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 27.08.2015 reconstituting the Rashtriya Sanskrit Parishad by the Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Higher Education, Govt. of India, it has been decided with the approval of Chairperson of the Parishad & Hon'ble Minister of Human Resource Development, to amend the composition of the Parishad to co-opt Chancellor, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati under the category of Ex-officio members. It has also been decided that Chairperson of the Parishad may invite any other Sanskrit Scholar in the meetings of the Parishad as Special Invitees.

2. Accordingly, Shri N. Gopalaswami, Chancellor, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati has been co-opted as Ex-officio member and Shri Chamu Krishna Shastry, Sr. Consultant (Languages), MHRD has been nominated in Rashtriya Sanskrit Parishad as Special Invitee.

3. This order will come into force with immediate effect.

SUKHBIR SINGH SANDHU
Joint Secy.

New Delhi, the 22nd February 2016

RESOLUTION

No. F.4-3/2015-U.3—Whereas the Council of Indian Council of Philosophical Research (ICPR) was last constituted on 15th October 2012 and the term of the Council having expired on 14th October 2015, the Government of India has resolved to re-constitute the Indian Council of Philosophical Research (ICPR) under Rule 3 of the Memorandum of Association and Rules of the ICPR. The tenure of members is for a period of three years from the date of issue of resolution except for Chairman and Member Secretary in whose case the tenure is mentioned below. The Council with following members is constituted with immediate effect:-

- A. Chairman - Prof. S.R. Bhatt (For three years from assumption of the charge on 20th October 2015)
- B. Eight representatives of different organisations:-
 - i. A representative of the University Grants Commission;
 - ii. Two representatives of the Indian Philosophical Congress;
 - iii. A representative of the Indian Council of Social Science Research;
 - iv. A representative of the Indian Council of Historical Research;
 - v. A representative of the Nation Science Academy;
 - vi. A representative of the Deptt. of Higher Education, Ministry of Human Resource Development.
 - vii. Financial Advisor, Deptt. of Higher Education, Ministry of Human Resource Development.
- C. Twelve members nominated by the Government of India:
 - i. Prof. Kusum Jain, Former Professor & Head Department of Philosophy, Rajasthan University
 - ii. Prof. Jatashankar Tiwari, Former Professor & Head Department of Philosophy, Allahabad University.
 - iii. Prof. X.P. Mao, Professor of Philosophy, North Eastern Hill University
 - iv. Dr. K. Arvinda Rao, Director Advaita Academy, Hyderabad
 - v. Prof. S.R. Leela, Former Professor & Head Department of Sanskrit, Bangalore University
 - vi. Prof. V. Kutumba Sastri, Former Vice-Chancellor, Somnath Sanskrit University
 - vii. Prof. R.C. Sinha, Former Professor & Head Department of Philosophy, Patna University.
 - viii. Prof. Dharmanand Sharma, Former Professor & Head Department of Philosophy, Chandigarh University
 - ix. Prof. Naresh Kumar Ambastha, HOD, Department of Philosophy, PKRM College, Dhanbad.
 - x. Prof. Hare Ram Tripathi, Professor, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha (Deemed University), Delhi.
 - xi. Prof. Om Prakash Pandey, Former Head of the Dept. of Sanskrit and Prakrit Languages, Lucknow University
 - xii. Dr. Rajaram Shukla, Professor Vaidic Darshan, BHU Varanasi.
- D. Four imminent philosophers to be co-opted by Council.
- E. Two representatives of Government of Uttar Pradesh; and
- F. Prof. Manendra Pratap Singh, Member Secretary, ICPR. (He was appointed as Member Secretary of the ICPR for a period of three years w.e.f. 18.11.2013).

ORDER

It is hereby ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRAVEEN KUMAR
Jt. Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in